हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 मार्च, 1979

खण्ड 1, अंक 16

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 26 मार्च 1979

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(16) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(16) 23
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(16) 31
आबकारी तथा कराधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य–	
(1) बाद ाहपुर और उमरी (कुरुक्षेत्र) में भाराब के ठेकों की नीलामी सम्बन्धी	(16) 32
(2) जिला करनाल में भाराब के नए ठेकों की नीलामी सम्बन्धी	(16) 33
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग – ग्रहण की गई ध्यानाकर्शण सूचना को वापस लेने सम्बंधी	(16) 35

वर्श 1979–80 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(16) 36
बैठक का समय बढ़ाना	(16) 68
वर्श 1979–80 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(16) 69
बैठक का समय बढ़ाना	(16) 96
वर्श 1979–80 के बजट के अनुदानों के मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(16) 96
परि ाश्ट	(16) 96 (1)

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 26 मार्च 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधानसभा हाल, विधान भवन, सैक्टर –1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होंगे।

Shops Purchased in open auction in New Anaj Mandi Hissar.

***1182. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister of Agriculture be pleased to state-

(a) whether it is a fact that some shops, out of those purchased by the people in open auction if New Anaj Mandi, Hissar, were given to some other persons instead of the real bidders during the Emergency period; and

(b) if so, whether any shops have been given to those persons in lieu of the shops purchased by them in the said open auction, if not, the reasons therefor ?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां। हिसार में नई मण्डी के विस्तार हेतु पुरानी मण्डी के व्यापारियों को स्थान देने के लिये रिवाईजड ले आउट प्लान तैयार किया गया था। दस व्यक्तियों को इसलिये भााप कम फ्लैटस/बूथस नहीं दिये ाज सके जिन प्लाटों को उन्होंने पहले बोली में खरीदा थां

(ख) जी हां। सभी दस व्यक्तियों को भााम कम फ्लैटस/बूथस बनाने के लिये बोली में खरीदे गये प्लाटों के बदल और प्लाटस दिये गये थे।

लाला बलवन्त राय तायलः मन्त्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि जिन दस आदमियों मे प्लाटस अमरजैंसी में छीने गये थे उनको बदले में प्लाटस दे दिये गये हैं परन्तु मैं यह कहता हूं कि उनको प्लाटस नहीं दिये गये हैं। ये असैम्बलीमें गलत जवाब दे रहे हैं उनसे अमरजैंसी के टाईम पर प्लाटस छीन लिए गये और किसी दूसरे को प्लाट अलाट कर दिये गये, क्या इस बारे में मंत्री जी इन्क्वायरी करायेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि किसार में पुरानी अनाज मंडी थी उसकी बजाये नई मंडी बनाने के लिए कालोनाइजे ान डिपार्टमैंट ने जमीन इंक्वायर करके आज से तकरीबन 15 साल पहले प्लाट बेचे थे लेकिन वहां पर जो पुरानी

मंडी में लोग बैठे थे उन्होंने वहां पर दुकानें प्रचेज नहीं की। उन्होंने इसलिए नहीं की कि पता नहीं नई मंडी चलेगी या नहीं परन्तु ज्यादा अनाज पैदा होने के कारण मजबूर हो कर सरकार को फैसला करना पडा कि सभी दुकानदारों को नई मंडी में जाना पडेगा। जो अनाज का काम करते हैं, उनको नई मंडी में जाने के लिए दुकानें नहीं थी क्योंकि उन्होनें उस समय दुकानें नहीं ली थीं इसलिए सरकार ने अपना लेआउट बदल कर 103 के करीब दुकानों के प्लाट और काटे और जो लोग पुरानी मंडी में रहते थे उन सबको प्लाट अलाट किये गये लेकिन दस दुकानें ऐसी थीं जो कि कालोनाइजे ान डिपार्टमैंट ने बेच रखी थीं जिन्होंने बोली में ले रखी थी लेकिन अब उनको उसके बदले में दूसरी दुकानें दी गई हैं। 103 दुकानों में ये दस आदभी भी एडजैस्ट हो गये हैं जिन्होंने कालोनाइजे ान महकमे से दुकानें नीलामी में खरीदी थीं।

लाला बलवन्त राय तायलः क्या यह सच है कि आनन्द प्रका ा जिसकी दुकान ली गई थी वही दुकान बडी करके किसी और दुकानदार को दी गई ?

चौधरी भजन लालः यह बात ठीक है लेकिन जब नये सिरे से स्कीम बनाई गई तो उनको वही कोरनर की दुकान दी गई है। वे मुझे भी मिले थे। पहले उन्होंने वह दुकान 32 हजार 100 रुपये में ली थी लेकिन अमरजैंसी में औरों को 25 हजार 923 रुपये की दी गई। वे कहते हैं कि मेरे से कीमत फालतू क्यों ली

गई है ? सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्योंकि दूसरों से 10प्रति ात फालतू कीमत ही ली गई है तो इनसे भी उतनी ही ले ली जाए।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि तायल साहब ने कहा है कि दस आदयिमों के प्लाटस अमरजैंसी के टाईम पर ले लिए थे, क्या अब उन दस आदमियों को बाद में सैटल कर दिया गया है ?

चौधरी भजन लालः सबको प्लाट अलाट कर दिये गये हैं। सिर्फ दो आदमियों को एतराज है कि उनकी साइड चेंज को गई है। बाकी किसी को कोई ऐतराज नहीं हैं

चौधरी लाल सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायों कि अगर किसी फार्मर की मंडी बनाने के लिए जमीन इक्वायर की जाती है और उस फार्मर के पास थोडी जमीन हो तो क्या वह जमीन छोड दी जायेगी ?

श्री अध्यक्षः यह तो बडा हाइपोथैटिकल सवाल है।

चौधरी खुर ाीद अहमदः स्पीकर साहब, हिसार में तो दुकानदारों को भाप्स कम फ्लैटस की जगह नहीं मिली तो न सही लेकिन जिन एम0एल0एज0 से फ्लैटस खाली करवाये जा रहे हैं क्या उनको बदले में मकान मिलेगा ? (हंसी)

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, हिसार में जो दुकानदारों के लिए प्लाटस दिये गये थे उनके अलावा बाद में एमरजैंसी के टाईम पर जो पार्क छोडा गया था उसके प्लाट काटकर क्यों बेचे गये तथा इसका क्या कारण था ?

श्री अध्यक्षः एमरजैंसी के बाद जो सरकार ने फैसला किया है उसके बारे में मंत्री जी से पूछना उचित नहीं हैं

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जमींदारों के गड्डों के लिए और पार्क के लिए जो जमीन छोडी गई थी उसके प्लाट काट कर क्यों बेचे गये ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पहले इस जगह पर दुकानें नहीं बननी थीं लेकिन बाद में एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड ने इसको एक्वायर करके दुकानें अलाट की है। उसका कारण यह था कि पैदावार इतनी ज्यादा बढ गई थी कि पुरानी मण्डी में जो लोग बचे थे, उनको भी इस जगह पर प्लाटस काट कर देने पडे।

चौधर संत कंवर : स्पीकर साहब, हिसार मंडी में जो दुकानें नीलाम की गई थी, उनमें वहां के आढतियों की मोनोपली हैं। क्या मिनिस्टर साहब उस मोनोपली को तोडने के लिए किसानों के लिए और हरिजनों के लिए नई मंडियों में 1/5 रिजर्वे ान करने पर विचार कर रहे हैं ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, जब दुकानें नीलाम होती हैं तो रिजर्वे ान का प्र न ही पैदा नहीं होता। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि नई मंडियों के प्लाटस की जहां पर भी नीलामी हुई है देहाती भाइयों ने भी लिए हैं। खासकर हिसार में 25 परसैंट देहाती भाईयों और किसान भाईयों ने दुकानें खरीदी हैं।

श्री फतेह चन्द विजः मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा अभी चौधरी खुर ाीद अहमद जी ने सवाल पूछा था कि मुझे एम0एल0ए0 फ्लैट से तो नहीं निकाला जायेगा, कि क्या वे अभी ओथ लेने वाले हैं (हंसी)

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): आपके जोर देने पर यह फैसला किया गया है कि मिनिस्टर साहब एम0एल0ए0 फ्लैट में और छोटी कोठियों में जायें लेकिन यह फैसला करते समय मिनिस्टर और एम0एल0ए0 में कोई फर्क नहीं होगा, अगर किसी एम0एल0ए0 के बच्चे मुस्तकिल तौर पर रहते हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा और उसी कैटेगरी में खुर ाीद जी भी आते हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि हरिजनों और ग्रामीण लोगों के लिए प्लाटस की रिजर्वे ान नहीं है। अब सरकार देहातों में उद्योगीकरण करने जा रही है। क्या मंडियों की तरह से उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए या

उनमें बनाया गया माल बेचने के लिए दुकानें दी जायेंगी और इस किस्म के प्लाटस नये जवानों को जो ऐसी दुकानें बनाना चाहें, उनका अलाट किये जायेंगे ?

श्री अध्यक्षः यह पालिसी मैटर है। इस पर्टिकुलर सवाल से सम्बधित नहीं है। अगर आप मिनिस्टर साहब को नोटिस देंगे तो वे जवाब दे देंगे।

लाला बलवन्त राय तायलः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन दस आदमियों के प्लाटस का झगडा है उनको कब तक अलाट कर दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्षः मंत्री जी ने अ योरेंस दी है कि प्लाटस दिये जा चुके हैं।

चौधरी भजन लालः पलाट न देने का तो कोई झगडा ही नहीं है। प्लाट दिये जा चुके हैं दो आदमियों की ि ाकायत है। वह कहते हैं कि मुझे से आपने 32 हजार 100 रुपये क्यों लिए जबकि औरों से कम लिए हैं। आनन्द प्रका ा जी ने यह दुकान कालोनाइजे ान डिपार्टमैंट से प्रचेज की थी और बाद में एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से नीलाम की गई, उन्होंने इन्ही दुकानों की 25 हजार 223 रुपये कीमत रखी। वह कहता है कि मेरे सात हजार रुपये वापिस दिलाये जायें। पहले यह फैसला हुआ था कि जो कारनर की दुकान लेगा उसको दस परसैंट ज्यादा

देने पडेंगे। उसके दस परसैंट से ज्यादा लिए हुए पैसों का झगडा जेरे गौर है कि यह पैसा उसे वापिस देना है या नहीं।

श्री अध्यक्ष: मेरी समझ में तो गवर्नमैंट का जवाब यही आया है कि दस आदमियों को नई अनाज मंडी में प्लाट्स मिल चुके हैं। कोई प्राइस वगैरह का झगडा है उसके लिए लीगल प्रोसिजर सबके लिए खुला है और सरकार इस पर गौर भी कर रही है।

Disparity in the Pay-Scales, of the Employees of

Haryana Public Service Commission

***1147. Rao Ram Narain:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Haryana Government vide communication No., 1183-I-G.S.-I-74/6259 dated 22nd March, 1978 categorically committed to the Central Government that there was no disparity in the pay-scale of the various categories of the employees of Haryana Civil Secretariat and the Haryana Public Service Commission;

(b) whether it is also a fact that there is still disparity between the pay scales of the various categories of the officials of the Haryana Civil Secretariat and those of the Haryana Public Service Commission; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether there is any proposal under consideration of the Government to bring the pay scales to bring the pay scales of the employees of the aforesaid Commission at par with those of the Haryana Civil Secretariat; if not, the reasons therefor ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): राज्य सरकार ने भारत सरकार को हरियाणा सिविल सैक्रेटेरियेट और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी ान के मुलाजिमों की तनख्वाह/पे स्केल्ज के बारे में महज जो उस वक्त की असली पोजी ानी थी उसको सामने रखकर 22–3–1974 को इतलाह की थी। उस वक्त यह ख्याल नहीं था कि यह मुस्तकिल रहेगी या नहीं। उस वक्त डिसपैरिटी नहीं थी। इस वक्त डिसपैरिटी है। सरकार ने अब एक पे कमी ान मुकर्रर कर दिया है और वह तनख्वाहों/पे स्केल्ज के बारे में फैसला करेगा।

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, यह जो पे कमी ान बनाया गया है यह तो पे रिवाइज करने के लिये बनाया गया है। मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्तलिफ पे स्केल्ज में जो डिसपैरिटी है, क्या यह पे कमी ान इसको भी कंसीडर करेगा ?

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, पे कमी ान के सामने इस तरह के सारे मसले होंगे। कमी ान के सामने

मुखतलिफ ग्रेडज भी होंगे जिनको वह देखेगा और दूसरी सारी बातें भी वह देखेगा।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि 22–3–1974 को केन्द्रीय सरकार को एक खत भेजा था और उस वक्त डिसपैरिटी नहीं थी और आज यह डिसपैरिटी है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चार वर्श में डिसपैरिटी पैदा होने के क्या कारण है ?

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, उसके कारण कुछ होंगे लेकिन इस बात पर गौर करने के बाद कि कुछ डिसपैरिटी है और हरियाणा पब्लिक सविर्स कमी ान का दफ्तर चूंकि हरियाणा सिविल सैक्रेटेरियट के बराबार यानी कि क्लास 'ए' था, चेयरमैन की जो कांफ्रैंस 26–27 नवम्बर 1971 को हुई उसके फैसले के मुताबिक 1974 में एक लैटर द्वारा इतलाह दे दी गई थी। उसके बाद पता लगा कि डिसपैरिटी है तो उस पर दोबारा गौर किया गया और यह सारा मामला पे कमी ान के सामने रखा जाएगा।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, पब्लिक सर्विस कमी ान का साल का खर्चा आठ लाख के करीब है और एस0एस0एस0 बोर्ड का साल का खर्चा दस लाख के करीब है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करैंगे कि क्या सरकार का

दोनों को मर्ज करने का कोई विचार है जिससे कि खर्च में कमी हो सके ?

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, अगर इसके बारे में अलग से नोटिस दिया जाएगा तो बता दिया जाएगा।

Red Cross Fairs in the State

***1185. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the names of places togetherwith the period for which the permission was granted for holding the Red Cross fairs during the period from 1st April, 1977 to 31st March, 1978 and 1st April 1978 to 31st December 1978 in the State;

(b) whether it has come to the notice of the Government that gambling is the main object of these fairs and it is indulged there at a large scale; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to check it in future ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) अपेक्षित सूचना विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत की जाती है (अनुबंध 1)

(ख) नहीं।

(ग) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

अनुबन्ध –1

1–4–1977 से 31–3–1978	1–4–1978 से 31–12–1978

स्थान	जिस अवधि के लिये अनुमति दी गई	स्थान	जिस अवधि के लिये अनुमति दी गई
सोनीपत	14—3—77 से 31—5—77	गोहाना	11—11—78 से 21—12—78
सोनपीत	24—3—78 से 22—5—78	गन्नौर	13—11—78 से 21—12—78
भिवानी	10—2—78 से 10—4—78	तो ाम	20—12—78 से 28—1—79
कैथल	6—5—77 से 17—5—77	लोहारू	3—12—78 से 11—1—179
टोहाना	27—3—77 से 24—7—77	दादरी	19—10—78 से 27—12—78
हांसी	22—12—77 से 16—11—77	फतेहाबाद	4—12—78 से 1—1—79
हांसी	22—12—77 से 1—1—78	हिसार	11—5—78 से 26—6—78
पानीपत	23—2—77 से	बरवाला	2—9—78 से

	13–4–77		1–11–78
रेवाड़ी	19–9–77 से 17–10–77	बरवाला	19–10–78 से 1–11–78
फरीदाबाद	15–5–77 से 23–6–77	पानीपत	15–6–78 से 24–7–78
गुडगांवा	26–8–77 से 4–10–77	करनाल	1–6–78 से 10–7–78
सिरसा	16–3–77 से 4–6–77	रेवाडी	2–8–78 से 12–9–78
डबवाली	20–6–77 से 2–7–77	महेन्द्रगढ़	9–10–78 से 12–9–78
जींद	20–6–77 से 2–7–77	नारनौल	10–11–78 से 17–12–78
अम्बाला	15–5–77 से 30–6–77	गुडगांवा	23–4–78 से 6–6–78
यमुनानगर	16–5–77 से 30–6–77	सिरसा	26–5–78 से 14–7–78
जगाधारी	1–7–77 से	एलानाबाद	7–6–78 से

	31—8—77		26—6—78
अम्बाला कैंट	7—7—77 से 28—8—77	कालियांवाली	14—12—78 से 12—1—78
कालका	15—5—77 से 6—5—77	जुलाना	11—8—78 से 31—8—78
		नरवाना	29—5—78 से 30—7—78
		अम्बाला	12—7—78 से 25—8—78
		कालका	25—9—78 से 30—10—78
		अम्बाला कैंट	22—10—78 से 20—12—78
		यमुनानगर	20—10—78 से 10—1—78
		नारायणगढ़	21—10—78 से 30—12—78

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, जवाब में बताया गया है कि एक एक, डेढ डेढ महीने तक मेला लगाने की इजाजत दी गई है और पचास पचास और साठ साठ हजार का यह ठेका दिया जाता है। वहां पर न कोई नुमाई ा होती है और न ही रिक्रिए ान की कोई बात होती है। वहां पर केवल जुआ खेला जाता है और उसको हम केवल जुआखाना कह सकते हैं। क्या मंत्री महोदय ऐसी इंस्ट्रक ांज जारी करने की कृपा करेंगे कि वहां पर (रैड क्रास के मेले में) जुआ खेलने की इजाजत न दी जाए ?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, विज साहब भाायद गैम्ज आफ स्किल यानी कि चतुराई के खेल को भी जुआ समझते हैं। जो स्किल गैम्ज हैं, वे पंजाब गैम्बलिंग एक्ट के सैक ान 13 के तहत आफैंस नहीं बनते। गैम्बलिंग जिसका आधार हार और जीत है वह कम्पलीट बैन है और 17–12–1979 को इंस्ट्रकं ाज जारी की हुई हैं कि रैड क्रास मेलों में इस किस्म की कोई बात नहीं दोहराई जाए।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब जिसको चतुराई का खेल बता रहे हैं उसमें यह होता है कि एक आदमी ने कोई चीज लगाई होती है और उसी चीज के ऊपर कुछ ऊपर चीज लगी होती हैं और कुछ नीचे लगी होती हैं। एक आदमी खड़ा होकर भाौट मारता है अगर उस चीज को भाोट लग जाता है तो वह जीत जाता है और अगर नहीं लगता तो हार जाता है .....

श्री अध्यक्षः आप सीधा सवाल पूछिए। आप तो चतुराई के खेल का डिस्क्रिप ान दे रहे हैं।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चतुराई के गेम का मतलब क्या है ?

श्री अध्यक्षः मतलब तो आपने खुद समझा दिया हैं

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, किसी एक कैटेगरी के साथ अगर दो कैटेगरी नीचे और ऊपर और लगा दें तो वह गैम्बलिंग है और उसको बंद करना चाहिएं

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब ने कहा है कि गेम्ज आफ स्किल पंजाब गैम्बलिंग एक्ट में स्पेसिफाइड हैं और वह औफेंस नहीं बनता। They are accepted as games of skill.

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, हमें तो पता नहीं कि वहां पर क्या लगता है और कौन लगाता है और न ही हमने वहां पर कोई ऐसी चीज देखी हैं लेकिन यह सच है कि गैम्बलिंग कहीं भी अलाउड नहीं है। अगर कोई बात माननीय सदस्य के नोटिस में है तो वह बताएं। इसके लिए पंजाब गैम्बलिंग एक्टा का सैक ान 13 पढना चाहिए।

श्रीमती भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, यह बात सच है कि जिसको मिनिस्टर साहब चतुराई का खेल कह रहे हैं वह निरा जुआ है। इस खेल के लिए कितने ही नौजवानों ने घरों में दिन

और रात चोरी की हैं, ताले तोडे हैं। मेरे पास इसके तथ्य हैं और बार बार स्टेटमैंट देने के बावजूद मिनिस्टर साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई केस उनके नोटिस में लाया जाए तो ऐक ान लेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, अगर मेरी बहन एक भी केस नोटिस में लाएंगी तो फौरन ऐक ान लिया जाएगा।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, गृह मंत्री महोदय ने गेम्ज आफ स्किल का जिक्र किया है। यह बात सच है कि रैड क्रास के मेले में अगर बीस दुकानें खोली जाती हैं तो भाायद मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात नहीं है कि उन दुकानों में एक दुकान ऐसी भी होती है जहां फ्लैस खेला जाता है और जिसकी चतुराई का गेम नहीं कहा जा सकता है। यह सरासर चांस पर निर्भर करता है जो कि जुआ है। क्या मंत्री महोदय फ्लै ा का स्टाल न लगाने का आदे ा दें गे ?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, फ्लै ा तो कोई ता ा का खेल होता है और वह क्लबों में खेला जाता है। मेले में वह खेल नहीं खेला जाता है। जैसा मैंने पहले कहा है कि गैम्बलिंग किसी भी रूप में अलाउड नहीं है और यदि कोई केस किसी मैम्बर के नोटिस में है तो वह मेरे नोटिस में लाएं और इस बारेम में स्ट्रिक्ट ऐक ान लिया जाएगा।

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, यह जो रैड क्रास के मेल लगाये जाते हैं यह एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई का बच्चों पर बुरा असर पडत है। इन मेलों में डांस वगैरह भी दिखाये जाते हैं और भी कई किस्म के काम होते हैं। क्या मंत्री महोदय ऐसी आईटम्ज को बंद करवाने का विचार रखते हैं ताकि हमारे समाज पर इन का बुरा असर न पडे ?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब दिया जा चुका है कि पंजाब गैम्बलिंग एक्ट की सैक ान 13 के अन्र्गत गेम्ज आफ स्किल खेली जाएंगी और दूसरी कोई गैम्ज जैसा कि गैमबलिंग, डांस और फ्लै ा वगैरह नहीं खेली जाएगी।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन रैड क्रास के मेलों में सरकार को अब तक कितनी आमदनी हुई है ?

श्री वीरेन्द्र सिहः आनरेबल मैम्बर इसके लिये अलग से नोटिस देंगे तो उनको बता दिया जाएगा। इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं हैं

श्री अध्यक्षः भले राम जी, इसके लिए आप अलग से नोटिस दीजियें

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, यह जो रैड क्रास के मेले हैं, इनमें बहुत ही गंदे और सेमी नेक्ड डांस होते हैं, क्या

मंत्री महोदय इन मेलों में ऐसी आईटम्ज को बंद करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, सेमी नेक्ड डांस जैसा कि मेरे भाई श्री भाम ोर सिंह जी बता रहे हैं हमने तो आज तक हरियाणा में देखे नहीं हैं। अगर कोई ऐसी बात है भी तो इसके लियसे मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि सरकार के दोबारा इस तरह की इंस्ट्रक ांज दे दी हैं कि अगर इस किस्म के नाच वगैरह, जो कि एक सभ्य सोयायटी के लिये भाोभा नहीं देते, गैम्बलिंग या जो चांस की गेह हो, ऐसी गेमें वहां न खेली जाएं।

श्री अध्यक्षः मैं आनरेबल मैम्बर्ज से यह कहूंगा कि आजकल फ्लै ा के कैमरे होते हैं। मैम्बर साहेबान अगर मौके पर फोटो खींच कर प्रोडयूस कर देंगे तो मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब अव य उस पर ऐक ाचन लेंगे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने गेम्ज आफ स्किल का जिक्र किया। मैं मंत्री महोदय से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि वे गुप्त तौर पर इन रैडक्रास के मेलों को दौरा करें तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वहां पर गरीब आदमियों को लूटा जा रहा है। अगर माननीय मिनिस्टर साहब के नोटिस में कोई ऐसी बात लाई जाएगी कि किस तरीके से वहां पर गरीब आदमियों को लूटा जा रहा है। अगर माननीय

मिनिस्टर साहब के नोटिस में कोई ऐसी बात लाई जाएगी तो क्या वे इस बुराई को बंद करवाने का आ वासन देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर साहब ने जो यह बात कही इसका कोई बेस नहीं है।, कोई सिर पैर नहीं हैं अगर वे कोई इसका खास इंस्टान्स बताएंगे तो अव य ऐक ान लिया जाएगा।

चौधरी गंगा रामः .....

Shrimati Sushma Swaraj: I take strong exception to it.

श्री अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि जो सप्लीमैंटरी पूछी जाए वह सवाल से सम्बन्धित ही पूछा जाए। इस तरह से सवाल पूछना यह सारे हाउस को भाोभा नहीं देता है। It should not be brought on record and should be expunged.

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, रैडक्रास के जो मेले लगते हैं उन पर सरकार की तरफ से फीस निर्धारित की हुई होती है। 20 या 50 पैसे के लगभग फीस टिकट के रूप में ली जाती है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन मेलों के अंदर जाने के बाद जो डांस और दूसरे जो काम होते हैं उनके लियें अलग से टिकट ली जाती है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर साहब की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि इन मेलों से जो आमदनी होती है वह रैडक्रास परपज के लिये होती है और जब कहीं स्टेट के ऊपर नेचुरल क्लैमिटी आ जाए तो फिर यह पैसा वहां पर खर्च किया जाता है। लक्की बैगज टिकट का तो मुझे ज्ञान नहीं है कि वहां पर बेचे जाते हैं या नहीं और न ही इस बात का मुझ ज्ञान है कि बाहर और अंदर अलग अलग टिकट लिये जाते हैं या कि नहीं। वैसे मांगेराम जी मेलों में जाते रहते हैं इनको पता होगा।

Mr. Speaker: It appears to me that the House is greatly exercised over this question. I can only request the Government to examine the matter in greater detail.

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय गलत स्टेटमैंट दे रहे हैं। मेलों का इकट्ठा हुआ पैसा मेले में ही रहता है और कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता (ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, यह बिल्कुल ढोंग रचा रखा है। गरीबों को पैसा लूटा जा रहा है। मेरी सरकार से अपील है कि इस मेले के कामों को बिल्कुल बन्द किया जाएं इसका हमारे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड रहा है। मिनिस्टर साहब गलत बयानी कर रहे हैं कि यह पैसा, जब नेचुरल कलेमिटी आती है तो स्टेट के हित के लिये खर्च किया जाता है यह

बिल्कुल गलत है यह बडा इम्पोर्टैंट सवाल है और मिनिस्टर साहब इसको मखौल में ही ले रहे हैं यह कोई जवाब नहीं हैं (ाोर)

आवाजें: स्पीकर साहब, इन मेलों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए।

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इन मेलों के ठेके 20–20 हजार तक के दिये जाते हैं और ठेकेदार वहां से दो दो तीन तीन लाख रुपया कमा कर ले जाते हैं यह बिलकुल फैक्ट हैं .. (ाोर) इन मेलों को बिलकुल बंद कर देना चाहिएं (ाोर)

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन मेलों का काम पहली कांग्रेस सरकार ने चालू किया था या कि जनता सरकार ने किया है ? (ाोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हम वजीर साहब से यह जानना चाहते हैं कि ..... (ाोर)

श्री अध्यक्ष: आप जरा बैठिये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह बडा जरूरी प्र न है, और इस पर डिसक्सन के लिए आधे घंटे का समय रखा जाए। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: आप जरा भाांति से काम लिजिये। अगर आप मैम्बर साहेबान इसके लिए मुझे लिख कर नोटिस देंगे तो मैं

कांसेडर करूंगा और बिजनैस एडवाईजरी कमेटी के सामने यह सारा मामला रखूंगा ..... (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, मुझे समझ नहीं आती कि ये मैम्बर साहेबान इस बात पर बडे एजीटेटिड क्यों फील कर रहे हैं ? यह भी कहा जा रहा है कि फलां जगह नाच होते हैं, फलां जगह पर जुआ होता है। ऐसे ही भाोर मचाने से क्या फायदा है। When not even a single instance has been quoted by any of the members ऐसा करने से हमें कोई फर्क नहीं पडता है। (Interruptions).

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अगर हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पडता है तो फिर इनके कहने से क्या फर्क पडता है .... (ाोर) ..... It is happening every where. We want a definite reply from the Minister that the 'melas' will not be held. (Noise and Interruptions)

Mr. Speaker: Please listen to him patiently.

Shri Verender Singh: Mr. Speaker, there should be some concrete instances so that that Government may be able to take action. (Interruptions).

Mr. Speaker: Please listen to his reply.

Ch. Birender Singh: The Minister should behave properly and give a definite reply.

Mr. Speaker: You must give him time to have his say and listen to him patiently. (Interruptions). साहेबान आप इन राइटिंग मुझे दीजिये and I will consider ti. (ाोर)

Ch. Jagjit Singh Pohloo: Mr. Speaker, there should be discussion on this matter for half an hour.

श्री अध्यक्षः मैंने पहले भी कहा है कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं मुझे लिखित रूप में दें, फिर मैं इस पर गौर करूंगा (ाोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह जो बोले जो रहे हैं, यह आपका ढीलापन है। कांग्रेस सरकार ने पहले ही काम खराब कर रखे हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से यह रिक्वैसट करूंगा कि जब एक मंत्री महोदय हाउस के अंदर जवाब दे रहे हों तो आप उसको बडी भाांतिपूर्वक सुनने की भाक्ति रखें और ध्यान से सुनें। अगर उनकी किसी स्टेटमैंट पर या उनके किसी कहने पर आप सहमत न हों तो I have asked you to give me in writing. This is quistion hour and you can ask supplementaries relevant to the main question (ाोर) अगर आप हाफ एन आवर डिस्क ान चाहते हैं तो आप इन राईटिंग दे दें और उस पर विचार हो सकता है। लेकिन इस तरह से हाउस में बीच में डिसटरबैंस क्रिएट करना, हाउस के डेकोरम के खिलाफ है। अब मैं

आनरेबल मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे अपनी स्टेटमैंट दें।

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मैम्बर साहेबान कोई इंस्टांस कोट करें तो उस पर सख्त ऐक ान लिया जाएगा और रैडक्रास के मेले में गैम्बलिंग या कोई ऐसा नाच जिसे सभ्य सोसायटी में पसंद नहीं किया जाता है वह मुकम्मल तौर पर नहीं होने दिया जाएगा।

श्री फतेह चन्द विजः अभी मंत्री महोदय ने बताया कि उनके नोटिस में ऐसा इंस्टांस लाया जाये तो मैं बताना चाहता हूं कि पानीपत में आज कल ऐसा मेला चल रहा है और वहां पर गैम्बलिंग हो रही है तो क्या मंत्री महोदय कभी दिल्ली जाते वक्त या आते वक्त वहां पर सरपराइज विजिट करेंगे ?

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने भी नरवाना और जींद में कैबरे डांस होते देखें हैं ..... (ाोर)

Mr. Speaker: If you give it in writing. the Hon. Minister will take action on it.

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने गवर्नर साहब के एड्रैस पर बोलते हुए सारी तफसील दी थी

Mr. Speaker: This is question hour. You are not supposed to give a reply.

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं .... (ाोर) रैडक्रास के मेले .....

Mr. Speaker: You kindly give it in writing. I can not allow one hour to be speant on one question.

श्री मांगे राम गुप्ताः अगर रैड क्रास के मेले की फीस मुकर्रर कर दी जाती है . (ाोर)

Mr. Speaker: Please take your seat. This sort of way, I will not allow.

तारांकित प्र न संख्या 1167

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, राव दलीप सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Wax Quota

***904. Swami Aditya Vesh, Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Indusries be pleased to state-

(a) the constituency number of persons to whom the quota of Wax was allotted during the period from 4th July, 1977 to 30th September 1978 in the State;

(b) whether the Government intends to allot quota of Wax for the public of the rural area in the State; and

(c) if not, the reasons thereof ?

विकास मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(ए) मोम की बांट कन्सटीच्यूंसी के आधार पर नहीं की जाती। राज्य सरकार द्वारा नियमित पालिसी के आधार औद्योगिक इकाईयों को दी जाती हैं। 4 जुलाई 77 से 30 सितम्बर 78 तक जिन औद्योगिक इकाईयों को मोम की बांट दी गई थी उसकी जिलेवार संख्या निम्नलिखित है –

जिला	इकाईयां
अम्बाला	47
करनाल	18
कुरुक्षेत्र	4
सोनीपत	24
गुडगांवा	27
रोहतक	12
भिवानी	14
महेन्द्रगढ	12
जीन्द	32

सिरसा	11
हिसार	43

(बी) सरकार ने देहाती क्षेत्र में 139 इकाईयों को मोमबत्ती बनाने के लिये मोम पहले ही अलाट कर दिया हैं

(सी) प्र न ही नहीं उठतां

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, खास कर जनता सरकार आने के बाद हरियाणा में गरीब और अमीर में बहुत फर्क बढता जा रहा हैं अब भी बडे बडे कारखानेदारों को वैक्सए का कोटा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम देहात में छोटे उद्योग लगा रहे हैं तो क्या देहात में सरकार को कोटा का विचार है ?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, आपकी आज्ञा से सदन की जानकारी के लिये मैं इस संबंध में थोडा सा विस्तार से बताना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्तें को मोम के कोटे के बारेम में बहुत बहम है। जब भी कोई इंडस्टरी की मांग आती है तो मेरे विरोधी ग्रुप के भाइयों की तरफ से नारे लगते हैं इसलिये मैं इस संबंध में विस्तार से बताना चाहता हूं कि मोम के कोटे के बारे में पिछली सरकार की पालिसी क्या थी और अब जनता सरकार की क्या पालिसी है। मैं आपके सामने फिग्गर्ज रख देता हूं उससे मालूम हो जाएगा कि जितने भी कुकर्म किये हुए हैं यह पिछली सरकार के ही किये हुए हैं जनता सरकार आने के बाद हमारे मुख्य मंत्री

महोदय जी ने इस बारे में टोटली पालिसी ही उल्ट दी है। हमने बडे बडे कारखानेदारों के कोटे को घटा कर इस कोटे को रूरल इंस्स्टरीज को दिया है। जैसें मैंने जवाब में कहा है कि रूरल एरियाज में 139 यूनिटस को मोम का कोटा दिया जा चुका हैं 1976 में कांग्रेस सरकार थी। उस को जो कोटा दिया गया था वह इस प्रकार था रूरल एरियाज में कैंडल मेकिंग यूनिटस 6 को दिया गया था और अर्बन यूनिट 69 को दिया गया था। प्रोसैसिंग यूनिटस रूरल में एक को दिया गया था और अर्बन में 49 को दिया ग्रया था। यानी उन्होंने कुल मिला कर 50 प्रोसैसिंग यूनिटस को और 75 कैंडल मेकिंग यूनिट को कोटा दिया। लेकिन जनता सरकार ने 1978 में यह पालिसी रिवाइज करा दी। कांग्रेस सरकार के टाईम में जो कैंडल मेकिंगे यूनिटस रूरल एरिया में 6 थीं उनको बढा कर हमने 148 कर दिया है। अर्बन यूनिटस के बारे में भी बताऊंगा और जो इस संबंध में अंधेरा है वह दूर हो जाएगा। मोम के कोटे में अगर हेराफेरी हुई हे तो वह कांग्रेस सरकार के टाईम में हुई है। इसी तरह से रूरल एरिया में जहां 1976 में प्रासैसिंग यूनिट एक थी अब एक की बजाये 16 हो गई हैं और अर्बन एरिया में 72 हो गई हैं यानी टोटल प्रोसैसिंग यूनिटस अब 88 हो गई हैं। पिछली सरकार के टाईम में टोटल कोटे का 82.6 प्रति ात कोटा सिर्फ 12 यूनिटस को ही दिया जाता था और उस पालिसी को बदल कर हम इसे इस पोजी ान पर ले आए हैं। इसके अलावा इसका क्राइटेरिया यह भी है कि रूरल यूनिटस के सिवाये और जो भी कोटा दिया गया है वह उसको दिया गया है

जिनके पास नान बैकवर्ड एरिया में 31–12–75 को अपनी म ीनरी थी और उन्होंने रजिस्ट्रे ज्ञन बरवाई हुई थी। जो बैकवर्ड एरियाज हैं उसमें 31–12–76 को जिसके पास म ीनरी थी और रजिस्ट्रे ान करवाई हुई थी उनको कोटा दिया गया है। हमने केवल उन्हीं फर्मों को कोटा दिया है जो रजिस्ट्रर्ड हैं। इसलिये यह बात मन से निकाल दो कि जनता सरकार ने किसी के साथ पक्षपात किया है।

स्वामी आदित्यवे ा: मैं मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने विस्तार रूप सें सारी बातें रखी हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो सवाल पूछा था वह निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से पूछा था कि किस क्षेत्र में कितना कितना कोटा दिया गया लेकिन इन्होंने जिलावाइज बताया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गुडगांवा जिला में जो कोटा दिया गया है वह सारा एक हलके में ही दिया गया है या अलग अलग हलकों में ?

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी इसका जवाब आ चुका है। इन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि हल्कावाइज आंकडे इकट्ठे नहीं किये जाते।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया– मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि महेन्द्रगढ जिला में 12 यूनिटस को मोम का कोटा

दिया गया है क्या वे यह बतायेंगे कि इनमें से कितना भाहर में दिया गया है और कितना गांव में दिया गया है ?

श्री अध्यक्षः डिस्ट्रिक्ट वाईज तो बता दिया गया है।

ठाकुर बीर सिंहः इस सवाल में देहात में कितना कोटा दिया गया है, यह नहीं पूछा गया है बल्कि हलके वाईज पूछा गया है जबकि डिस्ट्रिक्ट वाईज बता दिया गया है।

श्री अध्यक्षः अगर आप इस सप्लीमैंटरी का जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए।

ठाकुर बीर सिंहः देहात में जितनी फर्म्ज हैं उनमें मोम को कोटा दिया गया है।

श्री अध्यक्षः आप इसके लिये अलग से नोटिस दीजिए। अभी इस वक्त इनके पास फिगर्ज नहीं हैं महेन्द्रगढ में भाहर में, या देहात में कितना कोटा दिया गया है, मंत्री महोदय के पास इस समय इसका जवाब नहीं है उसके बारे में आप उनसे दफ्तर में मिलकर या बाद में जवाब ले सकते हैं।

ठाकुर बीर सिंहः देहात और भाहर का टोटल बता दिया है। इसमें से ज्यादा कोटा देहात में ही दिया गया है।

कंवर राम पाल सिंहः मंत्री महोदय ने बताा है कि जो रजिस्टर्ड यूनिटस हैं उनको वैक्स का कोटा देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रजिस्टर्ड यूनिटस हैं क्या वाकई में वे

काम भी करती हैं या सिर्फ रजिस्टर ही हुए हैं ? क्या जो यूनिटस काम करती हैं उनको ही रजिस्टर किया गया है ?

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि 1975–76 में बैकवर्ड, नान बैकवर्ड के आधार पर फर्में रजिस्टर की गई थी। अब हम उनको रजिस्टर करते हैं जिनके पास आलरैडी म ाीनें हैं जिनका काम चल रहा है और जिनको समय पर कोटे के मुताबिक मैटीरियल नहीं भी मिल पाता तो भी वे काम चलाते हैं चाहे वे बाहर से मोम की खरीद कर लेते हैं। उनको ही रजिस्टर किया जाता है जिनके पास म ाीनरी भी है और उनकी वर्कि कपैसिटी दोनों ठीक हैं।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, यह कोटा दिया जाता है क्या वह हर महीने सप्लाई नहीं किया जा सकता ताकि उनको काम स्मूथली चल सके क्योंकि एक दम से जब उन्हें कोटा मिलता है तो उसको कभी वे खरीद भी नहीं पाते हैं और इसमें ब्लैक होने का अंदे ाा है ?

ठाकुर बीर सिंहः यह कोटा क्वार्टरली दिया जाता है क्योंकि सैंट्रल गवर्नमैंट क्वार्टरली ही डिस्ट्रिब्यूट करती है इसलिए हम भी उसी प्रकार डिस्ट्रिब्यूट करते हैं कोटाच उनका मुकर्रर है जो फर्म्ज काम करती हैं वे उनको वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से आगे क्वार्टरली ही डिस्ट्रिब्यूट कर देती हैं।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस मोम के कोटे में से हरिजनाों और बैकवर्ड क्लासिज को कितन कितना दिया जाता है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज और किसानों को मिला कर ही ये यूनिटस बनाये जाते हैं। चौधरी पीर चंद जी अगर इस बारे में जहां यूनिटस बनने रह गये हैं, बता दें तो वहां 5–10 ऐसे यूनिटस बना देंगे।

चौधरी पीर चन्दः मेरा सवाल स्पीकर साहब, यह था कि क्या हरिजनों को भी इस प्रकार के कोटे दिए गये हैं ?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब दे दिया गया है कि यह जो यूनिटस बनी हैं इसका एक पार्टनर जमींदार है और एक हरिजन है। इसका जवाब दे दिया गया है।

ठाकुर बीर सिंहः इनका जवाब मैं देता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो नई पालिसी बनाई है उसमें कैटेगरीज मुकर्रर कर दी हैं उन कैटेगरीज के मुताबिक ही आईंदा कोटा दिया जाएगा ताकि इस किस्मे जो आक्षेप आते हैं कि पूंजीपतियों को ही यह मोम का कोटा दिया जाता है वह नहीं रहेगा। इन कैटेगरीज में बार विडोज, हरिजन, ि ाडयूल्ड ट्राईब्ज, डिस एबल्ड मिलिट्री मैन और ब्लाइंडज भी आते हैं। रूरल इंडस्ट्रिलाईजे ान के तहत मोम आइंदा दिया जाएगा। इनमें से ि ाडयूल्ड कास्टस के 28 यूनिटों

को दिया जा चुका है। नई यूनिटस काफी देहात में खोली गई हैं, इनमें से काफी कोटा ि ाडयूल्ड कास्टस के यूनिटस ले चुके हैं।

श्री अध्यक्षः यह बताना इस समय बहुत डिफीकल्ट हैं। जो यूनिटस खोल रखे हैं उनको जब कोटा देते हैं तो उसमें ि ाडयूल्ड कास्टस भी मैंबर हैं और नान ि ाडयूल्ड कास्टा भी मैम्बर हैं।

ठाकुर बीर सिंहः जनरली तो हम इसी तरह से देते हैं लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने कुछ कोटा मुकर्रर किया है ताकि जो कुछ स्पैसिफिक कैटेगरीज हैं, जिनकी इमदाद होनी चाहिए जैसे सो ाली बैकवर्ड या डिस एबल्ड मिलीट्रीमैन हैं या कोई टोटली ब्लाईंड मैंन हैं जिसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, उसे एक सर्टीफिकेट देना पडेगा फिर इन सर्टीफिकेटस के हिसाब से उनको वह कोटा दिया जायेगां

श्री मूल चन्द मंगलाः एमरजैंसी के दौरान जिन जिलों को बैबवर्ड करार दिया गया था क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनको भी यह कोटा दिया जायेगा ?

ठाकुर बीर सिंहः देहात के और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को यह कोटा दिया जायेगा जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जो डिस एबल्ड हैं और इमदाद के हकदार हैं उनको यह कोटा दिया जायेगा

चौधरी हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, इन्होंने बताया कि 139 यूनिटों को गोम का कोटा दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनको बढाकर 239 कर देने को कोई विचार है ? मैंने इस संबंध में एक दो आदमियों से पूछा था जिनसे मुझे यह पता चला कि 14सौ और 16सौ रुपये के बीच फायदा होता है। सन् 76 में कुल 100820 यूनिटों को कोटा दिया गया था अगर इनको 239 बडे इंडस्ट्रियल यूनिटस में बांट दिया जाये तो इनको प्रौफिट इक्वली डिवाईड हो सकता है।

ठाकुर बीर सिंहः स्टेट का कोटा आलरेडी मुकर्रर है जितनी फर्म्ज हैं, उनकी म ीनरों और वर्किंग कपैसिटी के हिसाब से बडे कारखानेदारों को यह कोटा डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है जो आगे छोटे कारखाने वालों को डिस्ट्रिब्यूट करते हैं।

स्वामी आदित्यवे ाः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिलों में जैसे अम्बाला में 47 और सिरसा में 11 को कोटा दिया गया है वह किस आधार पर दिया गया है क्या वह राजनैतिक आधार पर दिया गया है ?

ठाकुर बीर सिंहः इसका क्वै चन से कोई ताल्लुक नहीं है। यह पहले बता दिया गया है किस आधार पर कोटा दिया जायेगा। अगर अब स्वामी जी चाहें कि बगैर म ीनरी के कोटा मिल जाये तो वह नहीं मिल सकता। इंडस्ट्री वाले पूरी तरह

वैरीफाई करते हैं कि कितनी म ीनें चल रही हैं और वर्किंग कपैसिटी क्या है, तभी कोटा दिया जाता है।

Committee Constituted to consider the demands of

work charged employees in P.W.D. (B & R)

***1179. Shri. Shamsher Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a Committee of Administrative Secretaries/Engineer in Chief was constituted in the year 1978 lto ocnsider the demands of work charged employees in P.W.D. (B & R);

(b) if so, a copy of the recommendations, if any, made be laid on the Table of the House; and

(c) the details of recommendations, if any, which have been accepted by the Government so far ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(क) वश्र 1978 में प्र ाासकीय सचिवों और मुख्य अभियंताओं की कोई समिति गठित नहीं की गई थी। बल्कि यह मामला प्र ाासकीय सचिवों और मुख्य अभियंताओं के मध्य दो बैठकों में विचारा गया थां

(ख) तथा (ग) इस ग्रुप द्वारा की गई सिफारि ाों का निरीक्षण प्र ाासकीय विभाग द्वारा किया जा रहा है क्योंकि यह मामला अभी विचाराधीन है। बैठकों में हुये विचार विम ार्श का ब्यौरा जन हित में विधान सभा के पटल पर नहीं रखा जा रहा है।

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चीफ इंजीनियर्ज की जो मिटिंग्ज हुई उन मीटिंग्ज में उन्होंने क्या सिफारि ों की हैं ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल तो वही है जो परसौं चौथे आया था यह बजट में आ चुका है और इनको पता नहीं है कि सवाल क्या है ?

Mr. Speaker: You mean to say that it is in public interest to divulge it. (Interruptions).

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय जी ने बताया कि वह सिफारि ों सरकार ने मान ली हैं .....

Mr. Speaker: I think, you better discuss it with him separately.

श्री भाम ोर सिंहः नहीं जी, अभी इन्होंने बताया कि वह सिफारि ों मान ली गई हैं।

Mr. Speaker: That was a private convesation between two of you. I did not hear what it was. You may, therefore, better discuss it with him.

तारांकित प्र न संख्या 1195

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र भार्मा इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Bye- Passes

***1186. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the number of accident has increased very much in the cities i.e. Panipat etc. due to rush of traffic on the G.T. Road; and

(b) if so, whether the State Government intends to draw the attention of the Central Government for constructing bye passes near the cities in Haryana situated on the G.T. Road ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) नहीं, श्रीमान।

(बी) पानीपत भाहर में एक बाईपास के निर्माण संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं

श्री फतेह चन्द विज: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगें जैसे कि उन्होंने पहले सवाल के जवाब में यह कहा कि

नहीं जी तो क्या मंत्री जी के पास आंकडें हैं कि 1977–78 और 1978–79 में कितने कितने एक्सीडैंटस हुए हैं ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, यह आंकडें मुझे पुलिस विभाग से मिले हैं यह मैं आपको बताता हूं कि अम्बाला सिटी में 1977–78 में तीन हुए और अम्बाला कैंट में 1977 में चार थे .....

श्री अध्यक्षः सरदार जी यह तो पानीपत में पूछ रहे हैं।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैं वह भी बता रहा हूं कि पानीपत में पहले 15 थे अब 11 हुए हैं

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या महम बाइ पास की प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, इसमें बाइ पास का सवाल कहां है ?

श्री फतेह चन्द विजः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा है कि बाइ पास का मामला विचाराधीन है तो क्या पानीपत में म्यूनिसिपल हदूद के अंदर जो जी0टी0 रोड है उसे चौडा करके उसमें भी पटरी बनाने का विचार सरकार के विचाराधीन है ताकि एक्सीडैंटस रोके जा सकें ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, यह बाइ पास चाहते हैं या अपनी गलिया पक्की करवाना चाहते हैं यह स्कीम गवर्नमैंट आफ इंडिया की प्लान, नै ानल हाई वेज नम्बर के अंदर है।

Mr. Speaker: The Hon. Member has asked a very fair question. वे जानना चाहते हैं कि जो भाहर के बीच में रोड जाती है उसके ऊपर पटरी बनाने का विचार है ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, वह नै ानल हाई वेज नंबर वन है। इनका जो सवाल है वह गवर्नमैंट आफ इंडिया की प्लान के अंदर है। यह इनके क्वै चन की बात नहीं है। इनको यह पता नहीं है और मुझे पता है कि वह नै ानल हाई वेज है।

श्री फतेह चन्द विजः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय जी फरमायेंगे जैसे उन्होंने इसमें कहा था कि दिल्ली से ले करके अम्बाला तक सडक चौडी करने की तजवीज है और दरमियान में पटरी भी बनाने की तजवीज है और अब कहा गया है कि कोई पता नहीं है तो इन दोनों में कौन सी बात ठीक है ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, यह बात नहीं है यह तो बाइ पास की बात कर रहे हैं। जब वह फोर लान बनेगी तो वह भाहरों में नहीं बना सकेंगे और इनके भाहर में इतनी जगह कहां है इसलिए वह नैचुरिली ही बाइ पास जाएगी।

Per Capita Income of tehsils in Haryana

***900. Swami Aditya Vesh:** Will the Chief Minister be pleased to State-

(a) the tehsil wise per capita annual income of the people in the State; and

(b) the basis on which the per capita income is determined ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): अध्यक्ष महोदय, तहसील वाइज उसकी आमदनी नहीं लगाई जाती है और यह सारे सूबे के जितने आर्थिक हालात होते हैं उसके मुताबिक कुल आमदनी का जोड़ लगा करके फिर उसको कुल आबादी से तकसीम कर दिया जाता है उसके मुताबिक सालाना आमदनी कितनी है, इसका अंदाजा लगाया जाता है।

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय जी से जानना चाहता कि राजकीय स्तर पर एक व्यक्ति की आय निकाली जा सकती है तो तहसील वाइज निकालने में क्या कठिनाई है ?

चौधरी देवी लाल: अगर आप यह पूछना चाहें कि स्टेट वाईज कितनी आमदनी है तो मैं बता सकता हूं लेकिन सारा हिसाब लगवाना चाहें तो आपको यह गलतफहमी हो गई है। मैं आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अर्थ ाास्त्री नहीं हूं। आप यह सैक्रेटेरियट से पूछ सकते हैं।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे सवाल का उत्तर नहीं है मैं तो सदन के सामने यह सवाल रख रहा हूं कि एक व्यक्ति की कितनी आय है ?

चौधरी देवी लालः मैंने पर कैपिटा आमदनी कहा था। अगर आप सुनना चाहें तो मैं स्टेट बाइज आमदनी बता देता हूं पंजाब की है 1812 रुपए, हरियाणा की सारे हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर है 1472 रुपए, हिमाचल की 1058 , वैस्ट बंगाल की 1047, कर्नाटक की 1002, तामिलनाडु की 921 इस तरह से कई 897 और 700 तक हैं। आपको खु ा होना चाहिए कि आपके बिहार से हरियाणा की बहुत ज्यादा आमदनी है।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं तहसील का और यह बता रहे हैं सारी दुनिया का ?

श्री अध्यक्षः नहीं स्वामी जी, यह बडा क्लीयरली जवाब दिया है कि स्टेट लैवल पर यह वर्क आउट होती है और तहसील लैवल पर स्टैटीस्टिकल डिपार्टमैंट वर्क आउट नहीं करता। इसको थोडा सा समझने में आपको फर्क हुआ है। आपने स्टेट ही इंकम ले करके उसको स्टेट की आबादी से तकसीम करें तो पर कैपिआ इंकमू कही जाएगी। जो तहसील वाइज है वह इस वक्त वर्क आउट नहीं हो सकती।

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए कि तहसील ही एक छोटा सा राज्य है, उसकी आमदनी निकाली जा सकती है तो इसकी क्यों नहीं निकाली जा सकती ?

श्री अध्यक्ष: आप इनसे यह रिक्वैस्ट कर सकते हैं कि आगे कि लिए निकाली जाए ?

चौधरी देवी लाल: मैं स्वामी जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह थोडी सी तकलीफ उठा लें और स्टेटीस्टिकल सैक्रेटेरी से मिल लें वह सारे हालात आपके सामने रख देंगे और आपकी राय भी उनको पहुंच जाएगी कि क्या कुछ आप चाहते हैं उसके मुताबिक भाायद तहसील वाइज भी आपको इन्फर्मे ान मिल जाए।

चौधरी गया लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जैसे उन्होंनें बताया कि हरियाणा में 1400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वश्र आय है क्या इसमें करोडपति फैक्ट्री वालों की और झोंपडी में रहने वालों की एक बराबर आमदनी रखी गई है ?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं बनता है।

Question Hour is now over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों

के लिखित उत्तर

Regularisation of work charged employees in P.W.D. (B & R)

***1180. Shri Shamsher Singh:** Will the Ministter for Public Works be pleased to state-

(a) the category wise number of work charged employees in each Circle of the P.W.D. (B & R) whose services were regularised in 1974 and prior to that year;

(b) whether it is a fact that employees of P.W.D. (B & R) whose services were regularised before 1974 and during 1974 or after wards are being given different pay sclaes for the same post;

(c) if so, the names of such categories of employees togetherwith the details of different two sets of pay scales; and

(d) the steps being taken to remove the anamoly tin the pay scales for the same post ?

***Interim Reply**

MOST IMMEDIATE.

D.O. No. 17/3/79-PW-III(8)

Minister for Public Works,

Chandigarh.

March 24, 1979.

Subject : Starred Question no. 1180- Shri Shamsher Singh Surjewala M.L.A., regargdingh regularisation of work charged employees in P.W.D. (B & R)

Dear Col. Ram Singh Ji.

Starred Vidhan Sabha Question No. 1180 is dut for answer on 26th March, 1979. The answer of this question is not ready for want of necessary informaiton from the field offices which is being collected. Some more time is needed for collecting information from field offices and its compilation. It is, therefore, requested that time limit for answering. Starred Assemble question No. 1180 may kindly be extended for about a fortnight and some other date may kindly be fixed for its reply.

Your sincerely,

Sd/- (Lachhman Singh)

Col Ram Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Property Tax

***1072. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) the total amount of arrears of property tax upto 31st March, 1977 in Haryana State; and

(b) the total amount of property tax outstanding for the period from 1st April 1978 to 31st January 1979 in the State ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(ए) 31—3—1977 तक सम्पत्ति कर का कुल बकाया 3855296/— रुपये था।

(बी) चूंकि सम्पत्ति कर आरोपण अथवा समाप्त करने सम्बंधी मामला अभी सरकार के विचाराधीन है, प्र नाधीन अवधि के लिए सम्पत्ति कर की कोई मांग बनाई नहीं गई है।

Theft cases in Kaithal constituency

***1183. Shri Raghu Nath Goyal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether the Government is aware of the fact that theft cases are being committed in large number in the Kaithal Assembly Constituency;

(b) if so, the steps, if any, being taken by the Government to check them; and

(c) whether there is a proposal under consideration of the Government to set up any Police Post some where in the said Constituency ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह):

(अ) कैथल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1977 तथा 1978 में चोरी के केसों में कुछ बढौतरी हुई क्योंकि केसों को मुक्त रूप से दर्ज करने की नीति अपनाई गई। चालू वर्श में फिर भी पिछले वर्श के पहले 3 मास की तुलना में केसों में कमी हुई।

(ब) फिर भी अंधेरा पडने के समय से सुबह तक पुलिस ग त और पुलिस नाकाबंदी अपराध को नियन्त्रण में रखने के लिये चालू हैं

(स) नहीं।

Enquiry aginst the Sarpanch of Village Panchayat Buwan

***1196. Comrade Shankar Lal:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state.-

(a) whether any enquiry in respect of Panchayat funds has been conducted by the Vigilance Policie against the Sarpanch of village Panchayat Buwan, District Hissar, if so, a copy of the contents of the report of the Enquiry Officers be laid on the Table of the House; and

(b) the action taken sor far on the said enquiry report ?

विकास मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(क) हां। जांच की प्रति सदन के पटल पर रखी है।

(ख) सरपंच द्वारा पहंचाई गई हानि की वसूली हो चुकी है।

प्रति

गोपनीय

प्रेशक

निदे ाक,

वि ोश जांच अभिकरण, हरियाणा,

चण्डीगढ़।

सेवा में

उप सचिव (नाम से)

हरियाणा सरकार,

चौकसी विभाग।

क्रमांक 3046/वि0ज0अभि0 ह, दिनांक

विशय :– जांच क्रमांक 13 दिनांक 12–9–77 जिला हिसार।

विरूद्धः– श्री प्रभु दियाल सरपंच ग्राम पंचायत बवान तहसील फतेहाबाद जिला हिसार।

महोदय,

यह जांच मुख्य मंत्री महोदय सचिवालय के डायरी क्रम संख्या 557 और दिनांक 8–9–77 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर की गई और री बृज मोहन प्रार्थी की ि ाकायत में प्रतिवादी के विरूद्ध लगाए गए निम्नलिखित आरोपों की पडताल की जानी थी :–

आरोप नं0 1

कि श्री प्रभुदियाल सरपंच प्रतिवाद ने पंचायत फंड में से परिवार नियोजन ओपरे ान के 72 केसौं पर 7200 रुपये की रा ि ा खर्च की। वास्तविकता यह है कि उस समय की सरकार नकद तथा काईंड के रूप में प्रोत्साहन के लिए काफी खर्च कर रही थी। यह रा ि ा माह 9–76 में एक दिन के परिवार नियोजन कैंप पर खर्च नहीं की जा सकती। सारी रा ि ा सरपंच द्वारा उस समय के खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी श्री हंस राज के साथ मिलकर जेबों में डाली गई और इस फराड को पूरा करने के लिये पंचायत ने प्रस्ताव पास किर दिया और इस बारे में पंचायत सदस्यों ने भी सहयोग दिया।

आरोप नं0 2

कि गांव बवान में खसरा नं0 25/11 से 23,86/1, 2,3 की 15 एकड भूमि पंचायत भूमि में से श्रीमती नसीरी बेगम को अलाट कर दी। प्रतिवादी ने यह भूमि अपने भतीजे (बहन के लडके) जगदी ा पुत्र भोला राज के नाम खरीद ली। श्री कुंदन लाल ने गलत अलाटमैंट के लिए हरियाणा सरकार के विरूद्ध दिवानी दावा कियां केस का फैसला सब जज प्रथम श्रेणी के न्यायालय में 26–11–76 की पंचायत के हक में (कुंदन लाल) हो गया। माल रिकार्ड में इंद्राज ग्राम पंचातय के हक में हो गया। यह इन्द्राज होने के बाद भूमि की मालिक पंचायत है और इसे सरेआम बोली में नीलाम करना चाहिए था। इस पर अब भी श्री जगदी ा

(सरपंच के भतीजे) का कब्जा हैं इस हिसाब से पंचायत को 10000 रु0 की वार्शिक हानि हो रही है और वास्तव में यह गबन है।

आरोप नं0 3

कि सरपंच प्रतिवादी ने अपने घर के सामने लगभग 600 वर्ग गज भाामलाल देह के प्लाट पर नाजायज कब्जा कर रखा है।

आरोप नं0 4

कि सरपंच प्रतिवादी को उपायुक्त हिसार द्वारा उनके आदे ा क्रमांक 1349–41 दिनांक 16–6–73 द्वारा चेतावनी दी गई थी कि सरपंच अपने घर पर पंचायत का फर्नीचर रखे हुए हैं, और प्रयोग कर रहा है और यह पंचायत भूमि नाजायज बीज रहा हैं यह इस चेतावनी के बाद भी नहीं बदला।

आरोप नं0 5

ऐसा प्रतीत होता है कि सरपंच प्रतिवादी ने कानून की इज्जत खो रखी है, अपनी मरर्जी के अनुसार काम कर रहा है और जनता रा ि ा को खुर्द बुर्द करके खुब धन कमा रहा है।

उपरोक्त आरोपों की पूर्ण पडताल निरीक्षक गुरबख्भा सिंह ने सहायक उपनिरीक्षक, राजेन्द्र सिंह की सहायता से पूर्ण की है जिसकी अन्तिम रिपोर्ट की तीन प्रतियां संलग्न हैं पडताल के

फलस्वरूप इस जांच में जो निर्णय पाया गया है उस बारे प्रति आरोप टिप्पणी निम्न प्रकार से है :–

टिप्पणी :–

आरोप नं0 1

पड़ताल के दौरान श्री बृजमोहन परिवादी से सम्पर्क स्थापित किया गया है जिसने अपनी दी हुई ि ाकायत में लगाए हुए आरोपों की पुश्टि की है आढैर अपने कथन (क0 पृ0 1 से 6 में बताया कि प्रतिवादी ने परिवार नियोजन पर पंचायत रिकार्ड में 7200 रुपये की रा ि ा खर्च करनी दिखा रखी है और वास्तव में पंचायत फंड में से कोई पैसा परिवार नियोजन के लिए प्रतिवादी ने किसी को नहीं दिया और श्री हंसराज भाटिया खंड विकाए एवं पंचायत अधिकारी भूना, तथा मैम्बर पंचायत बवान जिनके हस्ताक्षर व अंगूठे उपरोक्त रा ि ा खर्च करने के बारे प्रस्ताव पास करने पर है, से मिलकर तथा सचिव ग्राम पंचायत से भी मिलकर उपरोक्त रा ि ा का गबन किया। कानून के अनुसार परिवार नियोजन पर पंचायत फंड में से पंचायत का काई पैसा खर्च नहीं कर सकती। इस प्रकार सरपंच ने साजबाज करके पंचायत रा ि ा का गबन किया है। उपरोक्त कथन की पुश्टि श्री सौदागार राम, गुरनाम सिंह, भाादी राम, सुंदर सिंह ने अपने सांझे कथन (क0पृ0 11–12 में की है। पडताल के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने श्री राम, ग्राम सचिव का कथन (क0पृ0 13 से 19 प्राप्त किया है जिसने अपने

कथन में बताया कि गांव बुवान में परिवार नियोजन का कैंप 19–9–76 व 20–9–76 को उच्च अधिकारियों की हिदायत पर लगा था, जो इस बारे में दिनांक 18–9–76 प्रस्ताव नं0 2 भी पास किया गया कि इस कैंप का खर्चा पंचायत फंड में से किया जाए इस प्रकार परिवार नियोजन पर कुल खर्चा 817 रुपये 50 पैसे खर्च हुआ था और अपने कथन में इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने किसी रकम का कोई गबन नहीं किया और पडताल के दौरान अन्य मैम्बर पंचायत का सांझा कथन (क0पृ0 21–22) पर प्राप्त किया गया है जिन्होंने भी आरोप की पुश्टि नहीं की और बताया कि पंचायत फंड की रा ि ा का कोई गबन नहीं किया गया और प्रस्ताव जो खर्चे पाए किए गऐ हैं, उन पर उनके हस्ताक्षर करने भी ठीक हैं। पडताल के दौरान पाया है कि पंचायत ने उपरोक्त परिवार नियोजन के लिए प्रस्ताव भी पास कर रखे हैं। जो प्रस्ताव दिनांक 22–9–76 द्वारा मुबलिग 268 रुपये तथा प्रस्ताव दिनांक 7–11–76 द्वारा क्रम संख्या 5,6,7 के अनुसार वर्मा मैडीकल हाल भुना, के मुबलिग 83 रुपये 50 पैसे, 144 रुपये, 332 रुपये कुल रा ि ा 817रुपये 50 पैसे के खर्चे के प्रस्ताव पंचायत ने सर्वसम्मति से पास कर रखे हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। उक्त रा ि ा का इन्द्राज कै ा बुक माह 9/76 के पृश्ट 12/170 मास 11/76 के पेज 14/170 पर है उक्त रा ि ा के बौचर नं 57, 58,59,60 व 61 वर्श 1976, 66, 67, 68 वर्श 1976 बौचर फाईल में देखे जा सकते हैं। जिन व्यक्तियों को परिवार नियोजन कैंप के बारे अदायगी की है, की तसदीक की गई उनमें से सर्वश्री रमै ा,

कपूरी राम, श्रीमती फूल, सूरज प्रका ा पार्टनर वमा मैडिकल हाल भूना, औम प्रका ा मालिक जैन फैन्सी स्टोर भूना के कथन (क0 पृ0 31, 33, 37, 27, 23) प्राप्त किए गए हैं जिन्होंने ग्राम पंचायत भूना से रा ि ा ठीक लेनी मानी है और श्री बि ान दास पुत्र पोखर दास ने अपने कथन (क0पृ0 35) में बताया कि उसने रात दिन परिवार नियोजन कैंप में रोटी चाय आदि का काम किया था, जहां तक उसे याद है उसे मजदूरी की रा ि ा 80 रुपये मिली थी। परन्तु बौचर नं0 58 दिनांक 31–8–76 में मुबलिग 100 रुपये रा ि ा दर्ज है लेकिन उसने उस पर अपने हस्ताक्षर करने ठीक माने हैं पंचायत ने उक्त रा ि ा के खर्चे का प्रस्ताव पास कर रखे हैं और श्री बि ान दास किसी गलती से अपने कथम में 80 रुपये रा ि ा लेना मानता है। जबकि उक्त बौचर र ाीद पर अपने हस्ताक्षर करने ठीक मानता है। इसलिये इसके कथन पर वि वास करना उचित नहीं है। पडताल के दौरान खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया गया है जिसने अपने पत्र क्रमांक 2815 दिनांक 28–12–77 में बताया कि पंचायत प्रत्येक नसबंदी/नल बंदी करवाने वालों को 50रु0 प्रति केस पर व्यय कर सकती है। अगर 50 रु0 प्रति केस से पंचायत ज्यादा खर्च करे तो वह खर्चा अवैध है। यह प्रलेख तथा अन्य प्रलेख प्रलेख फाईल के पृश्ट 41 से 45 पर देखें जा सकते हैं जिसके अनुसार उपरोक्त पंचायत ने कुल 817 रुपये 50 पसै 76 नसबंदी/नलबंदी पर खर्च किए। जिसकी पुश्टि चिकित्सा अधिकारी भूना के पत्र दिनांक 25–1–78 से होती हैं जो पत्र प्रलेख फाईल को पुश्ठ 83 पर लगा

देखा जा सकता है और खंड तथा पंचायत अधिकारी भूना के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 8–2–78 जो प्रलेख फाईल के पृश्ठ 87 पर देखा जा सकता हैं के अनुसार ने ग्राम पंचायत बुवान की परिवार नियोजन पर खर्च करने के लिए कोई प्रोत्साहन रा ि ा (गवर्नमैंट इनसैंटिव मनी) नहीं दी गई है।

इन परिस्थितयों में यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ। निरासार पाया गया है।

आरोप नं0 2

कि इस आरोप के विशय में अनुसंधान अधिकारी ने तहसील (बिक्री) हिसार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है जो प्रलेख फाईल के पृश्ठ 53–54 पर देखी जा सकी है। तहसीलदार बिक्री ने श्रीमती नसीरी बेगम को ग्राम बुवान की भामलात भूमि में से 115 कनाल 5 मरले भूमि अलाट की इस पर श्री कुन्दन लाल मैम्बर पंचायत ने गलत अलाटमैंट के लिए न्यायालय में दावा किया। जिसकी पुश्टि श्री कुन्दल लाल ने अपने कथन (क0पृ0 9–10) में की है और इस केस के बारे श्री एच0आर0 गोयल, सब जज हिसार ने जिसके फैसले की प्रति फाईल प्रलेख के पृश्ठ 55 से 66 पर देखी जा सकती है। फैसला किया। उसके बाद श्री कृश्ण कान्त अग्रवाल सीनियर सब अज हिसार के न्यायालय के फ ैसले दिनांक 24–8–77 की प्रति प्रलेख फाईल के पृश्ठ 67–69 पर देखी जा सकती है। फैसले में लिखा है कि श्री कुन्दन लाल एक

नया दावा दायर कर सकता है। जो श्री कुंदन लाल आदि ने श्री एस0के0 बांसाल के न्यायालय में 16–11–77 को एक नया दावा दायर कर रखा है। जो मामला न्यायालय में लम्बित है। इस आचरण पर इस आरोप के बारे में कोई टिप्पणी दी जानी उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधनी है।

आरोप नं0 3

पडताल के दौरान प्रार्थी तथा सर्व श्री सौदागरमल, सुन्दर सिंह, गुरनाम सिंह, भाादी राम ने अपने अपने कथनों में आरोप की पुश्टि की है इन कथनों के फलस्वरूप अनुसंधान अधिकारी ने तहसीलदार फतेहाबाद से सम्पर्क स्थापित किया और तहसीलदार फतेहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 5–1–78 को प्रलेख फाईल के पृश्ठ 75 पर देखा जा सकता है; में बताया कि श्री प्रभुदियाल सरपंच ग्राम बुवान ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा के बारे में गिरदावार व पटवारी हल्का से छानबीन कराई गई है। पटवारी व हल्का गिरदावार की रिपोर्ट दिनांक 4–1–78 के अनुसार राजस्व रिाकर्ड व मौका पर ग्राम पंचायत की भूमि पर सरपंच प्रतिवादी का अवैध कब्जा न हैं पडताल के दौरान सर्वश्री छोटूराम मेहरचन्द, टाला राम, मैम्बर पंचायत ने अपने सांझे कथन (क0पृ0 21–22) में बताया कि श्री प्रभुदियाल सरपंच प्रतिवादी ने अपने मकान के सामने भााम लाल भूमि के प्लाट पर नाजायज कब्जा नहीं किया है। इन परिस्थितियों में यह आरोप सिद्ध न हो पाया और निराधार रहा।

आरोप नं0 4

पडताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी को दिनांक 16–6–77 को चेतावनी दी जिसकी प्रमाणित प्रति व असल प्रति प्रलेख फाईल के पृश्ठ 5 व 7 पर देखी जा सकती हैं जो मामला पहले ही विभाग के ध्यान में हैं

अतः यह आरोप0 सारपूर्ण रहां

आरोप नु0 5

पडताल के दौरान यह आरोप सामान्य प्रकार का पाया गया। पडताल के फलस्वरूप पाया गया है कि प्रतिवादी भिन्न भिन्न समय पर भिन्न रा ि ा के जो पंचायत फंड के रूप में भी अपने पास रखता रहा और पंचातय एक्ट रूल के अनुसार 50 रु0 से अधिक रा ि ा सरकारी खजाना में प्रतिवादी जमा नहीं करवाता रहा है जिसकी पुश्टि प्रार्थी के कथन व प्रतिवावदी द्वारा अपने कथन में दिए गए ब्यौरा (क0पृ0 49–50) से होती हैं पडताल के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी भूना से सम्पर्क स्थापित किया है, जिसने अपने पत्र दिनांक 8–2–78 प्रलेख फाईल पृश्ठ 97 पर है, में बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत में ऑडिट के दौरान उसके बाद कै ा इन हैण्ड रा ि ा रखी हुई के मालिक गो ावारे की रिपोर्ट जिस की प्रति प्रलेख फाईल के पृश्ठ 109 वा 113 पर देखी जा सकती है। आडिट के समय रखी हुई रा ि ा का दंडित ब्याज धारा 105(2) ग्राम पंचायत एक्ट 1952

(सं ाोधित) के तहत निर्धारित करके उसे क्रमांक 2520–23 दिनांक 25–10–77 द्वारा नोटिस दिया था जिसके अनुपालन में सरपंच प्रतिवादी ने दंडित ब्याज की रा ि ा मुबलिग 410 रुपये 72 पैस सहकारी बैंक भूना में दिनांक 25–1–78 को असल रा ि ा के साहित कुल मुबलिग 3285 रुपये की रा ि ा जमा करवा दी है और उसके बाद सरपंच प्रतिवावदी के पास जो कै ा इन हैण्ड रही है उसके बारे में दंडित ब्याज वसूली के लिए दिया जा रहा है और पंचायत फंड के दंडिज बयाज 1362 रुपये 25 पैसे वसूल करने के लिए उपरोक्त कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी प्रति प्रलेख फाईल के पृश्ठ 121 पर देखी जा सकती है। इन परिस्थितियों में वैसे तो कानून के अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध जेरे धारा 403 भ0द0स0 के अन्तर्गत अपराध किया गया बनता है परन्तु उपरोक्त कार्यालय ने प्रतिवादी को पंचायत एक्ट 1952 की धारा 105(2) में दंडित ब्याज की पैनलिटी लगाकर उसे सजा घो ि ात कर दी है।और कानून और संविधान के अनुसार अपराधी को एक से ज्यादा बार एक अपराध करने के बारे में सजा नहीं दी जा सकती। प्रतिवादी द्वारा समय समय पर पंचायत फंड का कै ा इन हैण्ड रखना उसको दंडित बयाज लगाना विभाग के ध्यान योग्य है और सम्बन्धित विभाग को यह सुझाव दिया जावे कि प्रतिवादी के विरूद्ध अन्य प्र ाासनिक कार्यवाही भी की जावे।

इन परिस्थितियों में यह आरोप सिद्ध रहा है।

भवदीय

हस्ता/–

निदे ाक

वि ोश जांच अभिकरण, हरियाणा,

चण्डीगढ़।

Temporary Teachers

***1192. Ch. Ishwar Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the number of temporary teachers workign on six months basis at present;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the aforsaid teahcers; if so, ther time by which their services are lileky to be regularised; and

(c) the number of Adult Education Centres opened in the State so far together with the number of unemployed teachers appointed there ?

िशक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(क) 4650

(ख) जी नहीं।

(ग) 2815, 610

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Custodian Land

279. Shri Bhagi Ram: Will the Minister for Revenue be pleases to state-

(a) whether it is a fact that the auction of the Custodian Land is not confirmed even after auctioning it thrice, if so, the reasons therefor; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to confirm the auction of the Custodian Land after auctioning it twice ?

Revenue Minister (Shri Prit Singh):

(a) Part (i) Yes. In certain cases.

Part (ii) According to State Rules governing the sale fo surplus rural evacuee properties, the confirming authority is not bound to accedpt tghe highest bid or disclose his reasons therefor. In some cases the bids are not confirmed because of the following – (i) the price fetched is below the reserve price or below the previous fetched price wherein the previous auction purchaser has resioled from the auction, (ii) acceptance of objection petition agaist the auction (iv) pooking amojnt the bidders and (v) price fetched is not found to be fair or reasoble.

(b) No.

आबकारी तथा कराधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य –

(1) बाद ाहपुर कुरुक्षेत्र में भाराब के ठेकों की नीलामी सम्बन्धी

15.00 बजे।

श्री अध्यक्षः एक्साईज एंड टैक्से ान मंत्री जी ने स्वामी आदित्यवे ा एम0एल0ए0 के गांव बाद ाहपुर जिला कुरुक्षेत्र के गांव उमरी तथा करनाल के कुछ गांवों में भाराब के ठेकों की नीलामी के बारे में ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पर बयान देना है, वे अपना बयान दे सकते हैं।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह): जहां तक बाद ाहपुर के ठेके को बंद करने का सम्बंध है, माननीय सदस्य ने जो प्र न किया था उसके उत्तर में मैंने यह आ वासन दिया था कि अगस्त में जो रेजोल्यू ान आया वह 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और बाद ाहपुर में ठेका अगले साल बंद कर दिया जायेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि मैं पहली अप्रैल को वर्तमान वर्श मानकर कह रहा था। अतः अगले वर्श से मेरा अभिप्राय अप्रैल 1980 से था अगर पहली अप्रैल 1979 से होता तो मैं उस समय भी कह सकता था कि पहली अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा जैसा मैंने पहलें कहा था। फिर भी अगर माननीय सदस्य का यह विचार है कि इसका अर्थ यह था कि ऐसा ठेका 1–4–1979 से बंद होगा तो इस आ वासन को देखते हुए यह आदे ा जारी कर दिये गये हैं कि यह ठेका 174–1979 से ही बंद कर दिया जाये।

2. जहां तक उमरी ग्राम पंचायत का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति इस प्रकार है कि उमरी ग्राम पंचायत ने अपने गांव से भाराब की दुकानें बंद करने के लिए प्रस्ताव 2–1–1979 को पास

किया था। सरकार का निर्णय यह था कि जो प्रस्ताव पंचायत की ओर से 31–12–78 तक आयेंगे उन पर ही विचार किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत को सक्षम अधिकारी ने बुलाया था और उनको सारी बात बताने के बाद उन्हें यह परामर्श दिया था कि सरकार की नीति के अनुसार इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता और इस पर विचार 1–4–1980 से ही किया जा सकता है, अगर पंचायत इसके बारे में दोबारा प्रस्ताव पास करके पुनः भेजेगी। इसलिए यह ठेका 1–4–1979 से बंद नहीं किया जा सकता।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं इन्होंने उमरी गांव के भाराब के ठेके के बारे में अपना वक्तव्य दिया है। पिछले वर्श उस गांव के लोगों ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि वहां पर ठेका नीलाम न किया जाए। प्रस्ताव पारित करके भेजने थे 31 दिसम्बर तक किन्तु प्रस्ताव भेजा है 1–1–79 को। केवल एक दिन का अन्तर है फिर भी ठेके बन्द नहीं किये। गांव वालों की भावना यह है कि उनके गांव से ठेका हटना चाहिए। क्या मंत्री महोदय जी बतायेंगे कि उनकी भावना का आदर क्यों नहीं किया गया और उनकी भावना का आदर करते हुए वहां भाराब का ठेका इस साल से ही बन्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: वे यह कह रहे हैं कि इस साल से बंद नहीं होगा।

(2) जिला करनाल में भाराब के नए ठेकों की नीलामी के सम्बंधी

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, जिला करनाल के बारे में भी काल अटैन् ान मो ान दी थी, उसका जवाब नहीं आया, यह असंध और कासना के बारे में था ....

स्वामी आदित्यवे ाः मैंने करनाल के ठेकों के बारे में पूछा था लेकिन मंत्री महोदय ने पिछले साल की पालिसी के बारे में जवाब दे दिया .... (व्यवधान)

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब सुनी लीजिए, उसके बाद जो कहना चाहें, कह लें ......

स्वामी आदित्यवे ाः मेरा काल अटैन् ान मो ान यह था कि सरकार न ाबंदी लागू करने से पीछे क्यों हट रही है .... (व्यवधान)

Mr. Speaker: Order please. The Hon. Minister is making a statement.

चौधरी भोर सिंह: माननीय सदस्य द्वारा जिला करनाल में देसी भाराब की चार दुकानें, घोड, जुण्डला, सफीदों रोड असंध तथा कासना वर्श 1978–79 के लिए नीलामी किए जाने के बारे में प्रस्तुत नोटिस के सम्बंध में मुझे सदस्य को सूचित करना है कि

वर्श 1978–79 के दौरान इन स्थानों पर यह दुकानें स्वीकृत की हुई हैं।

2. जैसा कि सदन को ज्ञात ही है कि सरकार ने सदन में यह आ वासन दिया था कि जिन ग्राम पंचायतों द्वारा रैजोल्यू ान पारित करके अपने अपने क्षेत्र में देसी भाराब की दुकानें बंद करने की मांग की जाएगी, बंद कर दी जाएगी। सरकार ने 2–710–1977 से ग्राम चौटाला के 8 मील के घेरे तथा तावडू के इर्द गिर्द 144 गांवों की पट्टी को न ाबंदी क्षेत्र घोशित कर दिया हुआ है। राज्य में आगामी चार वर्शों में पूर्ण न ाबंदी प्रावस्था रूप से (in phased manner) लागू करने की मं ाा को ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही की गई थी। वर्श 1978–79 के लिए बतौर प्रथम पग, दे ाी भाराब को कोटा 20 प्रति ात कम कर दिया गया। वर्श 1977–78 में प्राप्त प्रस्तावों पर उचित रूप से विचार किया गया और इसके फलस्वरूप देसी भाराब की दुकानों की संख्या 518 से घटाकर 387 कर दी गई। जुण्डला, सफीदों रोड असन्ध तथा काचवा (न कि कासना) की भाराब की दुकानों को बंद करने के संबध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु 3 मार्च 1978 को ग्राम पंचायत घीड (न कि घोड) से एक प्रस्ताव देरी से प्राप्त हुआ था, जिसे उचित विचार उपरांत विभाग ने अस्वीकार कर दिया .....

चौधरी ि ाव राम वर्मा: स्पीकर साहब, यह पूछा था कि इन गांवों के रैजोल्यू ान आ चुके हैं फिर भी ठेके क्यों नीलाम

कर दिए गए हैं दोबारा सारी कहानी कहने का क्या मतलब है ? असंध रोड सफीदों और काछवा की दुकानें बंद करने क लिए पूछा था, इनके बारे में बता नहीं रहे दूसरी कहानी कह रहे हैं .... (व्यवधान)

चौधरी भोर सिंहः ये दुकानें तो बंद ही नहीं हुई और मंत्री जी को बताया 26 दुकानें थीं जिनको मार्च में अलाट किया था, इन में से कई दुकानों की सिक्योरिटी फीस नहीं आई थी। कैबिनेट की सब कमेटी ने यह फैसला किया था कि इनको दोबारा अलाट किया जाए। 26 दुकानों में से 15 दुकानें ऐसी थीं जिनकी सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करवाई थी। अगर आनरेबल मैम्बर चाहते हैं तो मैं उनके नाम पढ देता हूं।

Mr. Speaker: Actually all that is required is that the Minister is to read out his statement and then आप एक दो सवाल पूछ सकते हैं इसके बाद ज्यादा डिसक ान में जाने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी पहले अपनी स्टेटमैंट पढ दें।

Ch. Sher Singh: The Statement furhter reads-

3. देसी भाराब के बडे ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करने की मन ाा से सरकार ने ऐसे लाईसैंस अलाटमैंट द्वारा देने का निर्णय किया। ऐसी दुकानों/लाइसैंसों की अलाटमैंट में उपरोक्त चार दुकानें भी अलाट की गई थी। जिस पार्टी की सफीदो रोंड असन्ध की दुकान अलाट की गई थी, उसने वाछित लाइसैंस फीस तथा प्रतिभूति की रा ि ा जमा नहीं करवाई। भोश

तीन दुकानें बन्द नहीं की और यह वर्श 1978–79 की अलाटमैंट के लिए प्रचलित (current) रहे। क्योंकि इन दुकानों को बंद करने के लिए दिनांक 31–12–78 तक विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए, इन ठेकों को दूसरे ठेकों की भांति नीलाम कर दिया गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य को कोई बोधभ्रम (misapprehenstion) हुआ है कि यह नई दुकानें हैं। वास्तव में तो यह वश्र 1977–78 में चालू थी और वर्श 1978–79 में प्रचलित (current) रहीं।

4. जहां तक न ाबंदी नीति का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार से इस उद्दे य का अनुसरण कर रही हैं वर्श 1979–80 के लिए प्रत्येक जिला में वर्तमान, भारत में बनी विदे ी भाराब की दुकानों की संख्या 40 प्रति ात कम की जा रही हैं और देसी भज्ञराब को कोटा और 20 प्रति ात कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक अप्रैल 1979 से कोई नई भाराब की दुकान खोली स्वीकृत नहीं की गई है। इसके विपरीत 19 देसी भाराब की दुकानें वर्श 1979–80 के लिए बंद कर दी गई हैं। उपरोक्त तथ्यों से भली भांति प्रमाणित हेाता है कि न ाबंदी की नीति से किसी भी तरह हटा नहीं गया है।

स्वामी आदित्वे ाः मंत्री जी न जो वक्तव्य सदन में रखा है, उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल इन चार दुकानों को लेने वाला कोई नहीं आया, खाली पडी रही। इससे साफ जाहिर होता है कि इस इलाके के लोग भाराब के ठेके

नहीं चाहते लेकिन सरकारने जबरदस्ती नीलाम करके लोगों की भावनाओं का आदर नहीं किया और भाराबबंदी पालिसी को लागू नहीं किया है।

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, 73 दुकानें थी, इनमें से 26 दुकानें ऐसी थी जिनकी लाटरी डाली गई थी लेकिन सिक्योरिटी वगैरा जमा नहीं करवाई, इस लिए दोबारा नीलाम किया गया, इनसे प्रस्ताव पास होकर नहीं आये थे ..... (व्यवधान) .....

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग .....

ग्रहण की गई ध्यानाकर्शणर सूचना को वापस लेने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः साहेबान 23 मार्च को चौधरी हर स्वरूप बूरा ने अपना काल अटैन ान मो ान, जो लाइनिंग आफ वाटर चैनल्ज, यानी खालैं पक्की करने के बारे में था जिसका जवाब मन्त्री महोदय ने देना था, वापिस ले लिया था और उनका वापिस लेना मैंने स्वीकार कर लिया था। इस पर सुशमा जी ने एक प्वायंट आफ आर्डर रेज किया था, लेकिन काल अटैन ान मो ान के वापिस लिए जाने के बारे में मैंने जो फैसला किया था वह बरकरार रहेगा। इसके दो बेसिज हैं पार्लियामैंटरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बाई कौल एंड भाकधर के पेज 412 पर लिखा है –

"A Calling attention notice which has been admitted and put down in the list of business may be withdrawn by the

member concerned witht he Chair's permission on so stating his intention on the floor of the House."

यानी मैम्बर साहब जिन्होंने नोटिस दिया है वह उसे वापस स्पीकर साहब, की इजाजत से ले सकते हैं यह बात आन दी फ्लोर ऑफ दी हाउसा कह करके कि मैं इसे वापस लेना चाहता हूं। उस दिन श्री हर स्वरूप बूरा गैर हाजिर थे। उन्हौंने कहीं जाना था। इसलिए वे हाउस में नहीं आ सके। लिखित रूप में वे मेरे को दे गए थे। उसे मैंने हाउस में पढ कर सुना दिया था और उस पर अपना फैसला भी दे दिया था। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे रूलज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 112 में यह है कि अगर किसी ने किसी बात पर एतराज उठाना हो तो उसे उसी वक्त उठाना चाहिए। सुशमा जी यह एतराज उस वक्त नहीं उठाया था बल्कि सरदार लछमन सिंह जी जब अपनी पूरी स्टेटमैंट दे चुके उसके बाद उठाया। इन दोनों बेसिज पर इस प्वायंट आफ आर्डर को रद्द किया जाता है।

वर्श 1979–80 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब 1979–80 की डिमांडज फार ग्रान्टस पर बहस होगी तथा फिर मतदान होगा।

पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज फार ग्रान्टस और उनके ऊपर जो कट मो ान्ज आई हैं एक साथ पढी गई तथा पे ा की गई समझी जाएंगी। माननीस सदस्य किसी भी डिमांड पर डिसक ान कर सकते हैं लेकिन बोलते समय वह उस डिमान्ड का नम्बर बताएंगे जिस पर वे बोलना चाहते हैं। गवर्नमैंट की रिप्लाई के बाद कट मो ान्ज और डिमांडज पर अलग अलग मतदान कराया जाएगा। (विघ्न)

"कि 60714070 रुपए से अनधिक धन रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 2 सामान्य प्र ाासन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 157609960 रुपए से अनधिक धन रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों का चुकाने के लिए अनुदान की जाये जो मांग संख्या 3 गृह के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 544572990 रुपऐ से अनधिक धन रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 9 ि ाक्षा के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 28970470 रुपए के अनधिक धन राि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाये जो मांग संख्या 12 श्रम तथा रोजगार के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 57313085 रुपए से अनधिक धन राि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 16 उद्योग के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 477983020 रुपए से अनधिक धन राि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाये जो मांग संख्या 23 परिवहन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

डिमांड नं0 2

1 2	श्री भाम ेर सिंह सुरजेवाला़ श्री सुरेन्द्र सिंह	कि सामान्य प्र ाासन के बारे मे 60714070 रुपये की मांग संख्या 2 में 1 रुपये की कटौती की जाये।
9 10	श्री इन्द्रजीत सिंह श्री नारायण सिंह	कि सामान्य प्र ाासन के बारे में 60714070 रुपये की मांग संख्या 2 में 1 रुपये की कटौती की जाये।

डिमांड नं0 3		
3	श्री भाम ेर सिंह सुरजेवाला	कि पुलिस के बारे में 129442100 रुपये की मांग संख्या 3 के अधीन मुख्य भीर्श 255 में 1 रुपये की कटौती की जाए।
4	श्री सुरेन्द्र सिंह	
11	श्री इन्द्र जीत सिंह	कि गृह के बारे में 157609960 रुपये की मांग संख्या 3 में 1 रुपये की कटौती की जाये।
12	श्री नारायण सिंह	
डिमांड नं0 9		
5	श्री भाम ेर सिंह सुरजेवाला	कि ि ाक्षा के बारे में 544572990 रुपये की मांग सं0 9 में 1 रुपयै की कटौती की जाये।
6	श्री सुरेन्द्र सिंह	
डिमांड नं0 12		
7	श्री भाम ेर सिंह सुरजेवाला	कि श्रम तथा रोजगार के बारे में 28970470 रुपये की मांग सं0 12 में 1 रुपये की कटौती की जाये।
8	श्री सुरेन्द्र सिंह	

मानीय सदस्यों से मैं यह भी रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि समय चूंकि कम है इसलिए पांच छ मिनट तक ही अगर

माननीय सदस्य अपना भाशण सीमित रखें तो बहुत मेहरबानी होगी और ज्यादा मैम्बर साहेबान, बोल सकेंगे।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ): स्पीकर साहब,पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे सबसे पहले समय दिया। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं डिमांड नं0 2 पर बोलना चाहता हूं। आज जब हम एम0एल0एज0 होस्टल से विधान सभा की ओर से आ रहे थे तो रास्तें में कई लोगों से बात हुई। सब लोग बडे ताज्जुब में थे ओर आज यह बडी चर्चा का विशय बना हुआ है कि एम0एल0एज0 फ्लैटस के साथ ही पुलिस के टैंट लगे हुए हैं। आज से पहले कभी भी किसी प्रदे ा में ऐसी मि ाल मिल नहीं सकती कि प्रदे ा का मुख्य मंत्री जी अपनी बडी वि ाल कोठी को छोड कर प्रदे ा की भलाई के लिए खर्च कम करने के लिए सबसे पहले खुद कदम उठाए और एम0एल0एज0 फ्लैटस में छोटे से मकान में रहे। स्पीकर साहब, जिस तरीके से मंत्री लोग अपने खर्चे को कम करने के लिए एम0एल0एज0 फ्लैटस में आ रहे हैं यह बहुत बडा काम है। आर्थिक दृश्टि से चाहे इसका थोडा असर पडे लेकिन सबसे बडा असर इसका यह पडेगा कि अफसर साहेबान, भी अपने खर्च को कम करने के बारे में सोचेंगे। वे सोचेंगे कि मंत्रिगण जब अपने बडे मकान छोड कर एम0एल0एज0 फ्लैटस में आ रहे हैं और अपने टेलीफोन की एस0टी0डी0 कटा रहे हैं तो उन्हें भी अपने खर्च को कम करने के बारे में सोचना होगा। तमाम अफसर जो बहुत ज्यादा खर्च कर रहे

थे इस बारे में सोच रहे हैं और उनके दिमाग पर इस बात का बडा असर पड रहा है। वे यदि अपने खर्च को कम नहीं कर पाएंगे तो अपने आप भार्म महसूस करेंगे। स्पीकर साहब, मैं सरकार का ध्यान कारपोरे ान्ज की तरफ दिलाना चाहता हूं। जितनी भी हरियाणा के अन्दर कारपोरे ान्ज हैं, उनके अन्दर जिस तरीके से खर्च हो रहा है उसको कम करना होगा। आज हालत यह हैं मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि एक बोर्ड के बडे प्र ाासनिक अधिकारी ने अपने सामने जो मेज रखी जाती है वह 6 हजार रुपये की खरीदी है। यही नहीं 18 सौ रुपये की कुर्सी मंगवाई हैं, चार हजार रुपये का कारपैट मंगवाया है और 6 हजार के करीब रुपये पर्दों पर खर्च किए गए हैं। स्पीकर साहब, इस तरह के खर्चे अगर कम नहीं किए गए तो इस छोटे सये हरियाणा प्रदे ा में बडी मु कल होगी। (विघ्न) **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के नाजायज खर्चों पर रोक लगाई जाये। आज हालत यह हो गई है कि एक एक अफसर के ऊपर लाखों रुपये महीना खर्च हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि दिल्ली में हरियाणा भवन के ऊपर 6 लाख रुपये महीना खर्च हो रहा है। यह कोई मामूली रकम नहीं है। यह किन लोगों पर खर्च हो रहा है जो वैल सैटल्ड हैं जो हमारी स्टेट के बहुत बडे अफसरान हैं। आज हरियाणा भवन के अन्दर जब हम जाते हैं तो बडी मु कल से दो चार एम0एल0एज0 मिल पाएंगें हमारे अफसरान बहुत अच्दे हैं, बडे

ईमानदार हैं वे इस बात का बुरा न मनाएं लेकिन यह फैक्ट है कि आज यह हालत पैदा हो गई है कि बहुत सारे अफसरान अपने बीवी बच्चों कें साथ भानि–इतवार को कोई न कोई टूर प्रोग्राम बना कर वहां बैठे रहते हैं और एम0एल0एज0 को कमरा नहीं मिलता। पे कितना करते हैं केवल अढाई रुपये। जब तक इन खर्चों को कम नहीं किया जाएगा तक तक मुख्य मंत्री जी या मंत्रियों के खर्च कम करने से कोई फायदा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अगर कारों के खर्चे का हिसाब लगाया जाए तो एक एक अफसर की कार का बहुंत ज्यादा खर्च हैं इसलिए मेरा सरकार को यह सुझाव है कि इन कारों की बजाए अगर डीजल की बार या डीजल की जीप दे दी जाए तो खर्च कम हो सकता है। (विघ्न) चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी मैटाडोरे देनै की बात कह रहे हैं। यह बात भी ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे अफसर सैंट्रल गवर्नमैंट से बातचीत करने के लिए अकसर दिल्ली जाते रहते हैं। आठ आठ या दस दस अफसर अगर मैटाडोर में इकट्ठे चले जाएं या आ जाएं या डीलैक्स बस में सफर कर लें तो खर्च में बहुत कमी हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकारने यह बहुत बडा कदम उठाया है जो वजीरों ने अपने घरों के टेलीफोनों की एस0टी0डी0 कआ दी वरना एक एक मंत्री का एक एक साल का खर्चा डेढ डेढ लाख या दो दो लाख के करीब था। (विघ्न) ये मंत्री जी (सरदार लछमन सिंह जी की तरफ इ ाारा करते हुए) बडे गुस्से में बोल रहे हैं लेकिन

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा यह निवेदन है कि जिन मंत्रियों की यहां कोठियां हैं, जो उन्होंने किराये पर दे रखी हैं, हरियाणा सरकार की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें उन कोठियों को या तो खाली करवा लेना चाहिए या उनमें जो खाली कमरे पडें हैं उनमें सरकारी कोठी छोड कर रहना चाहिए। इसमें प्रदे ा की भलाई है। हाउस में जवाब देने से कोई बात नहीं बनती, बात तो प्रैक्टिकल रूप में काम करने से बनती है।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 9 पर थोडा सो बोलना चाहता हूं। यह ऐजुके ान के बारे में है। आज हरियाणा के अन्दर ऐजुके ान का बहुत बुरा हाल है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो मंत्री जी आज ट्रैजरी बैंचिज पर बैठे हुए हैं, वे कभी अपोजी ान में बैठा करते थे। डा0 मंगल सैन जी और चौधरी देवी लाल जी हमे ाा यही कहा करते थे कि तमाम लोगों को ि ाक्षा का समान अवसर मिले लेकिन आज सब को समान अवसर नहीं मिला रहा है। गांवों के अन्दर बच्चे बैठ नहीं सकते। अगर बैठने की जगह हो तौ उनके लिए कोई स्टेल का या डैस्कों का प्रबन्ध नहीं है। वे बेचारे टाट और जमीन पर बैठते हैं। उधर दूसरी तरफ बडे बडे पब्लिक स्कूल हैं उनमें बडे बडे व्यक्तियों के बच्चे पढते हैं। उन स्कूलों के मालिक लाखों रुपया हरियाणा से कमाते हैं। माननीय मंत्री जी ने उन लौगों को टैक्स से वंचित कर दिया है उन लोगों पर भी टैक्स लगना चाहिए था। वे गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। हमारे यहां हरियाणा में एक एक

इन्स्टीच्यू ान ऐसा है जिसके दाखिले के लिए पांच पांच और छः छः हजार रुपया देना पडता है और उसके मालिक उन गरीब बच्चों से लेते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, जब तक सरकार इन पब्लिक स्कूलों को बंद नहीं करेगी और आम आदमियों को ि ाक्षा का समान अवसर नहीं मिलेगा तक तक हरियाणा का भला नहीं हो सकता। जब तक एक आई0ए0एस0, चपडासी, क्लर्क, पंचायत मैम्बर और गरीब गांव के आदमी का लडका एक स्कूल में नहीं पढेगा तब तक दे ा का कल्याण नहीं हो सकतां इसलिए मेरी सरकार से गुजारि ा है कि इस काम को चौधरी देवी लाल जैसे ही नेता कर सकते हैं। अगर इन लोगों के हाथ में फिर हकूमत आ गई तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा।

मैं डिमांड नं0 12 पर भी बोलना चाहता हूं। आज हमारे हरियाणा प्रान्त में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है जिसको कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकतां नौकरी दिलाने के लिये मेरे पास श्री पोहलू राम जी भी आये थे कि इसको लगा दो। आज हालात यह है कि नौकरी पाने के लिये लडका अपनी मां और बहिनों के जेवर बेच कर और रि वत देकर नौकरी पाना चाहता है। इसलिये इन हालातों से बचाने के लिये उनके लिए कोई न कोई साधन जुटाने अत्यन्त आव यक हैं

डिप्टी स्पीकर साहब, जब तक पूरे तौर पर बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाती तब तक सरकार का यह फर्ज बन जाता है कि उन बेरोजगार लडकौं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। आज एक

तरफ तो हजारों की तादाद में जे0बी0टी0, बी0एड0 और ओवरसीयर ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं दूसरी तरफ दिन प्रति दिन बेरोजगारी बढ रही हैं अस्थल बोहर के अन्दर आयुर्वेदिक कालेज चल रहा है। वहां पर ट्रैनिंग में दाखिल होने के लिये छः छः और सात सात हजार रुपये चन्दे के रूप में देते हैं लेकिन जब वे कालेज से ट्रेनिंग करके निकलते हैं तो उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। कहीं पर वे वैद्य नहीं लगते। एम्पलायमैंट एक्सचेंज में जा कर नाम दर्ज करवाते हैं लेकिन वहां से भी उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है। इसलिये इन ट्रेनिगों पर सरकार को बैन लगाना चाहिये। जब तक सरकार बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं दे देती है तब तक उनको रूरल स्कीम के तहत बेरोजगारी भत्ता जरूर दिया जाना चाहिये। मैं डिमांड नं0 16 पर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सरकार ने स्माल स्केल और रूरल इन्डस्ट्रीज की स्कीम बनाई हैं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिये सरकार ने पग उठायें हैं। अगर इंडस्ट्रीज की तरफ पूरी गहराई से अध्ययन किया जाये तो डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत ही बुरी बात है, खाली हरियाणा प्रदे ा में ही नहीं सारे दे ा की बहुत बुरी हालत है। बडा उद्योगपति कोई एक करोड की इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको सरकार की तरफ से 90 लाख रुपये लोन दिया जाता है और उस पर दस लाख रुपया सबसिडी के तौर पर दे दिया जाता है लेकिन उद्योगपति का सारा कारखाना 80 लाख रुपये में लगता है। बताया जाता है कि 1 करोड में लगा है। सारा का सारा पैसा सरकार का लगता है। सरकार उन कारखानों को सस्ती

बिजली देती है। उनको चार पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है। यहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं उनको इस बात का पता होगा कि घरों के अंदर जो बिजली दी जाती है वह 35 पैसे यूनिट के हिसाब से या 33 पैसे के हिसाब से दी जाती है। इसी प्रकार से टयूबवैल्ज को भी बडी महंगी बिजली दी जा रही है। बडे व्यक्तियों को यानी इंडस्ट्रियलिस्टस को सस्ते दामों पर बिजली दी जाती है।

श्री उपाध्यक्षः आप जल्दी से वाइंड अप करें, औरों ने भी बोलना है।

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अभी दो मिनट में ही खत्म कर रहा हूं जो बडे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सस्ते ब्याज पर पैसा दिया जाता है। बडे उद्योगपतियों को तो और भी सुविधा सरकार ने पिछले साद दी है और पहले भी मिलती रही है। सरकार की तरफ से यहां पिछले साल बिल पे ा हुआ था उस समय उस बिल का काफी विरोध किया गया था लेकिन माननीय उद्योग मंत्री जी उसको पास करवाना चाहते थे और बाद में पास भी हुआ। उस बिल के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और दूसरे मंत्रियों ने यह बात कही थी कि आने वाले दिनों में इस बिल को विदड्रा कर लेंगें लेकिन आज तक वह विदड्रा नहीं हुआ। यह हरियाणा के लिये काला बिल था इससे बुरा बिल नहीं हो सकता कि बडे बडे लोगों को विदाउट इंट्रैस्ट लोन दिया जाता है और वह भी सैंट्रल सैल्ज टैक्स पे करने के

लिये। वे हरियाणा का भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और उन्हें सैंटर का सैल्ज टैक्स पे करने के लिये पैसा दिया जा रहा है।

बाबू मूल चन्द जी ने बजट पे ा करते हुए यहां कहा कि फरीदाबाद से अगर कोई फैक्टरी वाला अपने माल की ट्रांसफर करके हैड आफिस में दिल्ली ले जायेगा तो उस पर हरियाणा सरकार ट्रांसफर टैक्स लगायेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमे भुलावे की बात नहीं हो सकती कि इस माल पर हरियाणा सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। हरियाणा सरकार ने लगा भी दिया तो वे हाई कोर्ट के वैंकेट करवा लेंगे। उनको इस बात का पता होना चाहिये कि पिछले दिनों 15 मुख्य मंत्रियों ने सैंटर को यह लिख कर दिया है कि जो भी फैक्टरी हमारे प्रदे ा में है, उसको हैड आफिस दिल्ली में हो तो उस पर टैक्स लगना चाहिये क्योंकि वे बिना टैक्स दिये ही अपने माल की हैड आफिस दिल्ली में ट्रांसफर कर लेते हैं। जब कोई प्रदे ा जमीन देता है, बिजली देता है लेबर देता है तो वह टैक्स उसको मिलना चाहिये लेकिन जो हमारे वित्त मंत्री जी ने यह बार्डर पर टैक्स लगाया है कि जो कोई भी अपनी जिन्स बाहर ले जायेगा उसको टैक्स देना पडेगा। इसका मतलब यह हुआ है कि कोई जमीदार अपना गेहुं, ज्वार,चना या कोई दूसरी जिन्स दिल्ली की मंडी में ले जाता है तो उसको भी यह टैक्स पे करना पडेगा। अगर कोई जमींदार अपने माल को ले जाकर नरेले की मंडी में बेच देता था और दो पैसे ज्यादा ले लेता था वह भी खत्म हो गया। यह तो सारा टैक्स एग्रीकल्चर

गुडज पर लगा है इंडस्ट्रियल गुडज पर नहीं लगा। जब तक कांस्टीच्यू ान में अमैंडमैंट नहीं होती है तब तक हमारी असैम्बली उन फरीदाबाद के इंडस्ट्रियलस्टस पर टेक्स नहीं लगा सकती।

हिमाचल सरकार ने इस तरह से टैक्स लगाया थां वहां पर केस होई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है और वह हाई कोर्ट से कब वैकेट होगा इसका अभी पता नहीं है। आज तक हिमाचल गवर्नमैंट को उन इंडस्ट्रियलस्टस ने कोई भी टैक्स नहीं दिया है। इन भाब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

मास्टर ि ाव प्रसाद (अम्बाला भाहर): मैं डिमांड नम्बर नौ पर विचार रखना चाहता हूं। इसमें कोई भाक नहीं कि हरियाणा सरकार ने ि ाक्षा के फैलाव को सामने रखते हुए हर वर्श और पिछले वर्श भी हर कांस्टीच्यूएंसी में एक एक और दो दो स्कूलों को अपग्रेड किया है और नये स्कूलों को खोलने की योजना है लेकिन स्कूलों की बिल्डिंग बनाये जाने से ि ाक्षा का विस्तार नहीं हो पायेगा। हमारे यहां बहुत से स्कूल हैं जहां पर केवल एक ही टीचर है, जिनको हम सिंगल टीचर स्कूल कहते हैं। वहां पर पहली जमात से लेकर पांचवीं जमात तक के बच्चे हैं और उन सारी क्लासों को केवल एक टीचर पढाता है। यह ठीक है कि वहां पर विद्यार्थियों की संख्या चालीस या पचार होगी लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि एक टीचर पहली जमात से पांचवीं जमात तक विद्यार्थियों को कैसे पढा पाएगा। कम से कम ऐसी हालत में

बच्चे का तो विकास नहीं हो पायेगा। सरकार को इस तरफ सोचना चाहिये कि स्कूल में सिंगल टीचर की बजाए एक से अधिक टीचर रखे जाएं ताकि बच्चों पर कंट्रोल किया जा सके और ठीक तरह से ि ाक्षा दी जा सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी की यह सरकार आई है, हो सकता है पहले भी ऐसा ही होता हो लेकिन जो बात मेरे ध्यान में आई है वह यह है कि दो साल से मिनिस्टिरों को, एम0एल0एज0 को ट्रांसफर के सिवा और कोई काम नहीं हैं मैं समझता हूं कि जब तक ट्रांसफर की पालिसी के बारे में हमारी कोई ठोस पालिसी और ठोस कदम नहीं होंगे तब तक हमारी ि ाक्षा के ढांचे में भी कोई सुधार नहीं होगा। मेरे इस बारे में एक दो सुझाव हैं। पहला तो यह है कि जो टीचर्ज अपने घर के आसपास लगना चाहते हैं उनको प्रैफरैंस देकर लगा देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि ऐसी जगहों पर जहां पर टीचर्ज जाकर पढाना नहीं चाहते उन जगहों के लिये स्पै ाल अलाउंस दिया जाना चाहिये। जो टीचर्ज उन जगहों पर जाएं उनको स्पै ाल अलाउंस दिया जाए। जो टीचर्ज भाहरों में पढाते हैं उनका हाउस रैट खत्म कर दिया जाये और इसको खत्म करके जो पैसे की बचत हो उस पैसे को स्पै ाल अलाउंस के तौर पर रखा जाए और जो टीचर्ज उन जगहों पर जाने के लिये तेयार हों उनको वह पैसा स्पै ाल अलाउंस के तौर पर दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जो पुस्तकें बच्चों के लिये छापी जाती हैं वे उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती हैं। बहुत सी पुस्तकें तो ऐसी हैं जो चौथी और पांचवीं

कक्षा के बच्चों के लिये छापी जाती हैं लेकिन दसवीं क्लास या कालिज में पढने वाले विद्यार्थियों की समझ में नहीं आती हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो भी पुस्तकें छापी जाएं वे बच्चों के स्टैंडर्ड के मुताबिक छापी जानी चाहियें। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि जिस समय बी0एड0 या जे0बी0टी0 या दूसरे कोई और एडमि ान हों उनमें पोलिटीकल एप्रोच नहीं होनी चाहिये। इस एप्रोच को टोटली खत्म करना चाहिये। मैरिटस के आधार पर या जिन लोगों को इस क्षेत्र में काम करने में दिलचस्पी हो उन्हीं को एडमि ान के समय थोडा सा उत्साह बढा कर आगे लाना चाहिये। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि पोलिटीकल आधार पर या सिफारि ा के आधार पर ऐसे लोगों को एडमि ान मिल जाता है जिनकी इस क्षेत्र में कोई रूचि नहीं होती और वे लोग जब टीचर लग जाते हैं तो स्कूलों में भाराब के दौर और जुआ चलता रहता है। ऐसे लोग चरित्र के लिहाज से टीचर की पोस्ट के लिये बिल्कुल भी फिट नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा में बे ाक सडकें बन जाएं, इंडस्ट्रीज लग जाए और चाहे दूसरी तरक्की के काम हो जाएं लेकिन ि ाक्षा के क्षेत्र में जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिये अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उस तरक्की का उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिये। ि ाक्षा से ही दे ा आगे बढता है। यही कारण है कि आज चारों तरफ भ्रश्टाचार का माहौल है। आज कोई डाक्टर ईमानदार नहीं मिलता। आज कोई इंजीनियर ईमानदार नहीं मिलता। आज कहीं भी ईमानदार आदमी नहीं मिलता। इसका सबसे बडा कारण ऐजुके ान का ठीक न

मिलना है। यह ऐजुके ान का दोश है। यह देखा गया है कि बजट के अन्दर ऐजुके ान का प्रेफरैंस सबसे बाद में रखा जाता है। उसके लिये सब से कम पैसा रखा जाता है। मेरा कहनायह है कि बजट के अन्दर सब से ज्यादा पेसा ऐजुके ान के ऊपर रखना चाहिये। क्योंकि इसी के ऊपर दे ा का भविश्य निर्भर करता है। इस क्षेत्र में बिना लिहाज के बिना सिफारि ा के और बिना पोलिटीकल ऐप्रोच के सिलेक ान होनी चाहिये। इस क्षेत्र में काम करने वालों के सबसे ज्यादा बेजिज होने चाहिये। अगर सरकार ऐसा कर दे तो आप देखेंगे कि इस तरफ रूचि रखने वाले अच्छे लोग अपने आप आगे आएंगे। इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरियाणा में काफी स्कूल प्राईवेट हैं। यहां पर बोर्ड के भी स्कूल हैं। परीक्षाओं का जो परिणाम निकलता है, अगर उस परिणाम में से प्राईवेट स्कूलों के टीचरों का परिणाम निकाल दिया तो आप देखेंगे कि परिणाम क्या रहता है। गवर्नमैंट स्कूलों में एक बच्चें पर एक सौ बीस या पच्चीस रुपया खर्च किया जाता है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ज्यादा ध्यान सरकार को इन प्राईवेट स्कूलों की तरफ देना चाहिये। पिछले दिनों प्राईवेट स्कूलों के टीचर्ज हमारे मुख्य मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने अपनी सारी दिक्कतें उनके सामने रखी थीं और उन्होंने बताया था कि हम ज्यादा काम करते हैं लेकिन हमको कम वेजिज मिलते हैं। पहले यह कहा गया था कि कोठारी कमि ान की रिपोर्ट के मुताबिक प्राईवेट स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को भी सारी सहूलियतें दी जाएंगी।

आज हालत यह है कि प्राईवेट स्कूलों में छः सौ रुपये पर दस्तखत कराए जाते हैं और दिए जाते हैं केवल तीन सौ रुपए। तीन सौ पर दस्तखत कराए जाते हैं और दिए जाते हैं एक सौ पचास रुपए। इसी बीमारी को दूर करने का एक ही इलाज है कि उन टीचर्ज को वि वास दिलाया जाए कि इस बजट में ि ाक्षा के लिये बहुत अधिक पैसा रखा जाएगा औरउनकी तकलीफों को दूर करने के लिये कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। हमें अपनी तरफ से पूरी कोि ा ा करनी चाहिये कि प्राईवेट स्कूलों के टीचर्ज की तकलीफों को दूर करें और मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि जब वे जवाब दें तो मुक्ष्य मंत्री महोदय ने जो आ वासन दिया है उसको नि चत रूप से ध्यान में रख कर जवाब दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए डिमान्ड नम्बर तीन के बारे में दो तीन मिनट लेना चाहता हूं। यह डिमांड होम के बारे में है। इसमें कोई भाक नहीं है कि आज चारों तरफ ला एण्ड आर्डर की हालत बहुत खराब है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका कारण यह है कि एमरजैंसी के दौरान कांग्रेस के प्रधान और सैक्रेटेसरी जब पुलिस स्टे ान जाते थे तो वाहं प0र एय0एच0ओ0 से कहते थे कि फलां आदमी को गिरफ्तार कर लो। उस आदमी को बुलाया जाता था और उसको कहा जाता था कि क्या तुम जेल में जाना चाहते हो। अगर नहीं जाना चाहते हो तो इतना पैसा रि वत दो। फिर वह पैसा कांग्रेस का प्रधान, सैकेटरी और एस0एच0ओ0 आपस में मिलकर खाते थे। यह अच्छी बात है कि जनता पार्टी के लोग पुलिस स्टे ान में तो नहीं जाते हैं और न ही पैसा खाते

हैं। लेकिन पैसा खाने की पुलिस वालों को आदत पडी हुई है। हमारे अम्बाला में सट्टे और अफीम बेचने की बहुत बीमारी है। दस हजार रुपये तक अफीम का व्यापार रकने के लिये पुलिस को दिए जाते हैं। यही कारण है कि हमारे यहां अफीम की स्मगलिंग हो रही है। दिन दहाडे पुलिस स्टे ान से कौन आदमी आता है जिससे कि नाजायज अफीम पकड कर पैसा ले सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जब इस तरह का माहैल चारों तरफ हो और सिपाही तथ अफसरान साथ में बैठकर भाराब पीयें तो उन अफसरान की क्या इज्जत रहेगी ?

श्री उपाध्यक्षः अब आप खत्म करें आपका समय हो गया है।

मास्टर ि ाव प्रसादः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि ला एण्ड आर्डर की हालत को ठीक करने के लिये एक तो यह करना चाहिये कि डिपार्टमैंट प्रोमो ान होनी चाहिये। ऐसे लोगों को जो भाुरू से इस लाइन में निकल कर आते हैं उनको प्रोमोट करना चाहिये। बाहर से कम लोगों को डायरैक्ट अप्वायंटमैंट होनी चाहिये। इस तरह से किसी की भी प्रोमो ानल अप्वायंटमैंट हो तो किसी किस्म का प्रे ार, पोलिटीकल ऐप्रोच नहीं होनी चाहिए और अगर कोई आदमी कुरप ान करते हुए या रि वत लेते हुए पकडा जाए तो विधान सभा के किसी सदस्य को भी चाहे वह आदमी उस सदस्य का कितना ही नजदीकी हो या रि तेदार हो, चीफ मिनिस्टर साहब या मिनिस्टर को ऐप्रोच नहीं करना चाहिये। अगर

इस प्रकार की पोलिटीकल एप्रोच को खत्म कर दिया तो लॉ एण्ड आर्डर में सुधार हो सकता है।

इसके साथ ही साथ मैं डिमान्ड नम्बर एक और दो के बारे में कहना चाहता हूं। इस बारे में मेरा एक सुझाव है। हमने फैसला किया है कि देहात की डिवैलपमैंट होनी चाहिये। लेकिन मुझे देहात में एक दिक्कत नजर आई है कि वहां पर काम ज्यादा बढ गया है और स्टाफ कम है। मैं इस बारे में एक मिसाल देना चाहता हूं। गांव में पटवारी होताहै। गांव में चाहे काननूगो आ जाए तहसीलदार आ जाए या कोई और अफसर आ जाए, पटवारी को उनकी सेवा करनी पडती है। उसके पास काम इतना बढ गया है कि लेकिन पटवाघर कहीं भी नहीं है। उसके रवहने का उसके खाने का इंतजाम गांव को जो सरपंच होता है उसके घर में होता है। उसके कागज वगैरह भी सरपंच के घर में रखे रहते हैं। वह पटवारी सरपंच के कहने से कोई गलत काम भी कर सकता है। मैं समझता हूं कि आदमी की नेचर ऐसी होती है कि आबलीगे ान के तहत वह कोई भी काम कर सकता है। मुरा सुझाव है कि पटवार सर्किल के आधार पर एक ग्राम सचिवालय बना दिया जाए अगर पटवार सर्किल के आधार पर मुमकिन नहीं है तो काननूगो सर्किल पर एक सचिवालय खोद दिया जाए। जहां पर एक हफ्ते में बी0डी0ओक0 आए, ऐग्रीकल्चर इंस्पैक्टर आए, इंडस्टरी इंस्पैक्टर और लागों से उनकी कठिनाईयों के बारे में बातचीत करें और उनको दूर करें। लोग सरकार के पास न जाएं बल्कि सरकार वहां

पर पहुंचे और लोगों के साथ मिलकर बात करे और जनता को सहूलियतें पहुंचाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं .....

श्री उपाध्यक्षः मास्टर जी अब आप खत्म करें। आपका समय हो गया है।

मास्टर ि ाव प्रसादः उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। अब मैं अनएम्पलाएमैंट के बारे में कहना चाहता हूं ताकि अनएम्पलाएमैंट देर की जा सके। सरकार को थोडी से हिम्मत से काम लेना चाहिये। रिटायरमैंट की एज पचपन वर्श कर देनी चाहिये। पे नि ि चत कर देनी चाहिये कि इतने साल की सर्विस के बाद इस केडर में इतनी होगी। पत्नी और पति अगर दोनों नौकरी करते हैं तो एक को ही सर्विस में रखा जाना चाहिये। ऐसा करने से अनएम्पलाएमैंट दूर हो सकती है। इससे आगे में इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि देहात में इंडस्ट्रीज का बहुत बढावा हो राह है लेकिन अम्बाला और कुरुक्षेत्र को बिल्कुल वंचित कर दिया गया है। वहां पर सडकं भी अच्छी नहीं हैं और न ही पीने के लिये पानी है। अम्बाला भाहर बिल्कुल लाइन पर है लेकिन वहां पर पानी नहीं मिलता है। वहां की सडकें टूटी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिले पिछडे हुए घोशित कर देने चाहिये और वहां पर इंडस्ट्रीज को वही सहूलियतें देनी चाहिये जो एक पिछडे हुए इलाके को मिलती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के संबंध में कुछेक बातें कह कर खत्म करूंगा। इस समय ट्रांसपोर्ट की हालत इतनी ज्यादा नाकस और निकम्मी है कि इसके बारे में बयान भी नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक बस में बैठें तो आपको सब से पहले अपने कपडों का ध्यान रखना पडेगा क्योंकि तकरीबन बसें टूटी फूटी हैं, खिडकियों के भी ो टूट पडे हैं और हर लिहाज से बसें इतनी गंदी हैं कि आप उन में बैठ कर सफर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ दूसरी बात यह भी है कि मुसाफिरों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ड्राईवर स्टाप्स पर बसें खडी नहीं करते और सीधे ही भगा कर ले जाते हैं। मैं आपको एक बात अभी की बताता हूं कि मैंने बलदेव नगर कैम्प से चढना था औ मेरे साथ 13 सवारियां और थीं और वह बस वहां पर खडी नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस सरकारी बस के स्थान पर कोई प्राईवेट बस होती तो वह अव य वहां पर खडी करते और सभी सवारियां बिठा कर ले जाते तो आप ही देखें कि इस तरह करने से एक तो सरकार को कितनी हानि होती है और दूसरे मुसाफिरों को अलग से खराब होना पडता है। यह सब कुछ एक ड्राईवर की मर्जी पर होता है। वह जहां चाहे खडी करे जहां चाहे न करे। इसलिये मेरी सरकार से दर्खास्त है कि आप कृपया इस ओर वि ोशच ध्यान दें और खास तौर पर ड्राईवर्ज को यह हिदायतें दें कि जहां पर भी सवारी मिले, उसे अव य ले लिया जाये ताकि लोगों को भी कुछ सहूलियत हो जाए और सरकार को भी फायदा हो। उपाध्यक्ष

महोदय, इसके साथ साथ टैक्स बढाने का जहां तक सवाल है, इस सम्बंध में मेरा यह निवेदन है कि लोकल रूटस प0र कम से कम कुछ न कुछ सरकार की तरफ से रिलीफ दिया जाए सरकार इस ओर अव य ध्यान दे। इन भाब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

राव राम नारायण (साहलावास): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। ज्यादा न बोलता हुआ दो तीन डिमान्डज पर ही बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमारे मंत्रियों ने जो यह एलान किया है कि वे बडी कोठियां छोडकर फ्लैटस में आ रहे हैक्ं। मेरे विपचार में प्रैक्टिकली इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह तो एक दिखावा मात्र है यह कोई प्रैक्टिकेवल चीज नहीं है, उनको तो सैक्टर 7 और सैक्टर 16 में छोटी छोटी कोठियां खाली करवा के वहां पर जाना चाहिये। इन फलैटस में उनकी डिगनिटी भी कायम नहीं रहेगी और जो उनका कारोबार है, उसे भी वे पूरी तरह से नहीं कर पायेंगे ..... (हंसी)

आवाजें: राव साहब, यह कारोबार किस तरह का ? (हंसी एवं व्यवधान)

राव राम नारायणः उपाध्यक्ष महोदय, अगर असलियत में वे लोग इकोनौमी करना चाहते हैं तो अपनी तनख्वाहें बढा लें यूनियन मिनिस्टर साहब की तनख्वाह 3000 रुपये होती है लेकिन वे कार अपने घर की रखें, ड्राईवर अपना रखें, टैलीफोन अपना लगवा लें, प्राईवेट काल्ज कम करें और अगर सरकारी टैलीफोन बरतें तो प्राईवेट काल्ज का और दूसरी काल्ज का हिसाब किताब रखा जाए तब तो इकोनौमी हो सकती है। पर जब तक ये लोग सरकारी खर्च पर रहेंगे तब तक इकोनौमी नहीं हो सकती। इसके साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने वाकई इकोनौमी करनी है तो जो आपका टाप हैवी एडमिनिस्ट्रे ान है, उस पर भी कट लगनी चाहिये। हमारा हरियाणा जो है वह पहले के अम्बाला डिवीजन के बराबर है। जहां अब तीन आई0जी0 स्टेट में हैं, उनके स्थान पर एक ही आई0जी0 बहुत है। सात आठ डी0आईजी0 की बजाए दो या तीन डी0आई0जी0 बहुत हैं। इसी तरह से 10 कमि नर्ज की बजाये दो कमि नर्ज बहुत हैं, एफ 0सी0 1, चीफ सैक्रेटरी 1 और इसी तरह से कारपोरे ान और बोर्डों में जो बेतहा ाा एक्सपैंडीचर या अखराराजात है उसमें भी कमी होनी चाहिये। इसके साथ साथ एक बात एम0एल0एज0 साहेबान से कहूंगा कि वे अपनी चेयरमैन ाप अपने आप ही छोडकर लोगों का वि वास जीतें। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बडा अहम मसला है। मैं आपको बताता हूं कि लैंड एक्वीजी ान के बारे में आजकल बहुत बडी लिटीगे ान होती है। जिसकी जमीन एक्वायर की जाती है उसको

जब मुआवजा दिया जाता है तो पिछले पांच सालों की कीमतों की औसत निकाल कर दिया जाता है, इस वजहइ से लोग सै ान जहों के पास और हाई कोर्ट में अपीलें लेकर जाते हैं, जिस वजह से उनको काफी हैरानगी होती है और सरकार का भी बहुत खर्चा होता है क्योंकि सरकार को भी मुकद्दमा लडने के लिये सरकारी और गैर सरकारी वकील लगाने पडते हैं। आज हालत यह है कि आप किसी गांव में जाकर देख लें, उसके एक कोने पर जमीन का भाव एक रुपये गज है और दूसरे कोने पर 100 रुपये गज है। ऐसा होते हुए अगर पिछले पांच सालों की औसत निकाली जाती है तो यह लोगों के साथ बडा भारी अन्याय है। इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि जिसकी जमीन एक्वायर की जाए उसे मार्किट रेट पर पूरा मुआवजा दिया जाए ताकि वह भी परे ाानी से बचे और सरकार को भी फिजूल खर्ची न करनी पडे। लैंड एक्वीजी ान एक्ट का जो स्टैंडिंग आर्डर 28 है, उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पिछले पांच सालों की औसत निकाल कर मुआवजा दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में सवा छः एकड पर जो मालिया माफ किया गया है, उसके बारे में कहूंगा कि लोगों ने इसको काफी वैलकम किया है लेकिन इसको रै ानेलाईज कर देना चाहिए एक तरफ तो जैसे लोहोरू, नारनौल, महेन्द्रगढ और सैंडी एरियाज हैं और दूसरी तरफ जीन्दी, करनाल और अम्बाला का एरिया है, उसको अगर आप देखें तो आपको प्रोडक ान के

लिहाज से दोनों तरफ काफी फर्क दिखाई देगा। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि प्रोडक ान को ध्यान में रखते हुए जहां की प्रोडक ान कम है, वहां पर मालिया की ज्यादा माफी होनी चाहिये और जहां पर प्रोडक ान ज्यादा है वहां पर उसी हिसाब से मालिया लिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको लॉ एण्ड आर्डर की बात कहना चाहता हूं। पिछले दिनों बाबू जगजीवन राम जी, हमारे उप प्रधान मंत्री महोदय रोहतक में आये थे और वहां पर किसी कारणव ा हुल्लडबाजी हो गई, भाोर भाराबा हुआ और वहां पर जिला के सभी अफसर, डी0सी0, एस0पी0, डी0एस0प0ी0 (हैडक्वार्टर), एस0डी0एम0 वगैरह सभी मौजूद थे लेकिन इस हुल्लडबाजी के लिये एक एस0एच0ओ0 को दोशी ठहरा कर सस्पैंड कर दिया गया। बडे अफसरों को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया और इस प्रकार छोटे लोगों को स्केप गोट बनाया गया है जबकि इस मामले की सारी जिम्मेवारी बडे अफसरों की बनती थी।

चौधरी हर स्वरूप बूराः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मेरे लायक सीनीयर दोस्त ने अभी बताया कि उस एस0एच0ओ0 के साथ ज्यादती हुई है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि ज्यादती किसी पालिसी की वजह से हुई है या डिस्क्रिमिने ान की वजह से हुई है ?

राव राम नारायणः मैं इतना जानता हूं कि वह बेकसूर आदमी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक मोहनबाड़ी गांव है। वहां के एक मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई हैं आपको पता है आर्ट की जो चीजें हैं ये एक्सपोर्ट की जाती हैं। लेकिन पुलिस उस मूर्ति की आज तक बरामदगी नहीं कर सकी है। इसलिये मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह कोई खास इंतजाम करें कि वह मूर्ति हिन्दुस्तान से बाहर न जाने पाये। इसके अलावा पुलिस थानों में कुरप्ान अब पहले से ज्यादा हो गई है इसलिये इसकी रोकथाम के लिये भी कोई न कोई इंतजाम होना चाहिये। इसके अलावा जब से बिजली बोर्ड के दफ्तर के बारे में एलान हुआ है कि इसको हिसार ले जाया जा रहा है तथा और भी कुछ दफ्तरों को हिदायतें दी गई हैं कि वे जिला हैड क्वार्टर पर चले जाएं तब लोगों में यह भाक हो गया है कि हम चण्डीगढ़ पर अपना क्लेम रख भी रहे हैं या नहीं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फाजिल्का और अबोहर पर क्लेम के बारे में भी सरकार को अपनी स्टेटमैंट देनी चाहिये। इसके अलावा सवालों के जवाबों के दौरान में कर्मचारियों की एवरेज रिपोर्ट के बारे में डिस्कान होती रही है। ए0सी0आर0 में जो एवरेज रिपोर्ट लिखी जाती है वह नहीं लिखी जानी चाहिये। यह सबार्डिनेटस के साथ एक किस्म का धोखा हैं अगर एवरेज रिपोर्ट को एडवर्स रिमार्कस समझा जाता है तो यह रिमार्कस कर्मचारी को कम्युनिकेट होने चाहियें क्योंकि एडवर्स रिपोर्ट के लिये गवर्नमैंट की इंस्ट्रक्ान्ज हैं कि वह कर्मचारी को कम्पयुनिकेट होने चाहियें।

इसके बाद डिमांड नं0 9 एजुके ान के बारे मे हैं रोहतक के अंदर महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी कायम की गई है जिसके वाइस चांसलर चौ0 हरद्वारी लाल मुकर्रर किये गये हैं आपको यादा होगा कि उन्होनें इलैक ान के अन्दर एक हैंड बिल निकाला था उसमें उन्होंने कोई भी नहीं बख्शा। यहां तक कि चौधरी चरण सिंह जी को भी नहीं बख्शा। लेकिन उसके बावजूद भी उनको वाइस चांसलर लगा दिया। इसका मतलब यह है कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वह ठीक लिखा है। जब से वे रोहतक में गये हैं, वहां पर अमन नहीं है। इसलिये उनको जल्दी से वहां से हटाया जाये वरना रोहतक के अन्दर कभी भी अमन नहीं होगा। इसके बाद मैं इंडस्ट्रीज के बारे में थोडा सा कहना चाहता हूं। हमारी गवर्नमैंट का यह कदम बडा सराहनीय है कि वह रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज लगा रही है। लेकिन हमारे रूरल एरिया का जो क्लर्की कर सकता है। इसलिये इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट जब तक उसे पूरी तरह से एनक्रजमैंट नहीं देगा यानी उसको रुपये पैसे की पूरी सहूलियत नहीं दी जायेगी तब तक वह इस तरफ कामयाब नहीं हो सकेगा। इसके बाद मैं डिमांड नं0 23 जो ट्रांसपोर्ट के बारे में है कुछ कहना चाहूंगा। हमारे यहां देहात के अन्दर जो बसिज चल रही हैं वह बडी टूटी फूटी हैं और उनमें ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा रहती है। हमारी माताएं, बहिनें और बेटियां जब बसों में सफर करती हैं तो उनको पांव टिकाने को भी जगह नहीं मिलती। इसलिये में चाहता हूं कि बसों में ओवर क्राउडिंग

कम होनी चाहिये। इन भाब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के तहत लगभग 133 करोड रुपये की मांगें आज सदन के सामने रखी गई हैं। इन मांगों पर चर्चा करने का तरीका तो यह होना चाहिये था कि एक एक मद पर आंकडे दिखा कर उसे सदन के सामने रखा जाता है कि कौन सी मद पर पैसा ज्यादा रखा गया है और कौन सी मद पर कम पैसा रखा गया है और वह पैसा कौन से काम के लिये रखा गया है लेकिन मुझे दुख है कि ऐसा नहीं किया गया है और फिर इन डिमांडज पर चर्चा करने के लिये समय भी बहुत कम नि चत किया गया है। इतने समय में हम लोग आंकडों को छू तक भी नहीं सकते क्योंकि विभिन्न मांगों के अन्तर्गत उनकी अनेक मदें हैं। अब सबसे पहले मैं मांग संख्या 2 को ले रही हूं किजसमें 60714070 रुपये की मांग सामान्य प्र ाासन के तहत रखी गई है। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि पिछले दो सालों से देखा जा रहा है कि प्र ाासनिक अधिकारियों के तबादले निरन्तर किये जा रहे हैं। सैंकडों बार प्र ाासनिक सचिवों के विभाग बदले गये, कारपोरे ान्ज के मैनेजिंग डायरैक्टरर्ज बदले गये। जब बार बार प्र ाासनिक अधिकारी को बदला जाता है या सचिव को बदला जाता है तो प्र ाासन चलाने में बहुत बाधा आती है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री महोदय जी से गुजारि ा करना चाहती हूं क्योंकि

पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की सदस्या होने के नाते मेरा तजर्बा है कि इस तरह से जल्दी जल्दी तबादलै करने से दो बातों का असर पडता है। पहले तो यह कि सचिव अपने विभाग का काम जाकर समझ भी नहीं पाता कि उसे बदल दिया जाता है। अगर हम यह समझें कि आई0ए0एस0 अफ्सर हर जगह योग्यता से काम कर सकते हैं तो यह हमारी भूल है। किसी आई0ए0एस0 अफ्सर के लिये यह तो संभव है कि वह पहले 6 महीने जाकर वहां का काम समझे और अगले दो वर्श में वह अपनी योग्यता का प्रद र्न करे। लेकिन चूंकि इनको जल्दी से ही बदल दिया जाता है इसलिये काम सुचारू ढंग से नहीं चल पाता। हमने पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी में देखा है कि जब हम किसी काम की जिम्मेदारी फिक्स करना चाहते हैं और किसी अफसर से पूछते हैं कि तो वह कह देमता है कि मुझे तो पता नहीं यह फैसला तो मेरे से पहले अफसर ने लिया है और मैंने तो सिर्फ अमल किया है। अगर पहले अफसर से पूछते हैं तो वह कह देता है कि मैंने तो फैसला कर दिया था लेकिन मेरे से बाद वाले अफसर ने इसको अमल में लिया है। तो इस प्रकार से किसी अफ सर पर जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जा सकती है। अगर इनती जल्दी उसे बदल दिया जाता है तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। प्र ाासन में प्र ाासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स करने के लिये यह जरूरी है कि हम उसे कम से कम तीन वर्श के लिये एक एक विभाग में रखें। हां, अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जरूर

बदलना पड जोय तो अलग बात है वरना उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिये जिसमें वह अपनी योग्यता प्रदर्शित कर सकें।

16.00 बजे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं0 3 में गृह विभाग से संबंधि तळ पर कुछ कहना चाहती हूं कि मुझे खेद है कि गृह मंत्री जी उठ कर चले गये हैं लेकिन मुख्य मंत्री महोदय तो बैठे हैं। (विघ्न) गृह विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है इसके ऊपर ही सारे प्रदेश की कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं होगा कि मेरी इस बात से अपोजीशन के भाई खुश होंगे परन्तु यह पिछले तीस बरस से पुलिस को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि आज की पुलिस देशवासियों के लिये रक्षक होने की बजाये भाोशक हो गई हैं होना तो यह चाहिये कि एक पुलिस अधिकारी के सामने यहां एक भारीफ आदमी को पनाह मिलनी चाहिय परन्तु यहां यह होता है कि उसको तो खराब किया जाता है और गैर सावमाजिक तत्व के दिलों में पुलिस से दहशत होनी चाहिये लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता है। इस सारे के लिए सरकार जिम्मेदार है। मगर भारीफ आदमी थाने की सीढियां चढते हुए भी कांपता है और गैर सामाजि तत्व हैं वे पुलिस से मिलकर रंगरंलियां मनाते हैं। उनको कोई दहशत नहीं है। पुलिस अधिकारियों के लिये एक राश्ट्रीय आयोग पिछले दिनों बैठाया गया था उसकी सहायता के लिये एक अध्ययन मंडल नियुक्त किया गया था। मैं उसके सामने पेश हुई थी। मैंने

उनको समझाया कि आज के समय के अनुसार सरकार को पुलिस की ट्रेनिंग बदलनी होगी। कितनी कुर्बानियां देकर हमने आजादी हासिल की है। इस आजाद भात में उनको बताना होगा कि लोगों के नागरिक अधिकारन क्या क्या हैं ? पहले पुलिस टैरर के लिये दह ात के लिये रखी जाती थी। भाांतिप्रद आंदोंलन अगर होता है तो उसके साथ भी वह सही बर्ताव नहीं करेगी इसलिये यह जरूरी है कि पुलिस विभाग की ट्रेनिंग इस प्रकार की होनी चाहिये कि एक भारीफ आदमी को यह महसूस हो कि यह मेरा पनाहगार है और एक गैर सामाजित तत्व यह समझै कि यह एक दह ात है जो मुझे बख्भोगा नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी के साथ साथ न मालूम किन कारणों से पुलिस की तफती ा में बहुत लोग आडे आते हैं और पुलिस की तफती ा को कहीं न कहीं रोक दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर वाकया बताती हूं। 20 फरवरी 1979 को गोछी गांव रोहतक में बैरी के नजदीक राजवन्ती नाम की 13—14 साल की लडकी जो अपने खेतों को जा रही थी कुछ लोगों ने उसको पकड लिया और उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसके बाचद उसको कत्ल कर दिया गया। जब उसके मां बाप ने कुछ झगडा करना चाहता तो उन लोग्रों ने ला ा को उसके मां बाप को सौंपने की बजाये जला दिया। उसके मां बाप इस मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए पता नही रिपोर्ट लिखी गई या नहीं। अभी तक कोई तफती ा भी इस मामले में नहीं की गई। आज भी उसके मां बाप सुरक्षा के लिए पुकार रहे हैं। उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि इस तरह के भयभीत परिवारों को हमें सुरक्षचा प्रदान करनी चाहिये।

डिमांड नं0 9 ि ाक्षा के बारे में है, मैं आगे भी गाहे बे गोह कहती रही हूं। एक दो बातें मैं और कहना चाहूंगी कि पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में यह हो गया है कि जो भी सरकार कर्मचारी 20 वर्श की नौकरी के बाद ऐच्छिक रिटायरमैंट लेनाच चाहता हो उसके दे देते हैं जबकि हरियाणा में यह नौकरी 25 बरस की होनी चाहिए ऐसा है। मैं कहूंगी कि इसको 20 वर्श कर दिया जाये इससे सरकार को कोई फर्क पडने वाला नहीं है बल्कि इससे सरकार को आर्थिक तौर पर फायदा हो जायेगा। इससे पैं ान भी कम हो जायेगी। 5–10 वर्श पहले अगर कोई रिटायरमैंट लेना चाहता है तो उसको लेने दी जाये इससे और वेकैन्सीज होंगीं मैं कहूंगी कि इस अवधि को घटाकर 25 की बजाये 20 वर्श कर दिया जायें

अब मैं मैडीकल अलाउंस के बारे में कहना चाहूंगी। यह एक्चुअली जो दिया जाता है इससे देहाती भाईयों को कोई फायदा नहीं होता इससे भाहरी ि ाक्षक ही फायदा उठाते हैं इसका फलैट रेट कर दिया जाये ताकि सब को फायदा हो। देहाती भाईयों को जो सुविधा अब तक नहीं मिलती रही है वह भी मिल जायेगी।

अब मैं डिमांड नं0 12 श्रम और रोजगार के बारे में कहना चाहूंगी। औद्योगिक प्रगति के लिए इस क्षेत्र में भाांति बहुत जरूरी है और उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि मजदूर वर्ग में भाांति हो। आप मजदूरों के सत्याग्रह और आन्दोल को वापिस ले लेने से ही भाांति न समझ बैंठे। अगर आप मजदूर की जबान बंद करके ही, सत्याग्रह का अधिकार वापिस लेकर ही भाांति लाना चाहते हैं। तो मैं इसकी मुखालफत करूंगी। वह मरघट की भाांति होगी या कब्रिस्तान की भाांति होगी। मालिक और मजदूर के दोनों के आपसी सहयोग से ही भाांति कायम हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों सदन में गुड ईयर फैक्टरी के बारे में राजेन्द्र सिंह जी के सवाल के जवाब में हमारे श्रम मंत्री जी ने तसल्ली दी थी कि सात दिन के अन्दर इसको खुलवा दिया जायेगा। मुझे पता चला है कि लाक आउट हटा दिया गया है। तालाबंदी हट जाने से वह फैक्टरी नहीं खुलेगीं फैक्टरी केवल तालाबंदी खुलवाने से नहीं खुलेगी। जब तक वहां पर मजदूरों की मांगों पर जिन पर हडताल हुई थी और फिर जब तक 11 मजदूर जिनको एम्पलायर निकाल रहा है उनको आप अन्दर नहीं भेजेंगे तक तक फैक्टरी की तालाबंदी खोलने का कोई फायदा नहीं है। जब तक उनकी मोंगे पूरी नहीं होंगी वे काम पर ही नहीं जायेंगे और बाहर ही बैठे रहेंगे। उनके साथ साथ और भी मजदूर बाहर ही रहेंगे, कोई काम पर नहीं जायेगा। यह तालाबंदी तो तब तक रहेगी जब तक वे काम पर नहीं आते। केवल फैक्टरी खोल देने से तालाबंदी नहीं हट जाती। मैंने पहले भी कहा था कि यह हमारे

हिन्दुस्तान को कन्सर्न नहीं है अमेरिका की कन्सर्न हैं अब तक 132 करोड रुपया वे हमारे यहां से ले जा चुके हैं। यहां पर मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही हैं यह देखते हुए मैं श्रम मंत्री जी से कहूंगी कि यह तालाबंदी अच्छी नहीं है। मजदूरों के हक हथियाये जा रहे हैं।

मंत्री महोदय ने उसका जवाब देते हुए कहा कि मालिको को मजबूरी से तालाबंदी करनी पडी। माननीय मंत्री महोदय द्वारा असैम्बली के फ्लोर पर इस तरह की स्टेटमैंट देने से मजदूरों के हौंसल पस्त हो जाते हैं और मालिक मनमर्जी करते हैं। इसी प्रकार की मालिकों द्वारा ज्यादतिजयां करने से ही आज ट्रेड यूनियन्ज पनप रही है। मंत्री महोदय का ख्याल है कि पब्लिक सैक्टरों में ट्रेड यूनियन्ज पनप नहीं रही हैं। पब्लिक सैक्टरों में भी आपको मालूम है रेलवे और पी0एंड0 टी0 जो सबसे बडे पब्लिक सैक्टर हैं वहां पर भी बडी ट्रेड यूनियन्ज हैं। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि पब्लिक सैक्टर में ट्रेड यूनियन्ज पनपने नहीं देंगे। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि वे उन्हें पनपने दें। पब्लिक सैक्टर में सही आद र्ज्ञग रखें ताकि प्राईवेट फैक्ट्रियों में भी ट्रैड यूनियन्ज आगे बढ सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद में डिमांड नं0 23 जो ट्रांसपोर्ट महकमे के बारेम में है इसके बारे में केवल एक ही बात कहना चाहती हूं। यह जो 86 हजार रुपए ट्रांसपोर्ट के लिए रखे गए हैं, मैं यह नहीं कहूंगी कि इतने ज्यादा क्यों रखे गये हैं। मैं इसकी नुक्ताचीनी नहीं करती। भाायद

ज्यादा इसलिए रखे गये हों कि जहां पर बस स्टैंड नही हैं, वहां पर बस स्टैंड बनाए जाने हों। लेकिन मैं यह बात चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब के नोटिस में लाना चाहती हूं और इससे पहले भी यह बात उनके नोटिस में लीा चुकी हूं कि अम्बाला का जो बस स्टेंड है, बह बहुत छोटा है। वह इतना छोटा है कि बसों को बिल्कुल सडक पर आकर के ही खडा होना पडता है। यह 86 हजार रुपया बहुत कम है। इसलिए मैं चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब से अर्ज करती हूं कि अम्बाला कैंट के के बस स्टैंड को बडा करने के लिए चाहे अभी कुछ पैसे और रखें चाहे अनुपूरक अनुमानों द्वारा उन्हें इसके लिए मांग लानी पडे लेकिन अम्बाला के बस स्टैंड को बडा बनाया जाये क्योंकि जी0टी0 रोड पर यही एक बस अड्डा है जाहं पर हर बस जरूर रूकती है। इन भाब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ मांग न0 2 और 3 पर ही बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि जो आम आदमी हैं, उसको सबसे पहले तो अपना जायज हक मिलना चाहिए। जैसे यदि कोई कम्पीटी ान हो, उसमें भी उसको बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर हर एक चीज में उसको बराबर समझैंगे तो उसे बराबर तौर पर हम मिलेगा। अगर किसी काबिल आदमी को अपना हक नहीं मिलता है तो वह यह समझता है कि मरे साथ दुभात हो रही है

और लोग यह कह सकते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रे ान फेल हो गई है। (विघ्न) इसके बारे में थोडी देर पहले बहन सुशमा जी ने कहा था इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं ट्रांस्फर्ज के बारे में कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्टस के अन्दर मास्टर से ले करके बडे से बडे अफसरों तक के एक साल में चार चार बार ट्रांसफर होते हैं और जो बडे बडे अफसरान हैं जैसे आई0ए0एस0 और एच0सी0एस0 हैं उनके भी तबादले होते हैं। यह तबादले क्यों होते हैं ? इसके बारे में मैं तो यह समझता हूं कि वह अफसर पोलिटिकली बातों के लिए फिट नहीं होता इसलिए उसका तबादला कर दिया जाता है। अगर वह वहां पर भी सूट नहीं करता तो उसको वहां से भी बदल दिया जाता है। इसलिए यह जो आई0ए0एस0 अफसर हैं इनको कम से कम कुछ साल के लिये तो एक जगह पर रहने दिया जाये वैसे तो यह जो वजीर साहेबान हैं, उनको भी पता नहीं कि आज मेरे पास कौन सा महकमा है और कल को कौन सा होगा लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो तबादले होते हैं यह सिर्फ अफसरों को डिमारेलाइज करने के लिए होते हैं। यह आजकल ही नहीं बल्कि यह उनके साथ तब तक होते रहेंगे जब तक वह सर्विस में रहेंगे। अगर उनके ऊपर पोलीटिकल प्रै ार पडत है तो वह डिमारेलाइज होकर यह सोचेगाच कि अगर दूसरी सरकार भी आ गई तो वह भी उसको अपना ठीक तरह से काम नहीं करने रदेगी। डिप्टी

स्पीकर साहब, मेरी समझ में तो यह नहीं आता है कि सरकार किसी तरीके से यह ट्रांस्फर्ज करती हैं। जहां तक मैं सोचता हूं कि यह सरकार यही सोच रही है कि तीन साल हम काम और कर लें फिर तो हमारे सिर से यह बला टल जाएगी। इससे आगे जो सरकार आएगी यह बला उसके सिर आ जाएगी वह खुद संभाल लेंगी। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जो अफसरान हैं, उनके द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है। जैसे चन्दा इकट्ठा किया जाता है यह बहुत गलत काम है। यह काम गलत क्यों है इसलिए है कि जो अफसर लोगों से पेसे लगता है अगर उस अफसर से कोई आदमी यह कह दें कि मेरा यह काम कर दें तो वह किस मुंह से कह देगा कि मैं आपको काम नहीं कर सकता चाहे वह काम गलत भी क्यों ने हो। वह काम उस अफसर को करना पडेगा। यह एक किस्म की कुरप्ान ही है। इससे अफसर का जो मोरल स्टैंडर्ड है वह एक तरह से गिर जाता है। तो मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं कि आप इन अफसरों को काम करने दीजिए। उसके साथ यह नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर पोलिटिकली प्रै ार डाल करके उनसे कोई काम करवाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो समझता हूं कि जो अफसर हैं वही सरकार का काम चलाते हैं अगर उन अफसरों को इधर उधर कर दिया जाता है तो पार्टी तो 5 साल के अंदर आ करके चली जाती है लेकिन यह अफसर तो रिटायर होने तक सर्विस में रहते हैं। इसालिये यदि सरकार के काम इन अफसरों के ऊपर ही निर्भर हैं तो उनको ठीक काम करने दीजिए। हाउस के अंदर एक बात

और सुनने में आई कि जो अफसर कुरप्ट हैं उनको तबादला के देना चाहिए। मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत हूं कि जो अफसर कुरप्ट हैं उसका तबादला कर देना चाहिए लेकिन तबादल कर देने से उसकी कुरप ान तो नहीं हट जायेगीं यदि वह ऐसा गलत काम करता है वह काम करना बंद तो नहीं कर देगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इनके लिए लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर कोई अफसर या कोई पोलिटीि ायन कुरप्ट हैं तो उसको लोकपाल के सामने पे ा किया जाना चाहिए। वह परमानैंट होना चाहिए कोई भी सरकार उसे हटा न सके। इस तरह से इस कुरप ान के अंदर सुधार आ सकेगा। काफी दिन से हरियाणा के अंदर कुरप ान का सिलसिलाच चला आ रहा है। सबसे पहले हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह लोकपाल और लोकायुक्त मुकर्रर करें। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं एक बात बोर्ड के बारे में कहूंगा। जैसे पब्लिक सर्विस कमी ान या सबार्डीनेट सर्विस सलैक ान बोर्ड हैं। इनके अंदर न तो किसी पोलिटीकल आदमी की सिफारि ा होनी चाहिए और न ही इनके द्वारा सर्विस लगवाने के लिए किसी आदमी की सिफारि ा करनी चाहिए। थोडे दिन पहले ही इसके बारै में एक सवाल आया था, मेरे ख्याल से वह सवाल नम्बर 882 था। उसके जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था कि जब लोगों को एम्पलायमैंट दी जाती है तो यह भी कंसीडर किया जाता है कि किसी पोलिटिकल आदमी ने या किसी एम0एल0ए0 ने सिफारि ा की है। (विघ्न) इन्होंने खुद ही यह

माना है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इन भाब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री भाम ोर सिंह (नरवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं0 2 और 16 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। डिमांड नं0 2 जो कि सामान्य प्र ाासन के बारे में है, उसके अंदर 6 करोड से ज्यादा रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारी स्टेट में बावजूद इस बात के कि जनता पार्टी का यह फैसला था कि वह हाउस की स्टैंथ का 10 परसैंट से ज्यादा मंत्री नहीं बनाएंगे। इन्होनें 9 की बजाय 16 मंत्री बनाए और इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रे ान के ऊपर मंत्रिमंडल का ग्रुप जो है, वह मुकम्मल नहीं है और पूरा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उसका कारण यह है कि जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनमें आपस में कोलीजन या तालमेल नहीं हैं (विघ्न) जो मंत्री हैं वह क्रौस परपसिज पर काम करते हैं जिसकी वजह से जो मंत्रिमंडल का नक ाा है वह आम लोगों की नजरों में बहुत अच्छा बहुत सुन्दर और साफ नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): क्या आप दो चार मिसालें दे सकते हैं ?

श्री भाम ोर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडी के ठीक तौर पर ग्रिप न होने के कारण जैसा कि श्रीमती सुशमा स्वराज ने कहा है मैं इनकी बात नहीं दोहराऊंगा सिर्फ इतना ही कहना

चाहूंगा कि डेढ दो साल मंत्रिमंडल बने हुए हो गया है।इन डेढ दो सालों में कई बार ओथ टेकिंग सैरेमनीज हुई हैं और कोई दो दर्जन बार महकमे बदले जा चुके हैं सिवाये इरीगे ान एंड पावर महकमे के, कोई दूसरा ऐसा महकमा नहीं है जो कई बार बदला न गया हों। यहां तक कि फाइनांस डिपार्टमैंट जैसा महत्वपूर्ण महकमा चार दफा बदला जा चुका है। चार मुख्तलिफ मंत्रियों के पास यह महकमा रह चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक इमेज ठीक न होने का दूसरा कारण है एडमिनिस्ट्रे ान में कोलिजन का न होना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है एडमिनिस्ट्रे ान सैक्रेट्री से लेकर नीचे छोटे से छोटे अफसर तक सरकारी अफसरों को न सिर्फ उनको ट्रांस्फर किया गया बल्कि सियासी मदाखलत की बिनां पर बडभ फ्रीक्वेंटली ट्रांस्फर की गई। बावजूद इस फैसले के कि मुख्य मंत्री साल में एक बार ट्रांसफर करेंगे, उनको बिना वजह सियासी मदाालत के आधार पर ट्रांस्फर किया गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नरवाना के नायब तहसीलदार को दो महीने पहले इसलिए बदला गया कि उन्होंने जनता पार्टी के लीडर के कहने पर गलत गिरदावरी नहीं की। हाउस के सारे मैम्बरान इस बात को जानते हैं कि सियासी मदाखलत की बिना पर बे ाुमार सरकारी कर्मचारियों को ट्रांस्फर किया जाता है। पिछले दिनों हाउस में बताया गया था कि कहीं कहीं पर एक पोस्ट के ऊपर कई कई ट्रांस्फर आर्डर्ज कर दिए गए।

चौधरी राम कि ानः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है इन्होंने कहा कि जनता पार्टी के लीडर की वजह से ट्रांसफर किया गया। क्या ये उस लीडर का नाम बतायेंगे जिसकी वजह से नायब तहसीलदार का तबादला हुआ था ?

श्री भाम ोर सिंहः नाम तो मुत्री जी बता देंगे जब वे बोलेंगें मैं कह रहा था कि एक एक पोस्ट पर कई कई आफिसरों को तबदील कर दिया गया इसके दूसरी तरफ कई ऐसी पोस्टें थी जो लगातार खाली पडी रही, लेकिन उन पर कोई ट्रांसफर नहीं की गई। इन कारणों की वजह से मिनिस्ट्री का, मंत्रिमंडल का एडमिनिस्ट्रे ान पर पूरा ग्रिप नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं जिसको हरियाणा के सारे लोग और सारे एम0एल0एज0 महसूस करते हैं। हमारे सबसे बडे दफतर सिविल सैक्रेटेरियट से लेकर जिला, सब डिवीजन और तहसील लैवर तक तिजने दफतर हैं इनमें आम आदमी के काम आसानी से नहीं होते। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी कर्मचारी की नुक्ताचीनी नहीं करता लेकिन आम आदमी का यह ख्याल है कि ये दफतर इनके अपने लिए बने हुए हैं खुद के लिय बने हुए हैं। दफतरों में लौगों के किसी काम में रूकावट भले ही पड जाए किसी आदमी का काम बगर किसी सिफारि ा के बगैर किसी रि वत के और बगैर पोलीटीकल एप्रोच से होने वाला नहीं हैं (व्यवधान) छोटे दफतर से लेकर बडे दफतर तक किसी के मन में यह इच्छा नहीं कि आम आदमी के काम किए जाएं। उलटा हर स्तर पर इस बात का पूरा

पूरा ध्यान रखतें हैं कि किसी का काम बन कर न चला जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि सैक्रेटेरियट स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक सरकारी खर्चे लगातार बढते जा रहे हैं। करोडों रुपये के फिजूल खर्चे इस सासल क्रिएट किए गए हैं, फिजूल प्रोवीजन किये गये हैं, उन खर्चों को बचाया जा सकता है क्योंकि ये खर्चे सो ाल तौर पर, सामाजिक तौर पर अनुचित हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सैक्रेटेरियट की कंटीन के लिए सरकार ने 1 लाख रुपये की सबसिडी रखी है। हरियाणा भवन दिल्ली और एम0एल0एज0 होस्टल की कंटीन के बारे में खर्चे का जिक्र भी हाउस में आ चुका है। इनमें सियासी आदमी हों, चाहे सरकारी आफिसर हों, खाना खाते हैं और ठहरते हैं।.....

चौधरी लाल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चौधरी भाम ोर जी जो वकालत कर रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछली जो सरकार थी जो लीडर हुए हैं उन्होंने कितनी कितनी कुरप ान की हैं, क्या मैं उनकी लिस्ट पढ दूं ?

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि सरकारी आफिसर और सियासी लीडर जो वहां ठहरते हैं उनके खाने और चाय वगैरा देने के लिए गवर्नमैंट ने सबसिडी देने का प्रावधान किया है लेकिन इसके दूसरी तरफ एक बहुत बडा कंट्रास्ट है जो मैं बताना चाहता हूं। हरियाणा के जितने भी बस स्टैंड हैं, उन में खाना और चाय के लिए दुकानें खुली हुई

हैं। इन दुकानों की मारफत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट काफी पैसा कमाता है। हर कंटीन हर साल बोली पर दी जाती है। नतीजा यह होता है कि उन कंटीनों में जो चीजें बिकती हैं वे बाजार के भाव के मुकाबले में डेढ गनुी दो गुनी भाव पर बिकती है।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, ...

श्री भाम ोर सिंहः आप यदि और भी कुछ कहना चाहते हैं तो वह भी कह लें। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बस स्टैंडज पर जो कंटीनें हैं उन में रद्दी और खराब चीजें मिलती हैं और बाजार से बहुत महंगी होती हैं। जन साधारण लोग गरीब लोग जो बसों के सफर करते हैं बस का किराया देतें हैं उनको तो गन्दी और महंगी चीजें और दूसरी तरफ सरकारी आफिसरों की कंटीनों की हालत सुधारने के लिए सबसिडी पर खर्चा किया जाए, यह बडे भारी कंट्रास्ट की बात हैं बहुत बुरी बात है। सरकारी अफसरों को यह फैसिलिटी बंन करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कारें या कोई भी व्हीकल जो सरकारी आफिसर यूज करते हैं, सबडिविीजन लैवल से लेकर सैक्रेटेरियट लैवल तक जो कार आफिसर यूज करते हैं इनके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं जब तक सरकार इंडीविजुअल तौर पर दी हुई व्हीकल की फैसिलिटी बंद न करेगी तब तक कारों का मिसयूज बंद नहीं होगा। इनकी जगह एक स्टाफ कार होनी चाहिए चाहे चण्डीगढ़ की बात है चाहे जिला स्तर की बात है चाहे सब

डिवीजन की बात है हर जगह स्टाफ कार होनी चाहिए। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान पदासनी हुए।)** जिस आफिसर ने टूर पर जाना हो वह अपनी जस्टिफिके ान लिख कर भेज और उसकी जस्टिफिके ान की अरजैंसी को देखते हुए स्टाफ कार प्रोवाइड की जाए। आपको अच्छी तरह पता है ये कारें प्राईवेट काम करने के लिए हैं, चाहे बाजार में जाना हो, चाहे कहीं परचेंजिंग करने के लिए जाना हो चाहे आफिसर की फैमिली ने सिनेमा देखने जाना हो चाहे दौरे पर जाना हो। इंडिविजुअल तौर पर जो कारें दी हुई हैं इनका परसनल कामों के लिए यूज कररके मिसयूज होता है। मैं समझता हूं कि आफिसर्ज को नीचे से ऊपर तक जो कारें दी हुई हैं, 24 घंटे यूज करने के लिए दे रखी हैं यह सब खर्चे की आईटमें हैं। इन कारों को वापस लेकर खर्चा घटाना चाहिए इसके इलावा दफतरों में एयर कंडी ानर और हीटर भी खर्चे की आईटम्ज हैं। यहां पर इतनी सर्दी नहीं पडती कि किसी से बर्दा त न हो और न ही इतनी गर्मी पडती है कि आदमी काम ही न कर सके। इस प्रांत के लाखों करोडों आदमी बिना एयर कंडी ानर और हीटर के काम करते हैं इसलिए सरकार अगर खर्चे में कमी करना चाहती है तो एयर कंडी ानर्ज या डीटर्ज दफतरों से भी और रैजिडैंन्सिज से भी खत्म करने चाहिएं।

चेयरमैन साहब, 1977 में जब देवी लाल जी सरकार बनी तो इन्होंने कोई आधाी दर्जन के करीब एडवाइजर्ज मुख्तलिफ

स्फीयर्ज में एडवाईस लेने के लिए रखे लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हाउस में जब बात उठी और लोगों ने भी जब इसके विरूद्ध आवाज उठाई तो 99 परसैंट एडवाइज्र्ज की इन्होनें छुट्टी कर दी। लेकिन आज भी दो ऐस एडवाइज्र्ज मौजूद हैं। एक एडवाइजर विजिलैंस के हैं जिसके बारे में हाउस में बडी चर्चा हुई हैं इस विजिलैंस कमेटी के ऊपर लाखों रुपयों का खर्च हैं जबकि इसका कोई काम नहीं है। चौधरी साहब ने हाउस में एक बात कही थी कि पोलिटीकल आदमियों और एम0एल0एज0 आदि की गतिविधियों को पता करना जरूरी है। इस बात के लिए तो इनके पास आलरेडी सी0आईडी0 और विजिलैंस के महकमे हैं। .....

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, ऐसा है कि जब तक माननीय सदस्य के पास इस बात का प्रूप न हो कि वे प्राईवेट काम करते हैं तक तक हाउस में ऐसी बात नही कहनी चाहिए।

श्री भाम ोर सिंहः ..... (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, जो भाख्स हाउस में जवाब न दे सके, उसका नाम लेना यहां मुनासिब नहीं है। इसलिए इस बारे में इन्होंने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री सभापतिः यह पो ार्न एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री भाम ोर सिंहः .....

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): चेयरमैन साहब, अगर सरकार के खिलाफ ये कोई बात कहना चाहते हैं तो ये कोई सबस्टांटिव मो ान लाएं उसको एडमिट कराएं और फिर हाउस में ऐलीगे ांज लगाएं। हम उसको मुंह तोड जवाब देंगे।

श्री भाम ोर सिंहः .....

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि इन दोनों आदमियों का जिनका मैंने जिक्र किया है, कोई औचितय नहीं है।

इसके बाद डिमांड नं0 16 के बारे में भी चेयरमैन साहब, थोडा सा मैं कहना चाहूंगा। पिछले कुछ महीनों से हाउस के अंदर भी और बाहर भी डा0 मंगल सैन जी ने जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब हैं और दूसरे मंत्रियों ने भी बहुत बढा चढा कर एक प्रौपेगैंडा माउंट किया है। जो बिल्कुल झूझा है। रूरल इंडस्ट्रिलाइजे ान की बात बहुत थोथी बात है। इसमें कोई सच नहीं है। इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। डा0 मंगल सैन जी ने मेरे ही एक सवाल के जवाब में जो आंकडे दिए हैं वह मैं हाउस के सामने पढना चाहता हूं। एक तरफ तो ये क्लेम करते हैं कि दो लाख के करीब पढे लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाया है और इतने यूनिट कायम कर दिए हैं लेकिन मेरे सवाल नं0 1032 के जवाब में इन्होंने जो आंकडे दिए हैं वे मैं हाउस को बताना चाहता हूं। मेरा प्र न था –

"(a) the number of units registered under Rural Industrialisation programme in the Stat from 1st January to 31st December 1978,

(b) the number of persons actually employed/benefited under the said scheme during the above period;

(c) the amount of loan/subsidy advanced by the Govt. to such units durinig the above period ... "

इसके जवाब में इन्हौंने ये फिगर्ज दी हैं –

(a) Number of units registered 498.

(b) Number of personas actually employed/benefited 1286.

(c) Amonth of loan granted Rs. 378400/-

यानि 1286 आदमियों को 498 यूनिटस के लिए लगभग पौने चार लाख रुपये का लोन दिया है। इतना छोटा सा पाल्टरी सम देकर डा0 मेगल सैन जी क्लेम करते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया है। इसके अलावा लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का जहां तक ताल्लुक है इसके बारे में इसी सवाल का एक पार्ट यह था –

"(e) the amount of loan advanced/subsidy given to large and medium sclae units by Govt. or other Government agencies during the above period ?"

इसके बारे में इनका जवाब है –

(e) (i) subsidy –Nil

(ii) Loan advnced Rs. 8724000/-

कहने का मतलब यह है कि रूरल इंडिस्ट्रिलाइजे ान के तहत इन्हौंने 378420 रुपये दिए और लार्ज स्केल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए 8724000 रुपये दिए। (विघ्न) यह एक साल की फिगर्ज हैं। चेयरमैन साहब, मैं इस संबंध में दो स्पैसिफिक इंस्टांसिज भी इनको देना चाहता हूं। उनको बिल्कुल कर्जा नहीं मिला। जींद जिले में इसी महीने 13–3–79 को हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब श्री प्रीत सिंह राठी जी ने मैंसर्ज राधास्वामी आयल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज गुरथली तहसील नरवाना को यह सर्टिफिकेट दिया कि तुमको लोन मिल चुका है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या ? उसको बैंक के मैनेजर ने लोन देने से इंकार कर दिया।

चौधरी राजेन्द्र सिंहः चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है सुरजेवाला जी बोलते बोलते परे ाान हो गए हैं और घबरा भी गए हैं क्योंकि ये चेयर को प्रौपरली ऐड्रैस भी नहीं कर रहे हैं। ये आपको उपाध्यक्ष महोदय, कह रहे हैं इसलिये अब आप इन्हें बैठने के लिए कहें (विघ्न)

श्री भाम ोर सिंहः सौरी। चेयरमैन साहब, मैसर्ज राधास्वामी आयल एंड काटन इंडस्ट्रीज वाले जब बैंक मैनेजर के पास एग तो वहां के एक आढती के मकान की रजिस्ट्री उनके पास थी लेकिन बैंक मैनेजर ने उस रजिस्ट्री को प्लैज करने से इंकार कर दिया। उसके बाद वे अपनी जमीन की रजिस्ट्री और बीमे का

सर्टिफिकेट लेकर गए लेकिन तब भी बैंक मैनेजर ने लोन देने से इंकार कर दिया। बावजूद इसके कि उसके पास मंत्री महोदय द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट था उसको लोन नहीं मिल सका। चेयरमैन साहब, ग्रामोद्योग के लिए लोन दिए जाने के बारे में इन्होंने जो इंस्ट्रक ान्ज जारी की है उसमें यह लिखा है कि लोन बिना किसी जमानत के या बिना कुछ प्लैज किए दिया जाएगा। लेकिन इस केस में हालांकि उसने जमानत भी दी तब भी लोन नहीं मिला।

चेयरमैन साहब, इसी तरह का एक केस और है। वह एक साल पुराना है। वह हरियाणा कंटेनर्ज इंडस्ट्रीज बरवाला का है। उन्होंने एक लाख सत्तर हजार रुपये के कर्जे के लिए अक्तूबर 1978 में ऐप्लाई किया था। तमाम फार्मेलटीज पूरी कर ली गई थीं। इंस्पैक ान भी हो चुका है लेकिन आज तक उन्हें लोन नहीं मिला। चेयरमैन साहब, ऐसे केवल दो उदाहरण ही नहीं हैं, इस तरह के सैंकडों उदाहरण मौजूद हैं। इस बात के बावजूद कि जलसों में लोगों को सर्टिफिकेटस दिए गए उन्हें कोई कर्जा नहीं मिला हैं जहां तक रोजगार देने का सवाल है मैं फिर इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हें कि यह स्कीम एक झूठा प्रचार है। किसी पढे लिखे बेरोजगार लडके को कोई सबस्टांि ायल कर्जा मिला ही नहीं है और न ही कोई यूनिट मिला है। इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वह इन सारी बातों को जरा गौर से देखे।

चौधरी राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ): चेयरमैन साहब, डिमांड नं0 2 पर बोले हुए मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रे ान का संबंध है, आज सारे दे ा में किसी प्रदे ा के अंदर सबसे अच्छा और बढिया जनरल एडमिनिस्ट्रे ान अगर कहीं है, तो वह हरियाणा प्रदे ा के अंदर है। इसके लिए मैं सरकार की प्र ांसा करते हुए इसे बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं पर कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे मुख्य मंत्री जी या अन्य मंत्रियों के नोटिस में नहीं आतीं। उन अप्रिय घटनाओं की वजह से हमारे सारे एडमिनिस्ट्रे ान की जो तस्वरी है वह भद्दी हो जाती है। हमारे फरीदाबाद कंपलैक्स के अंदर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इसके संबंध में मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक अभी घटी अप्रिय घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां बाद ाह खान हस्पताल बहुत पुराना हस्पताल है। उसके अंदर एक सज्जन और अच्छे तजुर्बेकार हैं डा0 भक्त। वहां डाक्टर्ज के अंदर कुछ इनफाइटिंग सी है और वे चाहते हैं कि डा0 भगत को वहां से तबदील कर दिया जाए। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है। डा0 भगत जब हस्पताल में डयूटी पर थे तो एक सज्जन ने फर्जी बिलों पर उनसे हस्ताक्षर कराने चाहे। जब डा0 भगत ने ऐसा करने से इंकार कर दिया तो उनकी बडी मार पिटाई की गई। हस्पताल के बाहर पकड कर निकाल दिया और उनकी कार के भी ो तोडे गये। उनके कपडे फाड दिये गये। इसलिए मैं आदरणीय हैल्थ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा और पहले भी निवेदन कर

चुका हूं और बडे दु:ख के साथ कहना पडता है कि जिन लोगों ने डा0 भगत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जाने चाहिएं।

दूसरी बात यह है कि फरीदाबाद कम्पलैक्स के अंदर लेबर प्रोबलम दिन प्रति दिन बढती जा रही है। मैंने इस संबंध में पहले भी सदन के सम्मुख अपने विचार रखे थे। चौधरी भजन लाल जी ने इस विभाग को संभालने के प चात लेबरर्ज की प्रोब्लम को हल करने के लिए काफी कदम उठाये हैं और अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। गुड ईयर फैक्टरी को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने काफी प्रयत्न किया है। अभी पिछले दिनों में मैं भी वहां पर था वहां के वर्कर्ज ने बताया है कि वह भीघ्र ही चालू होने जा रही है। मैं सब लेबरर्ज की ओर से चौधरी भजन लाल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस फैक्टरी को खुलवाने में मदद की है। वहां पर भी 1500 के करीब वर्कर्ज काम करते हैं। वहां पर तीस ऐसे एम्पलाइज हैं जो रैगूलर हैं वहां पर एक यूनियन है जो उन तीस वर्कर्ज को फैक्टरी में नहीं आने देती है। मैंने डी0सी0 साहब को और एस0पी0 साहब को भी कहा था कि अगर इस समस्या का हल नहीं किया गया तो यह विकराल रूप धारण कर लेगी और सारे क्षेत्र में लेबर की प्रोब्लम एक समस्या बन जायेगी।

सभापति महोदय जी अब मैं डिमांड नं0 9 के संबंध में कुछ अर्ज करना चाहूंगा। अभी तक सरकार ने ि ाक्षा के बारे में

कोई ठोस पग नहीं उठाये हैं और न ही अभी तक अध्यापकों का जो फर्ज होना चाहिए वे उन्हें निभा पा रहे हैं। मैं ि ाक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ि ाक्षकों के ट्रांसफर की एक पालिसी बना ली जानी चाहिए। बार बार बिना किसी बात के ही तबादले कर दिये जाते हैं जिसके कारण बडी भारी दिक्कत बच्चों को भी और टीचर्ज को भी होती है। आने वाले समय में अध्यापकों के लिए एक पालिसी बनाई जायें जिससे एम0एल0एज0 का पीछा छूट जाये। अगर किसी एम0एल0ए0 के कमरे में बीस आदमी बैठे हें। तो अधिकतर अध्यापकों के ट्रांसफर रूकवाने वाले या करवाने वाले होंगे। इसलिए परमानैंट तौर पर कोई पालिसी अख्तियार करनी चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि कई अध्यापकों के साथ बडी हैरासमैंट होती है वह भी बंद होनी चाहिये ताकि वह बच्चों को ठीक प्रकार से ि ाक्षा दे सकें।

जहां तक डिमांड नं0 12 का सवाल है यह लेबर एंड एम्पलाएमैंट के बारे में हैं। मैं इस बारे में लेबर एंड एम्पलाएमैंट मिनिस्टर साहब से निवेदन कयंगा कि जो भी कुरप्ट अफसर हैं उनको बदला जाये और एडमिनिस्ट्रे ान को ठीक चलाया जाये। लेबर की समस्या तब तक नहीं सुलझेगी जब तक आपका उन पर डायरैक्ट कंट्रोल नहीं होगा। मैं यह भी कहूंगा कि महीने में दो विजिट मिनिस्टर साहब फरीदाबाद के अव य करें ताकि जो वहां के लेबर लीडर हैं, वहां की दिक्कतें आपके नोटिस में ला सकें।

मैं आपके जरिए सरकार से एक और निवेदन यह भी करूंगा कि फरीदाबाद की जनरल एडमिनिस्ट्रे ान की समस्या का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है कि फरीदाबाद को जिला घोशित किया जाये। जब भी कोई मंत्री या मुख्य मंत्री महोदय जो इस क्षेत्र में जाते हैं सारे क्षेत्र के निवासियों की यही मांग होती है कि फरीदाबाद को जिला घोशित किया जाये और उनकी यह मांग न्यायासंगल भी है। जब तक उसाके जिला नहीं बनाया जायेगा तब तक वहां का एडमिनिस्ट्रे ान ठीक नहीं हो सकेगा।

हमारा पलवल और बल्लभगढ का एरिया हैं वहां के रहने वाले को अगर गुडगांव कै जिला स्तर के अफसरों को सम्पर्क स्थापित करना पडे तो बडी दिक्कत का सामना करना पडता है। पहले हमें बल्लभगढ से फरीदाबाद, फरीदाबाद से बदरपुर और बदरपुर से दिल्ली जाना पडता है। फिर दिली से वाया महरौली गुडगांवा पहंचना पडता है। अगर हमें डी0यी0 और एस0पी0 से मिलने जाना हो तो सारे का सारा दिन खराब हो जाता है। इसलिए फरीदाबाद को जिला घोशित किया जाये।

जहां तक डिमांड नं0 23 का सवाल है उसके बारे में भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारी ट्रांसपोर्ट की स्थिति आज बहुत खराब है। बिगडी हुई चीज का सुधार करने में समय लगता है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि डिस्ट्रिक्टस लैवल पर वर्क ाापों में मैकेनिक भर्ती करके बसों को बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाये ताकि ठीक से सर्विस हो सके।

श्री भागी राम (एलनाबादी –अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं आपको भाुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया। मैं मांग नं0 2, 3 और 16 पर अपने विचार रखना चाहता हैं। पहले मैं सामान्य प्र ाासन की डिमांड नं0 2 पर अर्ज करना चाहता हूं। चौधरी संत कंवर जी ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब कुछ मंत्री महोदय अपनी कोठी छोड कर एम0एल0एज0 फलैटस में आने का फैसला कर चुके हैं। या आ ही गये हैं। इस बारे में संत कंवर जी ने कहा कि बहुत बढिया काम किया है। यह काम मेरी समझ के मुताबिक बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। एम0एल0ए0 फलैट एम0एल0एज0 के लिए बने हैं अगर वहां पर मुख्य मंत्री महोदय आ गये तो वे कहां जायेंगे। हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के पास से, पंजाब से या दुनिया के बडे बडे लीडर आते हैं। उनको कोई न कोई छोटा मोटा काम करवाना होता है इसलिए वहां पर कई बार तो दो सौा या चार सौ तक आदमी इकट्ठे जो जाते हैं मेरी समझ में जो यह फैसला किया गया है वह बिलकुल गलत किया है। ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था। यह फैसला जल्दी में कर दिया गया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर दोबारा विचार करके इस फैसले को वापिस लेना चाहिए और मंत्रियों को अपनी कोठियों में रहना चाहिए। यह तो ठीक है कि बडी कोठियों की बजाए छोटी कोठियों में रह लें। कोठियां बदलने का मेन मकसद यह था कि खर्चा कम हो। चेयरमैन साहब, देहात में कहावत है कि अगर मुर्दे के बाल काट दिए जाएं तो मुर्दा हल्का नहीं होता। कोठियां

छोडने से कोई खर्च में कमी नहीं होती। सरकार को तो इन अफसरों का खर्चा कम करना चाहिए। मैंने बडे बडे अफसरों को दखा है कि अगर बाजार से एक नींबू भी लाना हो तो जीप एक नींबू लेने जाती है। नींबू की कीमत सिर्फ पंद्रह पैस होती है और उस जीप में तेल पांच दस रुपए का पडता हैं इस तरह की और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेने के लिए बाजार में डिपार्टमैंट की जीप या कार जाती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अफसरों के इस तरह के जो खर्च हैं, उनकी तरफ ध्यान देकर कम कराने चाहिएं। चेयरमैन साहब, बडी बार की बजाए छोटी कार लेने से भी खर्च में कोई कमी आने वाली नहीं है।

अब मैं आपका ध्यान डिस्ट्रिक्ट सिरसा की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर हरियाणा और राजस्थान का बोर्डर लगता है। बोर्डर पर तलवारा एक गांव पडता है। वहां पर पानी की एक झील बनी हुई है। वहा ंपर नाजायज पिस्तौलें बनती हैं बंदूकें बनती हैं और वहां पर देसी भाराब निकलती है। वहां पर तीन चार बार छापे मारे गऐ हैं और तीन चार सौ सिपाही मौके पर भी गए लेकिन वहां पर कोई सामान नहीं पकडा गया। खाली ड्रम मिले, खाली बर्तन मिले और कुछ नहीं मिला। वे लोग सामान को इधर उधर कर देते हैं। वे लोग काफी बदमा ा हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि डैढ महीना हुआ उस वक्त छापा मारा गया था लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। वे लोग पुलिस के काबू में नहीं आते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई

है। मेरी राय है कि वहां पर एक पुलिस चौकी बिठा दी जाए जिससे कि वे लोग चोरी छिपे भाराब वगैरा न निकाल सकें। अब मैं उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार की उद्योगौं के बारे में नीति है वह सराहनीय है। इससे हरिजनों को काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसमें थोडी सी कमी है जो मैंने महसूस की है वह मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। हमारी सरकार की नीति है कि दो तीन या चार आदमी पार्टनरि ाप बनाएं और काम भ्रुरू करें। अभी पिछले दिनों सिरसा में ग्रिवेन्सिज कमेटी की मीटिंग हुई और उसमे जिला जनता पार्टी के प्रधान ने बताया कि ऐसे मामले हैं कि किसी आदमी ने अपनी पार्टनरि ाप बनाई जिसमें पहले तो एक आदमी को पार्टनर बना लिया लेकिन बाद में कहा गया कि उसको हम हिस्सा नहीं देते। हमने तो उसको कर्जा लेने के लिए हिस्सेदार बनाया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरह के जो केसिज जैं उनको खत्म करना चाहिए और जो लोग इस तरह की हेराफेरी करके इंडस्ट्रीज कायम कर रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नं0 9 के ऊपर थोडा सा कहना चाहता हूं जो कि ि ाक्षा के बारे में है। मैंने इसके बारे में पहले क्वै चन किया था और मंत्री महोदय ने जवाब दिया था .....

चौधरी गंगा रामः चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं ि ाक्षा के बारे में यह बताना चाहता हूं कि फ्लड के कारण गांवों में स्कूलों की बिल्डिंगें गिर गई हैं और अब बच्चों

को पढाने के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार कहती है कि गांव वाले नई बिल्डिंग बनाकर दें। चेयरमैन साहब, गावं वालों ने पहले ही लाखों रुपए खर्च कर बिल्डिंगे बनाई थीं और अब फिर सरकार कहती है कि दुबारा बिल्डिंग बनाकर दो। गांव वाले बनाने में लाचार हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को बिल्डिंगे खुद बनानी चाहिएं।

श्री सभापतिः आप अपनी बात उस वक्त कह लेना जब आपकी बोलने की बारी हो।

श्री भागी रामः चेयरमैन साहब, मैं ि ाक्षा के बारे में बता रहा था कि मंत्री महोदय ने मेरे एक सवाल के जवाब में यह बताया था कि रोहतक में इतने हाई स्कूल हैं और सिरसा में इतने हाई स्कूल हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि सिरसा ि ाक्षा के क्षेत्र में जितना पीछे है उसके हिसाब से वहां पर कम से कम पच्चीस स्कूल और खोल जाने चाहिएं।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नं0 23 के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने बसों में कुरप्ान को दूर करने के लिए एक छापामार दस्ता कायम किया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरह के कई दस्ते बनाये जाने चाहिएं जिससे कि जो ड्राईवर और कंडक्टर मिल जुल कर टिकट नहीं काटते या सवारियां टिकट नहीं लेती उसमें भी सुधार हो सके।

श्री दीप चन्द भाटिया (फरीदाबाद): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नं0 2 के बारे में बोलने से पहले अपने चीफ मिनिस्टर साहब और दूसरे मिनिस्टर साहेबान को मुबारिकवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकारी खर्च को कम करने का फैसला किया है। मैं दो दिान यहां नहीं आ सकता था क्योंकि मेरे एक रि तेदार की डैथ हो गई थी और मैं वहां चला गया था। यह जो फैसला किया गया था कि चीफ मिनिस्टर साहब और दूसरे मिनिस्टर साहब फ्लैटों में आ रहे हैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जनता पार्टी के सदस्य और मिनिस्टर साहब कांग्रेस के मिनिस्टर साहब जैसे नहीं हैं इनमें और उनमें बहुत डिफरैंस है। चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले इस भाुभ काम का मुहुर्त किया है। इसके लिए मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूं और मुझे आ ाा है कि दूसरे मंत्री महोदय भी ऐसा ही करेंगे। चेयरमैन साहब, इसके साि साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री बडी कारों को छोड कर छोटी फियट कारों को प्रयोग करें।

17.00 बजे।

जिनका कि पैट्रोल वगैरह का खर्चा कम होता है। साथ ही मैं अपने बडे बडे अफसरों को भी यह रिकवैस्ट करूंगा कि जिस प्रकार हामर मंत्री और दूसरे लोग खर्चे में किफायत कर रहे हैं, उसी प्रकार से वे भी अपने खर्चों में कमी करने का प्रयत्न करें। उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आजकल पैट्रोल कितना महंगा हो गया है। अफसरों के पास सरकारी कारें

होती हैं। अतः उनको भी चाहिये कि जितनी बचत वे सरकार के धन की कर सकें, करें। मुझे उन सबसे यह पूर्ण आ ाा है कि वे मेरी इन बातों की तरफ अव य ध्यान देंगे। उनकी इस किफायत का असर लोगों पर भी पडेगा और वे भी उनके ऐसे पग को सराहनीय बताएंगे और जो गरीब आदमी बसों में सफर करते हैं उनके दिल में भी इस जनता सरकार के लिये सहानुभूति होगी।

चेयरमैन साहब, अब मैं फरीदाबाद टाउनि ाप के बारेम में कुछ कहना चाहता हूं जहां से पहले 40 परसैंट के करीब सरकार को आमदनी होती थी और अब वहीं से सरकार को 8 करोड रुपये की आमदनी होने जा रही है। यह जो 8 करोड रुपये की आमदनी है यह सरमायेदारों पर इंडस्ट्रियलिटस पर टैक्स के कारण हो रही है यह बिलकुल ठीक है कि सरमायेदारों से यह टैक्स अव य लिया जाना चाहिये। फरीदाबाद जो है यह बाबा फरीद की नगरी है यहां से 8 करोड रुपये की आमदनी सरकार को होगी और दूसरी तरफ हमारे मिनिस्टर साहेबान और बडे बडे अफसर साहेबान अगर अपनी तरफ से किफायत की पूरी कोि ा ा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस प्रकार से कम से कम सरकारी की आमदनी दुगुनी होकर 16 करोड तो अव य हो जाएगी। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यह इलाका पहले रेतीला इलाक था और यहां की आबादी सिर्फ 25 हजार की ही थी और फ्रंटीयर के लोगों ने आकर इसी डिवैल्पमैंट की और अब वहां की आबादी लाखों में हो गई है अतः मैं अपनी हैल्थ मिनिस्टर साहब से

निवेदन करूंगा कि वहां पर एक बडा हस्पताल होना चाहिये ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और लोगों को इलाज वगैरह के लिये हर तरह की सहूलियतें मिल सकें।

चेयरमैन साहब, अब मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एमरजैंसी के टाईम में जो हजारों लोग झुग्गी झोंपडियां वाले बरबाद कर दिये गये थे और यह सारा काम पिछली सरकार के टाईम में इन्दिरा गांधी के टाईम में किया गया था उन लोगों को अब सरकार की तरफ से प्लाट दिये जाने चाहियें या फिर उन 12 हजार लोगों की सरकार की तरफ से मकान बनाकर दिये जाने चाहियें। इसके साथ साथ ही सरकार की तरफ से उन गरीब लोगों के बच्चों के लिये ि ाक्षा का भी पूरा प्रबन्ध किया जाना चाहिये। और उन गरीब मजदूर भाइयों के बच्चों का हर लिहाज से ख्याल किया जाना चाहिये।

चेयरमैन साहब, फरीदाबाद टाउनि ाप जो है वहां पर गंदगी बहुत है। मच्छरों की बुरी तरह से भरमार है। बेचारे मजदूर गरीब लोग सारा दिन काम करके आते हैं। रात को जब वे सोते हैं तो उनको मच्छरों को सामना करना पडता है जिसके कारण कई किस्म की बीमारियां उन लोगों को लग जाती हैं। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ भी पूरा पूरा ध्यान देकर वहां पर सफाई वगैरह का प्रबंध किया जाना चाहिये। जब बरसात का मौसम हो जाता है तो वहां पर इनता बुरा हाल हो जाता है कि लोग अपने घरों तक भी नहीं पहुंच पाते।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन साहब, यह किस डिमांड पर बोल रहे हैं ?

श्री दीप चन्द भाटियाः चेयरमैन साहब, मैं डिमांड न0 2 पर बोल रहा हूं। मैं किसी पर इस बात का इलजाम नहीं लगा रहा, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि गरीब लोगों की सहूलियत के लिये हर तरह से ध्यान रखा जाए ताकि आम लोगौं का जनता पार्टी पर वि वास और पक्का हो जाए।

अब मैं डिमांड नं0 23 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। हमारे मिनिस्टर साहब को और चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब को इस ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि बसों की हालत दिन व रात खराब होती जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि जब चण्डीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो क्या देखा जाता है कि दिल्ली के लिये तो कई बसें हमारी मिल जाती हैं पर जब दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जाना होता है तो सिवाये डी0टी0सी0 के और दूसरी कोई बस दिखाई नहीं देती है। हमारे हरियाणा की बसें तो उस तरफ बहुत ही कम चलती हैं, और जो थोडी बहुत चलती भी हैं, उनकी हालत बहुत खसता है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि एक तो बसों कें सुधार किया जाए और दूसरा अपनी स्टेट की आमदनी बढाने के लिये दिल्ली से फरीदाबाद के लिये हरियाणा की और बसें चलाई जाएं ताकि स्टेट का रैवेन्यू बढे और लोगों को भी आने जाने में सुविधा हो। यह जो फरीदाबाद कम्पलैक्स है यह चण्डीगढ़ से भी बढा हे इसके अंदर 50 के करीब

सैक्टर हैं। यहां पर लोकल बसों का भी इंतजाम होना चाहिये गरीब आदमियों को इधर उधर जाना होता है तो एक स्कूटर वाला उनसे कम से कम 5 रुपये झाड लेता है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर लोकल बसों का ज्यादा इंतजाम किया जाए। वहां पर टैक्सी वगैरह तो बिलकुल ही नहीं मिलती। अगर लोकल बसों का सरकार की तरफ से इंतजाम कर दिया जायेगा तो गरीब किसान मजदूर जो हैं उनको काफी राहत मिलेगी। सरकार इस ओर ध्यान देगी, मुझे पूर्ण आ ाा है।

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो पहले चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब थे उन्होंने यह वि वास दिलाया था कि हम फरीदाबाद को लोकल बसें भी देंगे और लोगों की तरफ हम खास तवज्जोह देंगे। मैं अपनी सरकार को यह बताना चाहता हूं कि यह जो फरीदाबाद है यह मिनी इंडया है, वहां पर कन्याकुमारी से लेकर क मीर तक के लोग रहते हैं। इसलिये इस जगह की तरफ अगर खास ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल में यह सारे हिन्दुस्तान में सबसे बढिया जगह होगी, इसका नाम ऊंचा होगा, इसकी तरफ खास ध्यान दिया जाए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन साहब, अभी भाटिया साहब ने कहा कि फरीदाबाद में कन्याकुमारी से लेकर का मीर तक के लोग रहते हैं लेकिन ये पे ाावर के लोगों को भूल गये हैं .....

श्री दीप चन्द भाटियाः चेयरमैन साहब, यह भूलते हैं मैंने तो पहले ही यह कहा कि फ्रन्टीयर के लोगों ने आकर वहां पर आबादी को बढाया है सबसे पहले वे लोग वहां पर आकर बसे हैं।

श्री सभापतिः भाटिया जी, अब आप वाइंड आप करिय, आपको बोलते हुए काफी टाईम हो गया है।

श्री दीप चन्द भाटियाः बस जी मैं थोडा सा ही बोल कर खत्म करता हूं सरकार ने जो सवा छः एकड पर मालिया माफ कर दिया है इसके लिए मैं अपनी सरकार को मुबारिकबाचद देता हूं मैं तो यह चाहता हूं कि यह सवा छः की बजाये 10 एकड पर मालिया माफ होना चाहिये जिससे कि हमारे गरीब भाई खु ा हो जाएं। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो पैसेन्जर्ज के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया है वह भी नहीं होना चाहिये बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जितने भी सरकार ने टैक्स लगाये हैं उन सब की पूर्ति अगर टैक्सों की चोरी रोकी जाए तो उन से भी हो सकती है और सरकार को फिर किसी प्रकार का टैक्स लगाने की आव यकता ही न पडे। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैसट है कि टैक्सों की चोरी को रोकने का खास बंदोबस्त किया जाना चाहिये।

श्री सभापतिः भाटिया साहब आप वाइंड अप करिये।

श्री दीप चन्द भाटियाः बस जी, एक दो बातें कह कर ही मैं समाप्त करता हूं। मैं अपनी सरकार को एक बात फरीदाबाद की ओर बताना चाहता हूं कि वहां पर एक फैक्टरी के अंदर गडबड के कारण हरनाम सिंह नामक व्यक्ति को मारा पीटा गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस बात की इंक्वायरी नहीं की गई कि यह किस्सा कैसे हुआ और न ही उस आदमी के परिवार की ही सरकार की ओर से कोई मदद दी गईग है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इन मामलों की तरफ भ खास तवज्जोह दे ताकि लोगों को यह एहसास हो जाए कि जनता राज्य सचमुच में जनता का राज्य है। इसलिये में निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाये। चीफ मिनिस्टर साहब ने और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने भी एक दो बार यकीन दिलाया था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि फरीदाबाचद को जिला बनाया जाये। अगर इस बारे में आज ही हाउस में एलान कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां पर एक इंजीनियरिग कालेज और मैडिकल कालेज अव य होना चाहिये। वहां पर बडी बडी फैक्टरियां हैं और लाखों की तादाद में वहां पर लोग रहते हैं। अगर वहां पर इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया जाये तो हरियाणा को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि फरीदाबाद को जिला हैड क्वार्टर भी बनाया जाये। यह दिल्ली के साथ लगता है और सरमायेदार लोग यह कोि ा ा कर रहे हैं

कि इसको दिल्ली में मिला दिया जाये। इसीलिये अगर फरीदाबाद को जिला बना दिया जाता है तो वह हरियाणा का पूरा अंग बन जाएगा और इसको दूसरी स्टेट में मिलाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसके बाद मैं बिजली बोर्ड के बारे में एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड पर हमारा करोडों रुपया लगा हुआ है। हम इंजीनियर्ज को तनख्वाह देते हैं लेकिन अगर कोई चीज वहां पर खराब हो जाती है और उसकी रिपेयर करवानी होती है तो वह हमें बाहर से करवानी पडती है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड का जो हैड है यानी चेयरमैन साहब, है वह टैक्नीकल आदमी होना चाहिये। क्योंकि बिजली बोर्ड में टैक्नीकल काम होता है इसको न तो मिनिस्टर साहब समझ सकता है और ही आई0ए0एस0 अफसर समझ सकता है। इसलिये अगर बिजली बोर्ड का चेयरमैन साहब, टैक्नीकल आदमी होगा तो जो हमारा करोडों रुपया बर्बाद हो रहा है जिसको हमारे किसान भाईयों पर और आम लोगों पर बोझा पडता है वह बच सकेगा। इन भाब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं चौधरी देवी लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्टेट की भलाई के लिये बहुत अच्छे कदम उठाये हैं।

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लालः) माननीय सभापति महोदय जी .....

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन साहब, जब मैंबर साहेबान को बोलने का पूरा मौका नहीं मिला है तो मंत्री जी किस चीज का जवाब दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपोजी ान बैंचिज से कम से कम एक आदमी को और बोलने का मौका दिया जाये।

श्री सभापतिः बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में जो फैसला हुआ था उसके हिसाब से मैं टाईम दे रहा हूं।

श्री भाम ोर सिंहः चेयरमैन साहब, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के फैसले अनुसार मैंने तीन आदमियों के नाम दिये थे लेकिन अब तक सिर्फ एक आदमी बोला है।

श्री सभापतिः कल को और डिमांडज आएंगी, उन पर बोल लेना।

बैठक का समय बढाना

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन साहब, जो डिमांडज आज आई है वह कल को नहीं आएगी। ये महत्वपूर्ण डिमांडज हैं और मैंबर साहेबान बोलना चाहते हैं इसलिस आप हाउस का समय बढा दें और मैंबर साहिबान को बोलने का मौका दें।

आवाजें: चेयरमैन साहब, जब मैंबर बोलना चाहते हैं तो आप समय बढा दें।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): चेयरमैन साहब, हाउस का टाईम अगर एक घंटा बढा दिया जाये तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री सभापतिः हाउस का समए एक घंटे के लिये बढाया जाता है।

वर्श 1979–80 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सबसे पहले मैं डिमांड नं0 3 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। डिमांड नं0 3 में 15 करोड 76 लाख रुपये की मांग की गई है। चेयरमैन साहब, इंसान को जिंदगी बसर करने के लिये जैसे रोटी, कपडे और मकान की जरूरत होती है उसी तरह से इंसान को अपनी जिंदगी की सुरक्षा की भी जरूरत होती है। अगर यह डिमांड 15 करोड की बजाये 30 करोड की भी होती तब भी मुझे कोई ि ाकवा नहीं ब ार्ते कि लोगों की जिंदगी की सुरक्षा हो। अभी ला एंड आर्डर के बारे में यहां पर बात चल रही थी। एक भाई ने यह बात कही कि भिवानी बैंक में डाका पडा था और मुलजिम गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसलिये सरकार बधाई की पात्र है। मैं बताता हूं कि हमारे जींद जिले में 6 डाके पडें हैं। वे डाके इतने खतरनाक थे कि लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। इन 6 में से

एक भी डाका आज तक ट्रेस नहीं हुआ है। अभी 22 तारीख को मेरे हलके के गांव बोंदवाल में रात को 12 बजे डाका पडा। जिनके घर डाका पडा उनके लिये यह खु ाकिस्मती समझें कि पिछले दिनों उनके लडके को हमने लाइसैंस की बंदूक दिला दी थी। जब उनके ऊपर हमला हो रहा था तो उस लडके ने हिम्मत की और उसने ऊपर चढ कर गोली चला दी और वे डाकू भाग गये। जिन हथियारों से उनके किवाड तोडे जा रहे थे वे मौके पर बरामद कर लिये गये थे लेकिन अभी तक उस मामले की कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। इसी तरह से जींद से 16 किलोमीटर दूर एक जटाना गांव है। वहां पर एस0एच0ओ0 मानता है कि वह रात को ग त करके निकला था और उसने तीन सिपाही भी ग त के लिये छोड रखे थे लेकिन रात को 11 बजे कुछ आदमी आये और एक घर में हमला कर दिया। वे घर का सारा सामान ले गये और घर के बच्चों को लडके और लडकियों तथा बहू बेटियों को बुरी तरह से पीटा गया। वे सब अब तक भी हस्तपाल में दाखिल हैं। एक औरत जिसके पास पिछले 15 सालों से कोई बच्चा नहीं था उसके पास अभी 12 दिन का लडका गोद में था। घर में लोग लडके की खु ियां मना रहे थे कि उन बदमा ाों ने हमला कर दिया। उन्होंने 12 दिन के लडके को छीन लिया और यह कहा कि अगर घर का सारा सामान नहीं दोगे तो इस लडके को मार दिया जाएगा। इस प्रकार वे घर का सारा जेवर और सामान ले गये। इसी तरह से 23 तारीख की बात हैं मैं जो बात बता रहा हूं । यह सब से दर्दनाक बात है और मैं इसे बिल्कुल सही बता रहा हूं जो

हमारे ऊपर एक कलंक है। मेरे जिला में गांव खेडी के अंदर एक डाका पडा वह डाका भी महाजन के घर पडा। डाकुओं की इतनी हिम्मत थी कि उनकी तरफ से यह कहा गया कि कोई भी जाट भाई मौके पर न आये, नजदीक न आये ..... (ाोर)

चौधरी गंगा रामः यह बडी भार्मनाक बात है जो कुछ भी गुप्ता जी ने कहा है वह गलत है इसको एक्सपंज किया जाये इसमें जाटों को नाम नहीं लिया जाना चाहिए किसी वि ोश का नाम नहीं आना चाहिएं।

श्री सभापतिः गुप्ता जी आप एक रिस्पौंसिबल मैंबर हैं आपको कम्यूनल फासिजम की बातें नहीं कहनी चाहिएं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह): यह बात जो आनरेबल मैम्बर साहब कह रहे हैं, किठाना की वारदात के बारे में मुझे इसकी इत्तलाह मिली थी। मैंने डी0एस0पी0 को फोन किया था। उसने बताया कि मुद्दई ने यह बताया है 4–5 सिक्ख लोग थे जिन्होंने डाका डाला है। आप को इस तरह नहीं कहना चाहिए था।

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): वे सिक्ख नहीं थे सिक्ख के वे ा में थे पंजाबी में बोले थे।

श्री मांगे राम गुप्ताः मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस इलाके में 5–6 डाके डले लेकिन एक भी ट्रेस आउट नहीं हुआ। इस तरह की दह ात फैली हुई है। चेयरमैन साहब, मैं यह

कह रहा हूं कि महाजनों को कोई रियायत नहीं है। डी0एस0पी0 वगैरह वहां पर कोई नहीं पहुंचा आपको डाकुओं को पकडना चाहिए और उन्हें मारना चाहिए। डाकू भाग गयें कोई भी डाका ट्रेस नहीं हुआ। चेयरमैन साहब, यह बुराई है दूार होनी चाहिये यह गलत नहीं है कि खेडी और जाटुआना में जाटों ने ही डाके डाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जाटों ने ही ये किये हैं ये सारे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं जैसे हमारे इलाकै में जाटों के गांव हैं वे हमारे खिलाफ प्रौपेगंडा करते हैं हमें बदनाम करते हैं। अगरी किसी गांव में किसी गरीब ने पैसा कमा रखा है तो उसके हक को छीनना नहीं चाहिए। मैं यह कहूंगा कि अगर किसी ने नाजायज पैसा कमाया है तो उसको जब्त किया जाये और देहात और भाहर में रहने वाले एक ही जाति के लोगौं पर डाके पडने पर एक भी ट्रेस आउट न हो और हमें कहा जाये कि सरकार को मुबारकबाद दो यह कैसे किया जा सकता है ?

श्री सभापतिः आप रैपीटि ान कर रहे हैं कृपया वाइंड अप करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि इसके बारे में कोई भी अफसर कोताही न करे और ज्यादा से ज्यादा कोि ा ा करके ज्यादा से ज्यादा केसिज ट्रेस आउट करे। डिमांड नं0 2 में जो सरकार ने कदम उठाया है उसके लिए भाुक्रिया अदा करता हूं अगर उस पर अमल किया जाये। जो नाजायज काम हो, उसकी हम मुखालफत करते हैं और जो अच्छी

बात है उसके लिए तहे दिल से भाुक्रिया अदा करते हैं। जो दह ात फैली हुई है और जिसके बारे में हमारे साथी कह रहे थे मैं उसको स्पश्ट करता हूं कि 5–6 डाके पडे और एक ही जाति के लोगों पर पडे। यह दुखदाई है। इसलिये मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता क्योंकि मेरा भी जन्म इसी जाति में हुआ है। यह जाति के नाम पर कलंक है अगर किसी ने नाजायज पैसा कमाया है तो उसको पकडा जाये और .....। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिहः यह एक्सपंज होना चाहिए। ऐसा कहना ठीक नहीं हैं

श्री लछमन सिंहः यह तो ..... वाली बात करके आप लोगौं को भडका रहे हैं। यह तो भडकाने वाली बात है।

श्री सभापतिः यह एक्सपंज किया जाए।

डा0 बृज मोहन गुप्ता (जगाधरी): मैं आपको ध्यान डिमांड नं0 23 पर दिलाना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर ट्रांसपोर्ट का कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। पिछले साल बाढ से अम्बाला सहारनपुर रोड जो टूटी हुई है, अम्बाला जगाधरी, जगाधारी सहारनपुर रोड का अभी तक अच्छा प्रबंध नहीं हुआ है। यह रूट खराब होने के कारण रेल भी अभी तक अच्छी तरह से चल नहीं पाती है इसलिये बसों में ज्यादा सवारियां होती हैं ज्यादा सवारियां एडजस्ट करने से बसों की हालत भी खराब है। हरियाणा में रेल

लाईन ठीक नहीं है। अम्बाला सहारनपुर रूट वाया जगाधारी जो है उस पर मेरी चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब से प्रार्थना है कि और बसिज चलाई जायें। अम्बाला में भााम को 8 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है बस नहीं है। अम्बाला जगाधरी 11 बजे ट्रेन चलती हैं। इस रूट पर इस टाईम में एक आध बस चलाई जाये ताकि अम्बाला से चलने वालों को परे ाान न हो। चण्डीगढ़ से 6 बजे जाने वाली लोगों को वहां काफी परे ाानी उठानी पडती है। ट्रांसपोर्ट की बस सर्विस अच्छी होनी चाहिए ताकि आने जाने वालों को परे ाान न हो। हरियाणा की बसों के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बस नं0 एच0आर0डी0 7254 में अम्बाला से चण्डीगढ़ आने के लिए खडा था वह हरियाणा रोडवेज करनाल की बस थी उस पर लिखा था कुरप ान जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे मेरे ख्याल से डिले ब्रीडज कुरप ान लिखा होगा डिले ब्रीडज की जगह की चादर तो भाायद फट गई थी और कुरप ान रह गया था। इससे लोग चर्चा कर रहे थे कि इसमें कुरप ान लिखा हुआ है। हो सकता है इसमें चार टिकट के पैसे लेते हों और देते हों एक टिकट। उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं। बस स्टैंड पर यह जिक्र कर रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है। चेयरमैन साहब, मैं यह बात चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस किस्म के भाब्द अगर कहीं गलती से कहीं रह गए हैं तो उनको जल्दी से जल्दी देख करके ठीक कर लिया जाए क्योंकि ऐसे भाब्दों से जनता में कुछ और किस्म के विचार भाुरू हो जाते हैं

और हम लोगों में भी भ्रुरू हो जाते हैं। इसके बाद में डिमांड नं0 12 के बारे में कहना चाहता हें। एम्पलायमैंट और लेबर के बारे में यह बात सभी मानते हैं कि आजकल हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे दे ा में अन एम्पलायमैंट बढ रही है। अनपढ भी और पढे लिखे भी बहुत ज्यादा बेकार हैं और मुझे यह भार्म के साथ कहना पडता है कि अभी कल परसों मेरे पास कुछ लडके आए जिनमें एम0ए0 और एम0एड0 भी थे। वह मुझे नौकरी के लिये कह रहे थे। चेयरमैन साहब, एम0ए0 फर्स्ट क्लास एक चपडासी की नौकरी के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं। इस किस्म की बेरोजगारी सारे दे ा के अंदर और हमारे हरियाणा के अंदर है। इसलिए हमारी सरकार मेरे विचार में बेरोजगारी के बारे में दो तीन बातें ध्यान में रखे तो कुछ न कुछ हमारे हरियाणा का सुधार हो सकता है और वह यह है कि किसी भी जगह गवर्नमैंट सर्विस में अगर किसी को नौकरी के लिए लिया जाता है तो वह आन मैरिट पर लिया जाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा ? इससे फायदा होगा जो कि एम0ए0 फर्स्ट क्लास लडके हैं वह नौकरी में आ जाएंगे और वह अच्छा काम करेंगे और दूसरी बात जो रात दिन को एम0एल0एज0 और मिनिस्टरज्र के पीछे सिफारि ा वाले घूमते फिरते हैं और हम लोगों को दुखी करते हैं वह दुख भी दूर होगा। दूसरी बात यह है कि सिफारि ा न होने से जो इंटैलीजैंट लडके हैं, वह सर्विस के बिना रह जाते हैं वह सर्विस में नहीं आ सकते और उनकी जगह सिफारि ा वाले आ जाते हैं अगर सिफारि ा वाले आएंगे तो वह काम क्या करेंगे वह तो ठीक से अपना नाम भी इंगलि ा

में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए मेरे विचार में भर्ती करते वक्त लडके की काबलियत को देखा जाना चाहिए और भर्ती आन मैरिट होनी चाहिए। एम्पलायमैंट में सब क्लासों की रिजर्वे ान हैं जैसे ि ाडयूल्ड कास्टस, ि ज्ञडयूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासिज और एक्स सर्विस मैन इनकी सब की रिजर्वे ान है। इस लिहाज से अगर हम मैरिट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही सालों में जो टौप क्लास लडके हैं वह अपनी जगह पर आ जाएंगबे। इससे एडमिनिस्ट्रे ान का काम भी ठीक चलेगा आऐर जो घपलेबाजी है वह भी खत्म हो जाएगी। एम0एल0एज0 के पीछे और मिनिस्टरर्ज साहब के पीछे जो रोजाचना 200–250 लडके रहते हैं और कहते हैं कि मेरी सिफारि ा कर दें वह भी खत्म हो जाएगा। अब मैं एक बात लेकर डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं कि ई0एस0आई0 की स्कीम लेबर डिपार्टमैंट की है। उस स्कीम के अंदर मजदूर एम्पलाइज की परमो ान के लिए पूरी तरह से सरी कवर की गई है। उसमे कुछ हिस्सा हरियाणा सरकार दे रही है और ज्यादातर सैंट्रल गवर्नमैंट दे रही है। वह स्कीम सैंट्रल गवर्नमैंट की है। उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं भी उसके अंदर 13 साल काम कर चूका हूं और मुझे पता है कि उसके अंदर मजदूरों के साथ खिलवाड किया जाता है उस स्कीम में सारा खिलवाड है। पानीपत, फरीदाबादी और जगाधरी में भी हास्पिटल बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनमें दवाईया नहीं हैं जिसके कारण बेचार गरीब आदमियों को दवाईयां बाजार से लेनी पडती हैं। तो मैं इस तरफ सरकार का ध्यान

दिलाना चाहता हूं कि जो मजदूरों को मखौल उडाया जाता है उस सारी स्कीम को फैमिली प्लानिंग में बदलें। उन मजदूरों का ख्याल रखते हुए इस ए0एस0आई0 स्कीम को ठीक तरीके से चलाया जाए। जो बडे बडे हास्पिटल हैं, वह सफेद हाथी की तरह हैं वहां पर किसी को दवाईयां नहीं मिलती हैं जबकि वहां पर सब कुछ मिलने का प्रावधान है। इस तरह से मजदूरों का मखौल न उडाएं और उनके साथ खिलवाड न करें। चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नं0 17 जो कि एजुके ान के बारे में है इसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। इसके बारे में तो मैं कहूंगा कि हमारी हरियाणा सरकार ने एक या डेढ साल के अंदर एजुके ान के अंदर बहुत सुधार किया है। पिछले ही साल 10 स्कूलों को अपग्रेड किया गया और अब की बार 80 स्कूलों को अपग्रेड करने जा रही है और मेरे ख्याल में इनका आर्डर भी आ चुका है। यह बहुत अच्छी बात है। इतने स्कूल कभी पिछले 27 सालों में भी अपग्रेड नहीं हुए। कम से कम इस सरकार ने 200 या 250 स्कूल अपग्रेड किए हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि प्राईवेट स्कूलों के अध्यापकों ने एक बार जनवरी में एक मांग की थी कि हमें तनख्वाह ट्रेजरी से मिलनी चाहिए क्योंकि प्राईवेट स्कूलों में अध्यापकों को तनख्वाह तो और ही दी जाती है और उनके हस्ताक्षर किसी दूसरी तनख्वाह पर करवा लिए जाते हैं। उनको वह तनख्वाह नहीं मिलती जिस पर उनके हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि उन अध्यापकों को ट्रेजरी से तनख्वाह देने की बात मान लें।

इसके बाद मैं डिमांड नं0 3 के बारे में कहना चाहता हूं जो कि मेरा मेन सब्जैक्ट है। इसके बारे में एक बात मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि कि हमारी जगाधरी के अंदर बहुत मोटर साईकिल और स्कूटर चोरी हुए थे और उनका कुछ पता नहीं लग सका था। अभी 5–6 दिन हुए अम्बाला के अंदर उनमें से 2 पकडे गए हैं भाायद और भी पकडै जाएं लेकिन मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि वह मोटर साईकिल उसी नम्बर से अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी में घूमते रहे और पुलिस उन्हें नहीं पकड सकी लेकिन एक मैकेनिक ने उन्हें पकड लिया। होम के बारे में ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह ठीक है कि होम डिपार्टमैंट वाले अपनी डयूटी 24 घंटे देते हैं। अभी एक जगाधरी की ही बात है। वहां पर सटटे वालों का एक जलूस निकाला गया जिससे जो दो तीन सटटे चलते थे वह बंद हो गए थे लेकिन अब फिर जगाधारी के अंदर दोबारा सटटा बडे जोरों से चल रहा है। यह पता नहीं वह सटटा एक बार बंद हाने के बाद फिर दोबारा कैसे चालू हो गया। मैं होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वहां पर सटे वाले बहुत ज्यादा तादाद में हो गए हैं और सटा एक बार बंद हो करके दोबारा फिर से चाले हो गया है वह इसकी तरफ ध्यान दें। इन भाब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी गया लाल (हसनपुर, अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं मांग नम्बर 2 पर बोलना चाहता हूं। सामान्य प्र ाासन

पर काफी चर्चा हो चुकी हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो कम खर्च करने का कदम उठाया हैं वह बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इस चर्चा पर काफी एम0एल0एज0 साहेबान ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह ठीक है कि खर्चा कम होगा। बडी कोठी पर चार चार हजार रुपया खर्च होता है, लेकिन छोटी कोठी पर कम खर्च होगा, छोटी कार पर भी कम खर्च होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री महोदय फ्लैट में आ जाएं तो सुरक्षा मु कल होगी क्योंकि फ्लैट में सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री का स्टाफ बहुत ज्यादा होता है। यह ठीक है कि बडी कोठी की बजाये छोटी कोठी लें लें तो ठीक रहेगा। इसके साथ ही साथ टेलीफोनी पर भी पाबंदी लगाई है। इससे खर्च में अव य कमी होगी। जनता सरकार का यह सराहनीय कदम है।

अब मैं डिमांड न0 2 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। हमारे दे ा का संविधान समाजवाद पर आधारित है। संविधान में यह लिखा हुआ है कि दे ा के नागरिकों को एक समान स्तरव पर लायेंग और सब को बराबर लाने के लिए ही रिजर्वे ान रखी गई थी। चेयरमैन साहब, ि ाडयूल्ड कास्टस वैल्फेयर कमेटी के माध्यम से मैंने पता किया है। ि ाडयूल्ड कास्टस की रिजवे ान इस प्रकार कभी पूरी नहीं हो सकती है। तीन चार महकमों का हमने ओरल एग्जामिने ान किया है जैसे सिंचाई विभाग, एक्साईज एंड टैक्से ान, जरायत विभाग। पिछले 32 सालों से 20 परसैंट

रिजर्वे ान चल रही है जो ि ाडयूल्ड कास्टस के लिए रखी गई है। इसके तहम कितने आदमी लिए गए हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सिंचाई विभाग में ि ाडयूल्ड कास्टस क्लास ए में कोई नहीं, क्लास बी में 3 परसैंट, क्लस सी में 9 परसैंट और चौथी क्लास में बाल्मीकी भाई आते हैं जो गंदगी उठाते हैं। इसकी वजह से इस क्लास में रिजर्वे ान पूरी है। इसी तरह एक्साईज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट में ए क्लास में 12 परसैंट, क्लास बी में 12.5 परसैंट और क्लास सी में 14.3 परसैंट जरायत विभाग में क्लाए ए में 6 परसैंट, क्लास बी में 12 परसैंट और क्लस सी में 14.3 परसैंट रिजर्वे ान है।

श्री सभापतिः आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

चौधरी गया लालः मैं सामान्य प्र ाासन पर बोल रहा हूं। चेयरमैन साहब, सरकार कानूनी बनाती है। स्टेट का मुख्य सचिव उसकी इम्पलीमैंटे ान करताा है परन्तु ऐसा नहीं होता।

श्री सभापतिः जो फिगर आप बोल रहे हैं यह कहां से ली हैं ?

चौधरी गया लालः ि ाडयूल्ड कास्टस कमेटी हर डिपार्टमैंट को एग्जामिन करती है उसकी फिगर मेरे पास हैं उसके मुताबिक बोल रहा हूं।

श्री सभापतिः ि ाडयूल्ड कास्टस वैल्फेयर कमेटी की रिपोर्ट आ गई है ?

चौधरी गया लालः मैं तो सामान्य प्र ाासन पर बोल रहा हूं। इसमें यह बात भी आती है।

श्री सभापतिः फिर आप यह फिगर्ज कोट न करें

चौधरी गया लालः चेयरमैन साहब, पिछले 30 सालों से हरिजनों और गरीबों की हिमायती कांग्रेस सरकार इस दे ा में विराजमान रही है। कांग्रेस 30 वर्श तक भाासन करती रही और यही गरीब जनता इनको सत्ता में लाती रहीं हरिजनों के मतों के ऊपर राज करते रहे, लेकिन 30 वर्श से रिजर्वे ान की कमी को पूरा नहीं कर सकी। 20 परसैंट में से दो तीन परसैंट ही लिए गए हैं और उछल उछल कर बातें करते हैं .....

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चौधरी गया लाल जी ने क्या कोई पार्टी छोड़ी है जो न बदली हो ? (व्यवधान)

चौधरी गया लालः मैंने कोई पार्टी नहीं बदली कांग्रेस के मुकाबले में तीन बार लडा हूं ये कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं, चूंकि बात हरिजनों की चल रही हैं, इसलिए उनकी तबीयत नहीं मानती, हरिजनों की बात करना ये ठीक नहीं मानते। चेयरमैन साहब, जहां तक ि ाडयूल्ड कास्टस की कुल टोटल का ताल्लुक है (ए) क्लास में 3.5 परसैंट, (बी) क्लास में 3.2 परसैंट (सी) क्लास में 8.9 परसैंट रिजेर्वे ान हुई हैं सरकार जो कानून बनाती है उसके इम्पलीमैंट करने का काम मुख्य सचिव का होता है। अभी

अभी मुख्य मंत्री जी ने एक बह ुत बडा कदम उठाया है। पहले जब रिक्रूटमैंट होती थी तो हरिजन नहीं लिये जोत थे लेकिन अब मुख्य मंत्री महोदय ने यह कर दिया है कि हर पांचवां आदमी हरिजन रिक्रूट किया जाएगा, मैं मुख्य मंत्री साहब को इसके लिए बधाई देता हूं।

श्री सभापतिः आपका टाईम हो गया है।

चौधरी गया लालः आप दो मिनअ सुन लीजिए। अब मैं डिमांड नं0 3 पर बोलना चाहता हूं। पुलिस दे ा की अनु ाासन व्यवस्था सुधारने के लिए होती है लेकिन चारों तरफ से यही ि ाकायत आ रही है कि पुलिए की व्यवस्था ठीक नहीं है। यह ठीक बात थी लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल काफी हालत सम्भल गई है। जब हरियाणा बना था तो आबादी 60 लाख थी और आज लगभग सवा करोड की आबादी है। सरकार ने पुलिस डिपार्टमैंट में बडे बडे अफसर, आई0जी0, डी0आई0जी0 वगैरा बहुत बडी तादाद में बना दिये हैं, लेकिन सिवाही, जो दिन रात रक्षा करते हैं। डाकुओं और चोरों से मुकाबला करते हैं, उनकी संख्या नहीं बढाई गई। दुगनी आबादमी होने के बावजूद भी थाने के स्टाफ की कमी हो रही है। मैं चाहूंगा कि इस तरफ सरकार ध्यान दे। स्टाफ की कमी होने की वजह से कुछ खराबियां हैं अगर इसे बढांएगे तो वे दूर हो जाएंगी अनु ाासन ठीक हो जाएगा अगर थानों में पूरा स्टाफ रखा जाए।

अब थोडा सा डिमांड नं0 16 के बारे में कहूंगा। सरकार ने उद्योगों के बारे में बहुत सराहनीय कदम उठाये हैं, बेरोजगारी को दूार करने की दि ाा में एक बहुत बड़ा कदम है। बेरोजगारों को रोजगारी देने के लिए बहुत अच्छा कदम हैं काफी पैसा हाथ के काम करने वालों को दिया है, कुछ छोटे उद्योग धन्धों को दिया है, लेकिन इसकी इम्पलीमैंटे ान में रूकावट आ रही हैं मुझे जो रिपोर्ट मिली है, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले साल बवानी खेडा में एक यूनिट हैंडलूम का लगाया गया था जिसके लिए 54 हजार रुपया मंजूर हुआ था। अब तक उस यूनिअ को 20 हजार रुपया मिला है, बाकी रुपया नहीं दिया गया, बैंक वाले उसको सहयोग नहीं दे रहे हैं। पैसा न मिलने के कारण निरा ा होकर उन्होंने हैंडलूम का काम छोड दिया। इसी तरह मीतरौल में खडडी का उद्योग लगाया था जिसके लिए 71 हजार रुपया मंजूर हुआ था लेकिन अब तक 15 हजार ही बैंक ने दिया है, बाकी नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से वे काम छोड रहे हैं। इसी तरह पलवल के पास एक गांव है वघौला। यहां नट वोल्ट के छोटे उद्योग के लिए 20 हजार रुपया मंजूर हुआ था लेकिन अभी तक 10 हजार मिला है, बाकी नहीं मिला। इसी तरह मगौला में एक प्रैस था, उसके लिए 59 हजार रुपया मंजूर हुआ था लेकिन 22 हजार रुपया मिला। इस तरह से बैंक कहीं भी लोगों का काम खराब हो जाता है और वे निरा ा होकर चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। अगर सरकार गांव में कारखाने लगाना चाहती है तो इसे सबसे पहले पैसे का प्रबंध

करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी फैक्टरी को धन प्राप्त करने में कोई रूकावट तो नहीं आ रही हैं उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी इस तरह की हिदायत दी जाएं। चेयरमैन साहब, इस बारे में मेरा एक सुझाव यह है कि औद्योगिक कारखाने कामयाब तब होंगे जब उनमें काम करने वाले लडके ट्रेंड होंगे। अन ट्रैंड लडके अगर किसी नए उद्योग को खोलेंगे तो वे उसमें कामयाब नहीं हो सकते। पहली बार ही उन्हें नुकसान उठाना पडेगा तो वे फैक्टरी को छोड देंगे।

श्री सभापतिः गया लाल जी, अब आप वाइन्ड अप कीजिए।

चौधरी गया लालः चेयरमैन साहब, थोडा सा मैं ि ाक्षा के सम्बंध में कहना चाहूंगा। प्रौढ़ ि ाक्षा आरम्भ करना एक बहुत अच्छा कदम है। (विघ्न) प्रौढ़ ि ाक्षा काफी देर से चल रही है लैकिन अफसोस की बात है कि पिछली सरकार ने इसकी तरफ, ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया। इस बार कुछ ध्यान दिया गया है। पहले यह होता था कि जब कभी निरीक्षण करने कोई अधिकारी जाता था तो रात को लालटेन के इर्द गिर्द गांव के कुछ बूढ़े आदि बैठा कर दिखा दिए जाते थे और वास्तव में इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। रिटायर्ड मास्टर अगर इस काम के लिए लगाए जाएं तो यह प्रौढ ि ाक्षा कार्यक्रम कामयाब हो सकता है। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मेरा यह निवदेन है कि गांव में गर्ल्ज स्कूल बहुत कम हैं।

इसके सम्बंध में मैंने एक सवाल पहले भी हाउस के सामने रखा था। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गांव में गर्ल्ज हाई स्कूल बढांए जाएं।

श्री सभापतिः अब आप बैठिए, आपने बहुत टाईम ले लिया है।

चौधरी गया लालः सभापति महोदय, गर्ल्ज हाई स्कूल तभी कामयाब होंगे जब वहां साथ साथ छात्रावास भी बनाए जाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि स्कूलों के साथ साथ छात्रावा भी बनाए जाएं। धन्यवाद।

चौधरी गंगा राम(गोहाना): चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं एजुके ान की डिमांड नं0 9 पर बोलना चाहता हूं क्योंकि आज ही यहां बात चल रही थी कि सर्विस के मामले में मैरिट लिस्ट बननी चाहिए। मैं ऐग्री करता हूं कि मैरिट लिस्ट बननी चाहिए लेकिन देखने की बात यह है कि हमारे देहातों के अंदर स्कूलों में पढने लिखने के लिए कोई किताब नहीं होती बैठने के लिए स्टूल नहीं होते, मास्टर नहीं होते, स्याही नहीं होती, दवात नहीं होती, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और खाने के लिए रोटी नहीं होती। अगर इन देहातों में पढने वाले बच्चों का कंपिटि ान आप रोहतक, करनाल, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली आदि के अंग्रेजी स्कूलों में पढने वाले बच्चों के साथ कराएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो 80 फीसदी देहाती हैं, उनको

कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मैं मैरिट लिस्ट को मानता हूं लेकिन मैरिट लिस्ट जो 80 फीसदी देहाती हैं, उनकी अलग होनी चाहिए और जो आली ाान भाहरों के बच्चे हैं, उनकी अलग होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, मैंने हाउस के सामने इस बारे में एक सवाल भी रखा था। देहातों के अन्दर फल्ड आया और उस फल्ड की वजह से बड़ा नुक्सान हुआ। मेरे हलके गोहाना में दो गांव हैं रिठाल और बीदल। लाखों रुपये की बिल्डिंग्ज उन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाई थीं लेकिन फल्ड के टाईम में वे बिल्कुल नश्ट हो गए। एक कमरा भी नहीं बचा जिसमें बच्चे बैठ सकें। पिछले एक साल से कोई पढाई नहीं हो रही है। 8वीं तक के वे स्कूल हैं। अब सरकार अगर यह कहे कि देहात वाले दुबारा उन बिल्डिंगों को बनाएं तो यह नामुमकिन सी बात हैं वे बेचारे 16 साल से फल्ड से मर रहे हैं इसलिए मैं अपनी सरकार से सिफारि ा करूंगा कि फल्ड के कारण जो बिल्डिंग्ज बिल्कुल नश्ट हो गई हैं, उन बिल्डिंगों पर चाहे लाखों रुपया लगे सरकार के रुपये से वे बननी चाहिए क्योंकि गांव वालों ने एक दफा वे बना दी थी।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार की यह पालिसी बहुत बढिया है जो यह देहातों के अन्दर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगा रही है। बहुत लडके आगे आ रहे हैं। उनको रोजगार भी मिल रहा है लेकिन एक बात मैं अव य कहना चाहूंगा क्योंकि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। बहुत बडी

फैक्टरीज जिसमें कई हजार लडकों को रोजगार मिलता है वह या तो कोआप्रेटिव सैक्टर में लगती हैं या पब्लिक सैक्टर में लगती हैं। गोहाना सारे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा नवार पैदा करता है। वहां सूत का एक बहुत बडा कारखाना भी है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर मेरी सरकार सैंटर को ऐप्रोच करे तो गोहाना के अंदर एक टैंट फैक्टरी लग सकती हैं चेयरमैन साहब, गोहाना के लोग फल्ड की वजह से बडे परे ाान हैं उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है क्योंकि सरकार की वहां किसी किस्म की कोई दस्तकारी नहीं हैं तो मैं अपनी सरकार से और अपनु मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि गोहाना वाले आपकी जन्म भर पूजा करेंगे अगर आपने वहां पर इस तरह का कोई कारखाना लगा दिया जिसमें दो चार हजार लडकों को रोजगार मिल जाए।

चेयरमैन साहब, चूंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं इसलिए एक बात मैं इनकसे भी अर्ज कर देना चाहता हूं आज ठीक है ला एंड आर्डर काफी हद तक कन्ट्रोल में है लेकिन कई अफसर आज भी ऐसे हैं जो जान बूझ कर हेरा फेरी करते हैं हो सकता है कि महकमे को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जाता हो। इस सम्बन्ध में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे हलके में एक कासंढा गांव हैं वहां दो परिवारों के अंदर फ्री फाईट हुई। जैलियां चलीं और गंडासे चले। दोनों तरफ के व्यक्ति घायल हुए। आज भी वे लोग हस्पताल में पड़े हुए हैं। मैं

किसी की तरफदारी नहीं करता लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ एक पार्टी का चालान हुआ और दफा 307 के तहत 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। दूसरी पार्टी के जो व्यक्ति घायल पड़े हैं उनमें से किसी एक का भी चालाना नहीं किया गया। इस बारे में हजारों गांव वाले अधिकारियों से मिले हैं, ऐप्रोच कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी पार्टी वालों का चालाना नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब चूंकि हर जगह निगरानी रखते हैं। इसलिए इस मामले में भी वे गांव वालों की ि ाकायत को अव य दूर करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिहः परसों आपके रोबरू दूर तो कर आया था।

चौधरी गंगा रामः आपने ि ाकायत सुनी थी और आपने सही कार्यवाही करने के लिए कहा भी था लेकिन उसके बावजून भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। (विघ्न)

चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं जनरल एडमिनिस्ट्रे ान पर आना चाहता हूं। मैं किसी की ि ाकायत नहीं करता लेकिन लोगों की सहूलियत को देखते हुए यह बात कहना चाहता हूं। हमारे कुछ ऐसे कारपोरे ान्ज हैं, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो लोगों की सहूलियतों को देखते हुए देहात के अंदर होनी चाहिए लेकिन उन्होंने अपना हैड औफिस चण्डीगढ़ बना रखा है। हमारे यहां जीन्द में एक टैनरी है।

18.00 बजे।

यहा ंपर चार आदमी कई हजार रुपये की बिल्डिंग किराये पर लेकर बैठे हुए हैं। कारखाना जीन्द में है। जो कुछ भी लेन देन होता है वह वहां पर होता है लेकिन पता नहीं चार व्यक्ति यहां पर किस इन्ट्रैस्ट में बैठे हुए हैं। इन चार आदमियों का यहां पर बर्डन है। चण्डीगढ़ में दफतर का खमख्वाह किराया दिया जा रहा है। इसी तरह से हरियाणा में दो कमि नरियां हैं एक हिसार में हे और दूसरी अम्बाला में है। आपको पता है कि जितनी भी अपीलें होती हैं वे सभी आमतौर पर गांवों वालों की होती हैं मैं भी वकील हूं। मुझे पता है कि देहात वालों को कितनी दिक्कत होती है। हमारे देहात के भाई यहां पर चूरमा साथ बान्ध कर आते हैं और अपने मुकद्दमें करते हैं। उनको यहां पर ठहरने की भी दिक्कत होती है। सारा दिन तो उनका कमि नर के आफिस में यहां चण्डीगढ़ में लग जाता हैं रात को वे यहां ठहरते हैं। जो लोग यहां पर आते हैं उनको बडी भारी परे ाानी होती हैं जब लोगों को फैसेलिटिज देने के लिए हमार मुख्य मंत्री साहब बडी बडी मिसालें कायम कर सकते हैं तो यह भी दिक्कत दूर होनी चाहिए। ऐसी मिसाल या तो बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने कायम की थी या फिर हमारे मुख्य मंत्री महोदय जी ने कायम की है कि अपनी बडी कोठी को छोड़कर एम0एल0एज0 फ्लैट में आ गये हैं इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिन अफसरों की डे टू डे डिलिंग पब्लिक से

होती है उनको चण्डीगढ़ में न रह कर फील्ड में जाना चाहिए। वहां पर पब्लिक की सुनवाई की जानी चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सरदार लछमन सिंह जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जाएं। (विघ्न) मैं जनरल एडमिनिस्ट्रे ान के बारे में बताना चाहता हूं।

श्री सभापतिः आप जनरल एडमिनिस्ट्रे ान पर बोल चुके हैं।

चौधरी गंगा रामः आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापतिः समय काफी हो गया है। एक घंटा हाउस का बढा है इसमें मिनिस्टरों ने भी जवाब देना है। अब आप बैठिये

चौधरी गंगा रामः अच्छा जी, धन्यवाद।

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सदन में कुछेक बातों का उत्तर देना चाहता हूं। प्रतिपक्ष में बैठे हुए चौधरी भाम ोर सिंह जी जिस दिन बजट पर बोल रहे थे, उस दिन वे कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहते थे। जब उनको बजट पर बोलते हुए आधा घण्टा हो गया तो कहने लगे कि मुझे थोड़ा समय मिला है अभी तो मैं इंडस्ट्रीज के विशय में बोलना चाहता हूं। मैंने उस दिन विचार किया कि इनके पास बडी भारी सामग्री होगी जो सरकार के बारे में कोई राज फा ा करेंगे। मुझे ख्याल था पता नहीं क्या कया बाते कहेंगे ?

उन्होंने यहां पर मंत्री परिशद का भी किक्र किया, उसका जवाब तो हमारे मुख्य मंत्री महोदय देंगे। उन्होंने कुछ यहां हीटर और एयरकन्डी ार्न्ज की बात की है, जिस वक्त वे मिनिस्टर साहब हुआ करते थे उस वक्त भी हीटर और एयर कंडी ार्न्ज लगे हुए थे। इसका जवाब हमारे वित्त मंत्री जी देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमार जान को तो बावेला यह आ अया है जिस संस्था में वे भााामिल हुए हैं उसके आका और नेता जो हुआ करते थे उन्होंने ही ये सारी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं। पोहलू साहब आप तो मेरे साथ ही रहे हैं, आपकी सियासी जिन्दगी तो मेरे साथ ही बीती है। इनके नेता ने जो भाहु ााहियत की जिन्दगी बिताई वैसी तो कोई भी नहीं बिता सकता। चण्डीगढ़ से दिल्ली चले जायें रैस्ट हाउसों पर हजारों रुपया खर्च किया हुआ है। 19—19 ओर 20—20 सूटसके रैस्ट हाउसिज बने हुए हैं। एयरकन्डी ांड हैं। बीस बीस हजार रुपये के कालीन बिछाए हुए हैं। कालीन पर पैर रखते ही आसमान की तरफ ख्याल चला जाता है। इस तरह से लाखों और करोड़ों रुपया बरबाद कर रखा है। मैं सुरजेवाला जी की तारीफ करूंगा क्योंकि वे रेडीकल विचारों के हैं, लेफटिस्ट विचारों के हैं। वे किसान सभी में भी थे। इसलिए मैं उनको कहूंगा कि उन्हें ऐसी पार्टी में भााामिल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने भ्रश्टाचार की भी बात कही है, उसका जवाब तो हमारे मुख्य मंत्री साहब जी देंगे लेकिन मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री साहब जी ने चुनौती दे रखी है कि कोई भी सदस्य रि वत लेते हुए व्यक्ति को पकड़वायेगा उसको पांच सौ रुपये इनाम दिया

जायेगा। उन्हें ऐसी हिम्मत से कहना चाहिए कि ऐसा कोई कर रहा है। यह बात मेरे से सम्बन्धित नहीं है लेकिन मेरे से ग्रामीण उद्योग की बात सम्बन्ध रखती है। उन्होंने गोयबल की बात की है, वे जिस पार्टी में भाामिल हुए हैं, वहां वैसा ही किया करते हैं। उन्होंने यहां विधान सभा में सवाल किया था और जवाब मैंने दिया था। सह सवाल नम्बर 1032 था। उन्होंने प्र न पूछा कि कितने ग्रामीण उद्योग पंजीकृत हुए हैं, मैंने जवाब दिया था कि 498 हुए हैं दूसरा पार्ट था कि कितने लोग लगे हैं, मैंने जवाब दिया था कि 1286 लगे हैं और तीन लाख 78 हजार 420 रुपये कर्जा दिया है जिसमें से 9000 सबसिडी दी गई है। बीस यूनिटस बडे लगे हैं और 87 लाख 24 हजार रुपया कर्जा दिया है। उन्होंने कहा यह कुछ भी नहीं हुआ है। चेयरमैन साहब, एक जानवर होता है जो दिन में नहीं निकलता हे और दिन में आंखें बन्द कर लेता है। वह रात का राजा होता है वह सूरज को नहीं देख सकता। आज हरियाणा में सन 1977–78 में 15 मार्च से 21 माच्र तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान चला है। इस दौरान में 692 यूनिट लगे हैं जो काम कर रहे हैं। हमने पचास लाख रुपये पहले कर्जा दिया है और इन दिनों में 70 लाख रुपये कर्जा लेकर दिया हैं यह कहना कि गायेबल का स्टैंड है उन्होंने कहा कि यह कितनी बिडम्बना की बात है कि छोटे आदमियों को तीन लाख 78 हजार रुपया दिया गया और बडे लोगों को 87 लाख रुपया दिया गया है। यह ठीक बात है हमने उनको दिया है जो हम अपनी तरफ से सीड मनी देते हैं वह 10 परसैंट होता है

लेकिन यह जो रुपया दिया गया है, इसमें हरियाणा फाइनैंस कारपोरे ान ने भी दिया है। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी फाइनैंस कारपोरे ान इसी पर्पज के लिए है। हम उन लोगों को सूद पर रुपया देते हैं। उसका वाणिज्य का काम हे, वह प्राइवेट लोगों से सूद लेती है। फाइनैंस कारपोरे ान ने प्राइवेट कम्पनियों को 57 लाख 24 हजार रुपया दिया है। हमने अपनी ओर से जो दिया वह पोली स्अील को और जीन्द में जो टैनरी लगी हुई है, उसके दिया है। अभी गंगा राम जी भी इसका जिक्र कर रहे थे। पांच लाख रुपया हरियाणा डिवैल्पमैंट कारपोरे ान की तरफ से टैनरी को दिया है और 25 लाख रुपया पोली स्टील को दिया है। जो भी हमने रुपया दिया है वह गलत नहीं दिया है। उन्होंने यहां पर यह भी बडा वावेला मचा रखा था कि गरीबों को पैसा नहीं दिया। दो फर्मों के नाम भी उन्होंने बताये एक राधा स्वामी आयल कम्पनी का और दूसरा हरियाणा कंटेनेयर का। चेयरमैन साहब, ये लोग बात तो ग्रामीण उद्योग और रूरल इंडस्टियलाइजे न की कर रहे थे लेकिन बात भ्रुरू कर दी भाहर वालों को कर्जा देने की। चेयरमैन साहब, गांव में कर्जा देने वाली बात बिल्कुल अलग है और भाहर में कर्जा देने वाली बात बिल्कुल अलग है। अभी श्री गया लाल जी ने चार गांव बामनी खेडा, मीतरो और बघोला (दो यूनिट) का जिक्र किया और कहा कि बैंक वालों ने रुपया सैंक ान किया और पूरा रुपया नहीं दिया। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से अपोजी ान के मैम्बर्ज और ट्रेजरी बैंचिज के मम्म्गर्ज को कहना चाहता हूं कि सदन में उनको अपनी बात कहने का पूरा

अधिकार है लेकिन मुझे भी तो अधिकार दे दीजिए कि मैं अपनी बात कह सकूं। चेयरमैन साहब, हरियाणा में बैंक वाले हमारा जरूर सहयोग करेंगे। हमने उनसे आ वासन ले रखा है और मेरा अपना अनुमान है कि अगर कहीं कठिनाई हुई तो उसको दूर कर देंगे। चेयरमैन साहब, उनकी बात में कोई वजन नहीं है केवल मात्र प्रचार के लिए बात कह गए। लघु उद्योग का कयों गिला करते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आई उनके जो कांग्रेसी प्रैडीसैसर थे, उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने तो **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** करोड़ों रुपया मारूति को ही दे दिया और करोड़ों रुपया लोगों से लेकर दे दिया था क्योंकि उस कम्पनी का मैनेजिंग डायरैक्टर वह था जिसकी पूज्य माता जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान के लोगों आप मुझे वोट दो, मैं हिन्दुस्तान की गरीबी दूर कर दूंगी। उन्हौंने जनता की गरीबी तो कहां दूर करनी थी। उन्होंने तो अपने बेटे की गरीबी दूर करनी थी। उन्होंने तो लघु उद्योग के लिए कोई काम ही नहीं किया। इनको तो यह तकलीफ है कि जनता सरकार ने सत्ता में आते ही, हमारा जो वि वास था कि हिन्दुस्तान में मास प्रोडक ान होना चाहिए बहुत पैदावार होनी चाहिए, उस नीति पर काम करना आरम्भ कर दिया। स्पीकर साहब, अभी गंगा राम ने कहा कि गोहाना निवाड़ का केन्द्र है और गोहाना तहसील में पानी से तबाही होती है। जब वे गोहाना की बात कहते हैं तो मुझे बडी खु ी होती है। उन्होंने तम्बू के कारखाने की बात कही। स्पीकर साहब, मैं आज ही केन्द्रीय उद्योग मंत्री से मीटिंग करके आया हूं

और इसीलिए आज सुबह क्वै चन आवर में मैं नहीं था। केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने कहा है कि हरियाणा को जरूर कुछ उद्योग देंगे। श्री गंगा राम ने तम्बू के कारखाने की जो बात कही है, उसे जरूर करेंगे। टैनरी के कारखाने की बात कही गई है। टैनरी के कारखाने में अचानक छापा गारा गया और मैंने आदे ा दे दिया है कि यहां के दफ्तर का बिस्तर गोल करके वहां पर जाना चाहिए और वहां पर जो कमी हे उसको पूरा करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर बारह जिसमें 2 करोड़ 89 लाख 70 हजार 470 रुपया मांगा गया है। इसमें से 37 लाख रुपया लेबर डिपार्टमैंट के लिए मांगा गया हे और 43 लाख रुपया रोजगार डिपार्टमैंट के लिए मांगा गया है। बाकी का सारा रुपया आई0टी0आईज0 के लिए रखा गया है। स्पीकर साहब, सुशमा जी ने लेबर के बारे में आपत्ति की है। अध्यक्ष महोदय, इसमैं कोई दो राय नहीं है कि जब तक वर्कर को हम पूरी तरह से साथ लेकर नहीं चलेंगे और जब तक वर्कर का माइंड पीसफुल नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं बढेंगा। इसी तरह से उद्योगपति की अगर हम ठीक बात को नहीं मानेंगे और उद्योगपति का माइंड पीसफुल नहीं होगा तो स्टेट में उद्योग नहीं पनप सकेंगे। इसलिए सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि दोनों की ठीक बात सुने और जो

बात जायज है, उसको मनवाए। जहां तक सरकार का ताल्लुक है उसकी हमे ाा यही कोि ा ा रही है कि जो गरीब आदमी है, जो गरीब मजदूर है उसका सरकार हमे ाा ध्यान रखती रही है। लेबर डिपार्टमैंट का भी कर्त्तव्य बनता है और उसने अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह से निभाया है और जहां कहीं मालिक और लेबर में झगडा होता है लेकर डिपार्टमैंट पूरी कोि ा ा करता है कि फैसला हो जाए। कई जगह झगडे ऐसे थे जिनको कोर्ट में रैफर किया गया है। पिछले साल आठ हजार केसिज कोर्ट में रैफर किए और चार लाख 72 हजार के करीब लेबर कोर्ट के द्वारा मिल मालिकों से पैसा वर्कर्ज को दिलाया गया है। इसी तरह से इस साल साढ़े छः हजार केसिज कोर्ट को रैफर किए और तकरीबन चार लाख रुपया वर्कर्ज को दिलाया गया और मैं वि वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी लेबर की फीस हमारी स्टेट में है, भाायदी किसी और स्टेट में नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट में तकरीबन अढाई लाख वर्कर्ज फैक्टरीज में काम करते हैं। उनमें से बडी मुि कल से सारी स्टेट में चौबीस सौ या पच्चीस सौ वर्कर्ज ऐसे हैं, जो हड़ताल की कोि ा ा करते हैं अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट में सिर्फ दो फैक्टरीज हैं जिनमें तालाबंदी हैं बहिन सु ामा जी ने गुड ईयर के बारे में जिक्र किया। सरकार की तरफ से इसमें कोई जयादती नहीं की गई है। मैंने तीन चार बाद मीटिंग की है। हमारे अफसरों ने भी मीटिंगें कीं और उसके बाद भी जब बात बनती नहीं दिखाई दी तो सरकार ने डिक्लेरूर किया कि जितने दिन फैक्टरी बन्द रही है, मजदूरों को उतने दिन

की मजदूरी मिले। सरकार वर्कर्ज का हर तरह से ध्यान रखती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहिन सुशमा जी को बताना चाहता हूं कि हमारी स्टेट की फैक्टरीज में जितनी पीस है और वर्कर्ज के साथ जितना तालमेल है भाायद ही किसी और स्टेट में होगा। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, जहां तक लेबर का मिनिमम वेजिज का ताल्लुक है, हम इसी साल पहली अप्रैल से मिनिमम वेजिज का फैसला करने जा रहे हैं। 1975 में मिनिमम वेजिज पास किए गए थे जो 155 से लेकर 185 रुपए तक थे। पहले मिनिमम वेजिज का फैसला 31 मार्च तक होना था लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने आज ही फैसला किया है कि हरियाणा में 240 रुपए से कम किसी वर्कर को नहीं देंगे। हमने 240 रुपए मिनिमम वेज रखा है। स्पीकर साहब, पंजाब में मिनिमम वेज 225 रुपए हैं। गरीब मजदूर से हमारी सरकार की पूरी हमदर्दी है और इसीलिए हमने 240 रुपया मिनिमम वेज तय किया है। बहिन सुशमा ने एक बात और कही कि सरकार अदायरों में भी यूनियन होनी चाहिए। यूनियन को दबाना नहीं चाहिएं अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार कर्मचारियों का ताल्लुक है अगर हम ज्यादा यूनियन को बढावा देंगे तो काम ठीक नहीं चलेगा और मैं लीडर्ज को और खास तौर से सुशमा जी को कहूंगा कि इतनी सस्ती लीडरी उन्हें नहीं करनी चाहिए और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार किसी के हक को नहीं दबाती है और गरीब आदमी की बात सरकार सुनती है। अगर सरकारी अदायरों में भी जहां 25 या पचास आदमी काम करते हैं, वहां पर यूनियन को बढावा दें, तो एडमिनिस्ट्रे ान ठीक नहीं

चलेगा। अध्यक्ष महोदय, अनु ाासन को कायम रखने के लिए हमारे लीडर्ज का फर्ज बनता है कि वे लोगों को समझाएं। लेबर और मिल मालिकों का छोटे और बडे भाई को किसी भाई का रि ता होना चाहिए। अगर एक बेटा या छोटा भाई अपने बाप या बडे भाई को किसी के भडकावे में आकर गाली देने लगे या बाप अपने बेटे पर कोई ज्यादती करने लगे तो काम ठीक तरह से नहीं चल सकता। दोनों में जब कोआप्रे ान होगा तभी काम ठीक तरह से चलेगा। बजाए हम वर्कर्ज को भडकाएं, हमें वर्कर्ज को कहना चाहिए कि उनको अनु ाासन में रहना चाहिए जिससे दे ा और प्रदे ा की प्रगति हो सके। अध्यक्ष महोदय, लेकर के बारे में मुझे इतना ही कहना है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, रोजगार विभाग के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं बताना चाहूंगा कि रोजगार विभाग ने पिछले साल 36553 आदमियों को रोजगार दिलाया और इस साल 37791 लोगों को रोजगार दिलाया गया। जो प्राईवेट अदायरे हैं उनको भी इस विभाग द्वारा रजिस्टर किया जाता है और बेरोजगार नौजवानों का मार्ग द र्ान करते हैं कि आप ऐसे करो, इस जगह पर एप्लीके ान्ज वगैरह दो। इस तरह कई प्रकार से बेरोजगार नौजवानों का मार्ग द र्ान किया जाता रहा है। जो गैर सरकार अदायरे हैं, फैक्टरियां हैं, जिन के अन्दर कम से कम 25 आदमी हों, उनको भी इस विभाग के द्वारा कवर किया गया है और उन फर्मा या फैक्टरियों के नाम भी इसी विभाग द्वारा रजिस्टर किये जाते हैं ताकि ऐसे प्राईवेट अदायरों में भी रोजगार विभाग द्वारा भर्ती की जा सके जिससे कि लोगों को राहत मिल

सके। इस प्रकार इस रोजगार विभाग द्वारा कोई लगभग साढे तीन हजार प्राईवेट अदायरों में भी बेरोजगार लोगों को सर्विस मिली है। इन भाब्दों के साथ मैं ज्यादा न बोलता हुआ, यह कहूंगा कि इस कट मो ान में कोई वजन नहीं है, इसलिये इन ग्रान्टस को पास किया जाए। साथ ही आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग न0 9 के विशय में कुछ बातें कहना चाहता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि किसी दे ा, किसी समाज या किसी व्यक्ति का उत्थान तभी हो सकता है जबकि वहां पर ि ाक्षा का अच्छा प्रबन्ध हो, लोगों को साही ि ाक्षा दी जाती हो। यह एक बडा महत्वपूर्ण विशय है। हम को पता है कि सन 1966 के बाद किस प्रकार हमारे राज्य में कृशि और दूसरे कामों में काफी वृद्धि हुई है लेकिन ि ाक्षा के सम्बन्ध में अभी भी हमारा दे ा, हमारा प्रान्त बिल्कुल पिछडा हुआ है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस तरफ खास ध्यान दिया है और ि ाक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का काफी प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिये कई प्रकार के ठोस कदम भी उठाये गये हैं राश्ट्रीय स्तर पर एक नान फारमल एजुके ान के सम्बंध में और जनरल एजुके ान के सम्बंध में एक राश्ट्रीय नीति निर्धारित की गई है जिसमें इस प्रकार के प्रयत्न किये गये हैं कि ि ाक्षा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की ढील न बरती जाए और ि ाक्षा का स्तर ऊंचा रखा जाए। इस बात के

साथ साथ और भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर प्रोढ ि ाक्षा के संबंध में भी कई कदम उठाये गये हैं और जहां पर भी इस प्रौढ ि ाक्षा की चर्चा होती हे, तो उस वक्त यह कहा जाता है कि इसमें सरकार को सफलता नहीं मिल सकती। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 2 अक्तूबर को तो यह कार्यक्रम भाुरू किया गया है और उसके भाुरू करने के प चात बहुत सारी फारमैलिटीज ऐसी थीं, जिनको पूरा किया जाना चाहिये था, केन्द्र वगैरह स्थापित करने थे और अफसरों की एप्वांयमैंट भी करनी थी, जिसके लिये समय भी चाहिये था। वह कार्यक्रम काफी हद तक पूरा हो चुका है और इतने थोड़े से समय में ही इतनी जल्दी यह कह देना कि यह कार्यक्रम असफल रहेगा, मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा।

इसके साथ साथ मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर लोग बडे गरीब हैं और वे अपने बच्चों को ि ाक्षा नहीं दे पाते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 9 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए नॉन फारमल स्कूलों की स्थापना की है। कई मां बाप किसी कारणव ा अपने बच्चों को नहीं पढा पाते या बीच में ही छोड देते हैं ऐसे लोगों के बच्चों के लिये सरकार ने इस प्रकार का प्रबन्ध किया ह ताकि गरीब बच्चों को ि ाक्षा दी जा सके और अभी तक 2358 स्कूल खोले जा चुके हैं जिसमें प्राईमरी व मिडल स्कूल भाामिल हैं। इसी तरह सें हमारी सरकार ने 5380 प्रौढ ि ाक्षा केन्द्र खोलने का

फैसला किया है जिन में से 2815 प्रौढ ि ाक्षा केन्द्र खोले जा चुके हैं तो आप ही देख लीजिये कि सरकार अपने हरियाणा प्रान्त में ि ाक्षा को कितना प्रोत्साहन दे रही है कि जिसकी मिसाल आज तक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहता हूं कि 9 साल से 14 साल के बच्चों को पढाने के लिये पहले इंस्ट्रक्टर्ज को 50 रुपये माहवार दिये जाते थे और इस वेतन पर भी कोई भी आदमी आने के लिये तेयार नहीं होता था। अब हमारी सरकार ने इस ओर खास ध्यान दिया है क्योंकि यह रकम बहुत थोडी थी अब नॉन फारमल प्राईमरी स्कूल्ज तक के बच्चों को पढाने वाले को 100 रुपये और मिडल तक के बच्चों को पढाने वाले को 150 रुपये माहवार दिये जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐसा सिर्फ हरियाणा स्टेट के अंदर ही किया गया है और किसी स्टेट में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया हैं (तालियां) इन केन्द्रों के द्वारा जो बेरोजगोर जे0बी0टी0 टीचर्ज हैं उनको नौकरियां मिलने में भी सुविधा होगी। इससे बेरोजगारी भी कम होगी और लोगों को अपना जीवन निर्वाह करने के लिये काफी सुविधाएं भी प्राप्त हो जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्कूलों की ि ाक्षा व जनरल ि ाक्षा का संबंध है, इसके बारे में पिछली सरकार ने जो अन्याय किया था, वह आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था। उस वक्त ि ाक्षा का स्तर इतना गिर गया था जिसका आप अंदाजा भी

नहीं लगा सकते। उस वक्त प्राईमरी और मिडल स्कूलों का दर्जा भी कम कर दिया गया था और कोई कदर नहीं की जाती थी लेकिन अब हमारी जनता सरकार ने इन सब बातों को खास ध्यान में रखा हे और सरकार ने प्राईमरी और मिडल स्कूलों का दर्जा बढा दिया है और आपको पता होगा कि सरकार ने 70 प्राईमरी स्कूलों का दर्जा बढाकर मिडल और 41 मिडल स्कूलों का दर्जा बढाकर हाई स्कूल तक कर दिया गया हैं और इस प्रकार हमारी सरकार ने औसतन दो स्कूल हर हल्कावईज अपग्रेड करने का फैसला किया है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार स्कूलों के दर्जे को बढाकर अप ग्रेड किया गया है, उसी प्रकार सरकार ने गरीब हरिजनों और गरीब बच्चों को जो कि पिछडे वर्ग से सम्बंध रखते हैं, उनके लिये रियायतें देने का भी प्रबन्ध किया गया है। पहले इस काम के लिये बच्चों को साढे 9 लाख रुपये रियायतें, छात्रवृत्तियां और दूसरे कामों के लिये दिये जाते थे लेकिन अब वह रा ि ा बढाकर सरकार ने 34 लाख रुपये के करीब कर दी है, इसके साथ यह भी किया गया है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको पहले छात्रवृति 8 रुपये माहवार की दी जाती थी अब वह रा ि ा बढाकर 16 रुपये माहवार कर दी गई है। जिन बच्चियों को यूनीफार्म के लिये 15 रुपये दिये जाते थे, अब वह रा ि ा बढाकर 30 रुपये की दी गई है जो 15 रुपये की वर्दी के अलावा हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक और फैसला भी किया है कि जब तक टीचर्ज टैंड नहीं होंगे तब तक बच्चों को अच्छी

ि ाक्षा भी नहीं दी जा सकती, इसके लिये सरकार चाहती हे कि 5000 प्राईमरी और 12000 दूसरे टीचर्ज को अच्छी ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया जाए, अतः इसके लिये सरकार ने ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया है ताकि बच्चों को सही ि ाक्षा मिल सके। इसी प्रकार से सौ ाल वैलफेयर प्र ि ाक्षण के लिये भी हमने 20 लाख रु0 का प्रबन्ध किया है। इसके अलावा हमने यह भी प्रयत्न किया है कि बच्चों को ि ाक्षा के लिये सिलेबस आदि का प्रबन्ध किया जाये। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गुडगांव में जो हमारे दो इंस्टीच्यू ांज काम कर रहे हैं उनका काम ठीक ढंग से चलाने के लिये हमने एक स्टेट कौंसिल की स्थापना करने का फैसला लिया है। उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि बच्चों को ि ाक्षा के लिये अधिक से अधिक कैसे अट्रैक्ट किया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमने बच्चों की ि ाक्षा में सुधार करने के लिये एक टैक्नोलोजी सैल भी स्थापित करने का फैसला लिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो पीछे ि ाक्षा योजनाबद्ध तरीके से नहीं दी गई। आपको पता है कि 18 हजार अध्यापक एडहोक बेसिज पर लगे हुए थे और उससे सारे विभाग को ही एडहोक विभाग कह दिया जाता था। यह बात गलत नहीं है क्योंकि जिस विभाग में इतनी संख्या में एडहोक कर्मचारी हों, तो उस विभाग के काम भी एडहोक ही होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन अध्यापको को रैगुलर करने का फैसला लिया है। इन अध्यापकों को दो महीनों की छुट्टियों की तनख्वाह नहीं मिलती थी और न ही इनका कोई सर्विस रिकार्ड था। कोई भी टीचर जब

तक भाांतिपूर्वक तरीके से न रह रहा हो तब तक वह अच्छी ि ाक्षा नहीं दे सकता। इस चीज को देखते हुए हमने लगभग 12 हजार टीचर्ज को रैगुलर किया और 834 टीचर्ज को रैगुलर करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इनके अलावा 2200 टीचर्ज और रैगुलर लगाये गये हैं। इस प्रकार से कुल मिला कर लगभग 15 हजार अध्यापकों को सरकार ने ठीक ढंग से काम करने का फैसला लिया और उनको राहत दो। अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी यह महकमा रहा है और आपको पता है कि हरियाणा में जो मिडल स्कूल हैं, उनमें आज तक कोई भी हैडमास्टर की पोस्ट नहीं है। मैं पिछले 6 महीनों से देख रहा हूं कि जो लोग 6 महीने के बेसिज पर लगे हुए थे वे उन स्कूलों में इन्चार्ज थे। इन स्कूलों के अध्यापकों तथा दूसरे कर्मचारियों को तनख्वाह देने का काम उस इलाके के एस0डी0ओ0 पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एस0डी0ओ0 के पास कितना लम्बा चौडा एरिया होता है। इसके अलावा इन स्कूलों के जो टीचर्ज हैं उनको एक भी पैसा खर्च करने की पावर नहीं थीं इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार यह विचार कर रही है कि मिडल स्कूल की सीनियर टीजर को वहां का इंजचार्ज बनाया जाये और उसको ड्रांइग एंड डिसबर्सिंग अफसर की पावर्ज दी जाएं ताकि एस0डी0ओ0 का टाइम भी बच सके और इन स्कूलों के अध्यापकों को भी तकलीफ न हो। हम यह भी कोि ा ा कर रहे हैं कि इस काम के लिये टीचर्ज को वि ोश भत्ता दिया जाये। इसके अलावा जैसे दूसरे महकमों में व्हीकल्ज और टैलीफोन की सहूलियत है उसी प्रकार

से हम धन की उपलब्धि होने पर ि ाक्षा विभाग में भी यह सहूलियत देने की सोच रहे हैं। सरकार इस चीज को भी महसूस करती है कि स्कूलों में इन्सपैक ान की बहुत बुरी हाल है। अब तक यह होता रहा है कि अगर कोई किसी स्कूल की इन्स्पैक ान कर भी जाता था तो उस पर कोई एक ान नहीं होता था। इसके लिये भी सरकार कदम उठा रही है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में स्टाफ कालेज में एक सैमिनार हुआ था। उसमें मैं भी गया था और ि ाक्षा सचिव भी गये थे। उस सैमिनार में यह तय किया गया कि स्कूलों की इन्स्प्रैक ान किस प्रकार से की जाये और उसके बाद फौलोअप एक ान कैसे लिया जाये। इस प्रकार से सरकार सारे विभाग को ओवर हाल करने के लिये प्रयत्न ील है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, देखने में तो यह आता है कि स्कूलों और कालेजों के दो अलग अलग डायरैक्टोरेट हैं। आपको पता है कि डी0पी0आई0 स्कूलों को डी0ई0ओ0 के थ्रू कन्ट्रोल करता है। लेकिन डी0ई0ओ0डी0पी0आई0 (कालेज) के तहत काम करता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार यह विचार कर रही है कि स्कूलों को कालेजों की डायरैक्टोरेट भी अलग अलग हो ताकि स्कूलों की तरफ भी ूपरा ध्यान दिया जा सके। पहली सरकार के समय में सारी पावर्ज सैंट्रलाइज कर दी गई थीं। पहले डी0पी0आई0 एक ट्रांसफर भी नहीं कर सकता था। अब सरकार ने इन सारी पावर्ज को डिसैंटरलाइज करने का फैसला लिया है। पहले अगर किसी कालेज के साधारण केस पर भी फैसला करना होता था तो सरकार करती थी लेकिन अब हमने वे पावर्ज

डी0पी0आई0 को दे दी हैं और इसी प्रकार से डी0पी0आई0 की पावर्ज डी0ई0ओ0 को देने के लिये विचार हो रहा है। इन सारी बातों के लिये हम जल्द फैसला लेंगे। अध्यक्ष महोदय, गंगा राम जी ने स्कूलों की बिल्डिंगों का और बाढ पीडित इलाके के स्कूलों का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत बहुत खराब है और चौथी और पांचवी पंच वर्शीय योजनाओं में स्कूल भवनों के लिये केवल 81 लाख रुपये लगाये गये थे लेकिन हमने केवल वर्श 1979–80 के लिये इस काम के लिये साढे 91 लाख रुपये बजट में प्रोवाईड किये हैं। इसके अलावा जहां बाढ पीडित इलाकों में स्कूलों की बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है उनके लिये अलग से 45 लाख रुपये रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने जहां स्कूलों का जिक्र किया वहां मैं कालेजों के बारे में भी थोडा सा कहूंगा। हरियाणा में जितने भी प्राइवेट कालेज घाटे में चल रहे थे उनको पहले सरकार की तरफ से 30 प्रति ात ग्रांट मिलती थी बाद में उसे बढा कर 45 प्रति ात किया गया था और फिर 45 प्रति ात से हमने 75 प्रति ात कर दी। इसक अलावा जिन प्राइवेट कालेजों की मैनेजमैंट ठीक काम नहीं कर रही थी हमने उन कालेजों को टेक ओवर करने का भी काम किया है। इसके अलावा जब यह महकमा आपके पास था तो अपने एक सर्वे कमेटी बनाने का आदे ा दिया था। वह कमेटी बनी और उसकी कई रिकमैंडे ांज थी। हमने प्राईवेट टीचर्ज की सिक्योरिटी आफ सर्विस का भी इसमें प्रावधान किया है। उस समय सिक्योरिटी आफ सर्विस नहीं थी हम सिक्योरिटी आफ

सर्विस का इंतजाम कर रहे हैं। जहां तक प्राईवेट कोलिजों की बात हैं हमने उनकी ग्रांट को 30 प्रति ात से 75 प्रति ात कर दिया हैं इसके साथ साथ सरकार ने यह भी फैसला किया है कि पहले जो इन कालेजों में लैम्चरर्ज को और टीचर्ज को ग्रैचुटी नहीं मिल पाती थी उसको भी सरकार ने घाटे में भाामिल कर लिया है। इससे उनको राहत मिल सकेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से कालिजिज के लैक्चरर्ज को ए0डी0ए0 नहीं मिल पाता। एक अप्रैल से सरकार ने हिदायत जारी कर दी है कि उनको ए0डी0ए0 दिया जायेगा। इसके साथ साथ उनकी पहले इस प्रकार की ि ाकायतें मिलती थी कि उनसे दस्तखत तो और कुछ पर करवाये जाते हें और दिया और कुछ जाता है इसको ध्यान में रखते हुए चैक द्वारा पेमैंट की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात के लिए भी विचार कर रही है कि महिलाओं के लिए और देहात में नए कालिजिज खोलने के लिए 3 हजार की बजाये 10 हजार रुपया एक्स्ट्रा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, हम ि ाक्षा के सुधार करने के लिये जो ि ाक्षा बोर्ड बना हुआ है उसकी बहुत सी बातों में सुधार करने की कोि ा ा कर रहे हैं। उनके लिए एक कमेटी बनायी गई है जिसके अंदर जितनी ि ाक्षा विभाग की जरूरतें होंगी उनको पूरा करने की कोि ा ा कर रहे हैं। दूसरे सरकार यह भी फैसला कर रही है कि प्राईमरी से ऊंचे दर्जे के या उससे भी ऊंचे दर्ज के स्कूल नजदीक बनाये जायें ताकि बच्चों को स्कूल तक जाने में तंगी न हो। अध्यक्ष महोदय, सदन में जिक्र आया कि जो हम

ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जो प्राईवेट कालिजिज ट्रेनिंग दे रहे हैं, वे एक दुकान की तरह हैं, कुरप ान के अड्डे हैं उन्होंने रोजगार बनाया हुआ है। दो सरकार कालेजों को छोड़कर सारे ऐसे कालेजों को बंद कर दिया जाये। गवर्नमैंट कालेज, भिवानी और एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ एक और कालेज है जो जारी रहेंगे। (विध्न)। इसके साथ साथ यह भी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ज को जो वि ोश ग्रांट दी जाती है, उसका कई बार कई सदस्यों ने जिक्र किया है और वि ोश तौर पर रोहतक की यूनिवर्सिटी का। सरकार एम0डी0 यूनिवर्सिटी एक्ट में अमैंडमैंट लाने जा रही है और एक कमेटी मुकर्रर कर दी है। हमारी कोि ा ा होगी कि यूनिवर्सिटी का फंक ाानिंग ज्यादा से ज्यादा डैमोक्रेटिक ढंग से हो। यू0जी0सी0 ने एम0डी0 यूनिवर्सिटी को मान्यता दे दी है, यू सूचना वी0सी0 ने दी है। साईट भी देख ली गई है ताकि अलगा कार्यक्रम चलाया जा सके। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो उसके लिए जो प्रिएम्बल में रखा गया था कि संस्कृत के लिये वि ोश ध्यान दिया जायेगा हम उसको भी लाने की कोि ा ा कर रहे हैं। इसका उद्दे य था कि संस्कृत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार हो। हमें यह पूरा ध्यान है कि इस उद्दे य की पूर्ति हो। अध्यक्ष महोदय, टीचर्ज की कितनी बडी समस्या थी कि 10–10, 15–15 साल से एफीि ायंसी क्रास नहीं हुई थी उनको कोई सर्विस रिकार्ड नहीं बना था, सर्विस बुक्स अवेलेबल नहीं थीं

जिसको अपोजी ान के भाई भी जिक्र कर रहे थे, वह समस्या दूर कर दी गई। जो 20–30 साल से रिटायर हो चुके थे उन प्रान्तीयकृत अध्यापकों को अभी तक कोई पैं ान नहीं मिली थी 1957 से 1966 के बीच रिटायर हो चुके थे ऐसे किसी टीचर को पैं ान नहीं मिली थी उनमें से कई तो भगवान को भी प्यार हो गये हैं उनको रिकार्ड बनाया गया है और उनको पैं ान देने का प्रबंध किया गया है। हमारे अपोजी ान के भाई यहां तो दहाड़ते हैं परन्तु वे पिछले तीस वर्श में कुछ नहीं कर सके। जनता पार्टी की सरकार ने ही उनको आकर पैं ान दी है, सभी को पैं ान का लाभ हुआ है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः प्वायंट आफ आर्डर सर। ि ाक्षा मंत्री जी ने यूनिवर्सिटियों का और सबका फैसला कर दिया, लेकिन चौ0 गंगा राम का हिसार के स्कूल का फैसला अभी तक नहीं किया है।

श्री अध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः यह महकमा ि ाक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिये जुटा हुआ है और इसके लिए यह महकमा मुबारिकबाद का भी हकदार है। ि ाक्षा की सभी समस्याओं को खत्म करने की कोि ा ा यह महकमा कर रहा है, कई सुधार भी हुए हैं। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों ने

महसूस भी किया होगा कि ि ाक्षा बोर्ड ने नकल को समाप्त करने के लिये काफी कोि ा ा की है।

अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने जो फैसले किये हैं और जो इतने बडे बडै काम किए हैं, उनको बयान करने के लिय मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों को बयान कर सकूं। (ाोए एवं विघ्न) ि ाक्षक जो लॉ कालेज में ि ाक्षा बोर्ड में एग्जामिनर और सुप्रवाइजर अप्वायंट होते थे और उनको जो कम्पन सेटरी अलाउंस मिलता था उसका 50 परसैंट पहले सरकार ले लेती थी लेकिन अब जनता पार्टी की सरकार ने यह फैसला किया है कि उनको वह अलाउंस सारे का सारा दिया जाएगा। (थम्पिंग) इसके बाद प्राइवेट स्कूलों के सम्बंध में भी चर्चा आई है कि उनके अध्यापकों को ट्रैजरी से तनख्वाह दी जाए। यह कोई साधारण बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, अगर ट्रैजरी से उकनो तनख्वाह देने की बात की जाए तो लगभग डेढ दो करोड रुपए का बोझ सरकार पर पडेगा। इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस की बात थी पहले यदि किसी टीचर से कोई किसी प्रकार की गलती हो जाती थी तो उसको हटा दिया जाता था और सरकार उसकी अपील पर उसको वापिस वहां पर रखने के आदे ा देती थी और मैनेजमैंट अगर नहीं मानता था तो उसकी सारी ग्रांट बंद करने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था और उसको वापिस सर्विस में नहीं रख सकते थे। लेकिन अब इस सरकार ने सिक्योरिटी आफ सर्विस में रूल

बनाने का आदे ा दे दिया है ताकि उनको दोबारा सर्विस में लाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, टैक्नीकल एजुके ान के अंदर विद्यार्थियों को 10 से बढाकर 15 परसैंट स्टाइपैंड कर दिया है तथा पहले जो 20 रु0 माहवार विद्यार्थियों को देते थे उसे बढा कर 50 रु0 करने का फैसला किया है। अध्यक्ष महोदय, बातें और भी बहुत रह गई हैं लेकिन समय की कमी को देखते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया (विघ्न एवं भाोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिहः): स्पीकर साहब, मैं डिमांड न0 3 पर कुछ कहना चाहूंगा जो होम डिपार्टमैंट से ताल्लुक रखती है। होम डिपार्टमैंट ऐसा महकमा है जिसके अफसरान को बडी नाखु ागवार डयूटी सरअंजाम देनी पडती है। अच्छे मौकों पर इन लोगों को कोई बुलाता नहीं, यदि कोई दुर्घटना हो जाये तो पुलिस को याद करते हैं। सुशमा जी ने कहा कि इनकी ट्रैनिंग कु छ सालों से ऐसी चली आई है कि लोग इनको रक्षक नहीं बल्कि भाोशक समझते हैं। स्पीकर साहब, मैं इस बात से इतफाक नहीं करता लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने पुलिस की ट्रेनिंग में काफी सुधार लाने भारू किये हैं। मुसीबत यह है कि जब कोई केस हो जाये और उनकी तफती ा भारू होती है तो पुलिस अफसरान पर तरह तरह के दबाव डाले जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल इन्ट्रैस्टस इलवाल्व होते हैं। तरह तरह के एलीगे ांज तफती ी अफसरों पर लगते हैं। अतः हमारी जनता

को भी अपनी डयूटीज के बारे में कुछ एहसास करना होगा पुलिस अच्छे व्यवहार से और अच्छे ढंग से काम तभी कर सकेगी। मुझे अफसोस है कि बडे बडे जिम्मेवारी लोग भी जैसे श्री मांगेराम गुप्ता और श्री जगजीत सिंह पोहलू भी कानून भाकनी करते हैं। इस प्रकार के जिम्मेवार लोग ही जो एक एक लाख लोगों के नुमांइदे हैं अगर कानून ि ाकनी करें तो किसी मुंह से ये लोग कह सकते हैं कि लॉ एंड आर्डर की हीलत ठीक नहीं। इसमें कोई भाक नहीं कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद क्राईम्ज की फिगर्ज में इन्क्रीज नजर आती है। वह इन्क्रीज स्वाभाविक थी क्योंकि 1975–76 के माहौल का और आज के माहौल का मुकाबला कीजिए क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने यह नीति अपनाई है कि फ्री रजिस्ट्र ान आफ केसिज होने चाहिएं। पिछली सरकार के जमाने में टोटल क्राइम्ज के आंकडों का हमारे टाईम की फिगर्ज से मुकाबला करें तो उनके मुकाबले में हमारी क्राइम्ज की फिगर्ज कम हैं। उन सालों में क्राइम्ज ज्यादा होने का कारण थाा कि जो असल केस होते थे जैसे केसिज अगेंस्ट प्रोपर्टी, केसिज अगेंस्ट कुरप्ान वगैरा की फ्री रजिस्ट्र ान नहीं होती थी। लेकिन अगर किसी की भाराब की भट्टी को पकड लिया जाता था और एक केस में 10 बोतलों को पकडा गया तो उस एक आदमी का चालान न करके 10 आदमियों का चालाना किया जाता था। कांग्रेस के जमाने की इनक्रीज की फिगर्ज कम्पेयर करें तो पता लगेगा कि 1975 में टोटल फिगर्ज 31259 क्राइम्ज की है और 1977–78 में लगभग 27 या 28 हजार की फिगर्ज हैं जो कम हैं।

पिछली सरकार के जमाने में किसी गरीब आदमी को कमजोर आदमी को जो सोसाइटी में समाज में बिल्कुल कमजोर हैं अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो हमने उनके लिए आदे ा दे दिए हैं कि उनके पूरी तरह से केस दर्ज किए जाएं। पहले पुलिस के अंदर जब प्रोमो ान होती थी तो उसकी काबलियत का जो क्राइटेरिया माना जाता था हमने उसको चेंज किया है। हमने उन बातों को बदला है। हमने उस क्राइटेरिया को बदला है। उस आदमी की लोगों के अंदर क्या अप्रोच है उसकी इन्वैस्टीगे ान कितनी साफ है, वह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वह लौगों का क्या काम कर सकता है और लोग उसको कितना चाहते हैं। इस प्रकार का क्राइटेरिया हमने अपनाया हैं इससे आपको क्राइम्ज की फिगर्ज में इंक्रीज जरूर नजर आती है लेकिन पुलिस की एफि ाएंसी इस बात पर निर्भर करती है कि क्राईम होने के बाद क्या उसकी डिटैक ान की जाती है, इन्वैस्टिगे ान की जाती है, और इन्वैस्टिगे ान होने के बाद क्या लोगों को तसल्ली होती है या नहीं, इस बात पर एफि ाएंसी निर्भर करती है।

19.00 बजे।

पुलिस तफती ा जो कर रही है क्या यह सही है, किसी किस्म का भेदभाव तो नहीं बरता जाता, इन सभी बातों पर निर्भर करती हैं। प्रिवेंटिव मैयर्ज भी लेना बडा जरूरी है। हमने नै ानल हाई वे पर चैक पोस्टस कायम की हैं, लेटैंस्ट मैंयर्ज भी

लेना बडा जरूरी है। हमने नै ानल होई वे पर चैक पोस्टस कायम की हैं, लैटैस्ट वायरलैस फिटिड हैं, रात को पैट्रोलिंग होती है। बुटाना गांव में जो परसों वाक्या हुआ इन्होंने खुद इस बात को माना कि पुलिस पार्टी वहां पर ग त करके गई है .....
..

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब स्पीच दे रहे हैं और बाजू चढाते जा रहे हैं, पुलिस का महकमा है और हमें इनसे खतरा है, ये बाजू चढाकर न बोलें। (हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिहः मैं अर्ज कर रहा था कि श्री मांगे राम गुप्ता ने खुद माना है कि जिस समय बुटाना गांव में वारदात हुई। उस समय पुलिस पार्टी वहां ग त करके गई थी। रात को पुलिस आफिसर वहां मौजूद थे और डी0एस0पी0 ने बताया कि पुलिस पार्टी आधा घंटा पहले ग त करके गई है। वह पुलिस दूसरे गांव में थी, ज्यों ही फायरिंग की आवाज आई, पुलिस पार्टी वहां आई। एक सिपाही रो ानी न होने के कारण गड्ढै में गिर गया, उसके पांव में चोट आई, भाायद वह हास्पिटल में एडमिट हुआ है। इस तरह नै ानल हाई वे पर जो जरूरी जगहें हैं जिन जगहों पर हमें पुलिस की जरूरत महसूस हुई वहां पर पुलिस की ग त सारी रात जारी रहती हैं

स्पीकर साहब, सरकार कोि ा ा कर रही है कि हर पुलिस स्टे ान को एक जीप प्रोवाइड की जाए ताकि क्राइम्ज की

डिटैक ान करना आसान हो जाए। स्पीकर साहब, मैं बहुत थोडे लफ्जों में खत्म करूंगा, दो तीन बातें ही रखूंगा। पिछले डेढ साल के अंदर अंदर हरियाणा की पुलिस ने तीन बहुत बडे काम किए हैं। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि करनाल जिले की पुलिस ने 17 लाख रुपये का सोना पकडा यह छोटी बात नहीं। डकैत भिवानी का बैंक लूटना चाहते थे, उनको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। ठगों के गिरोह के 7 आदमियों को भिवानी की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके इलावा बडे बडे नामवर बदमा ा लोग दूसरे प्रदे ाों से आकर हरियाणा में औप्रैट करते थे। अ ाोक, नरिन्द्र जैसे डैकाअटस को गिरफ्तार किया। जयप्रका ा अ ारफ जिसके नाम से मेवात का एरिया बदनाम था, जगजीत सिंह जैसे जो नामी कामी थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके इलावा 1978 के साल के दौरान टोटल 99451 रुपये की रिकवरी की है जो 77 परसैंट बैठती है, यह कम नहीं है। इसके इलवा 247 मर्डर हुए हैं इन में से 95 फीसदी ट्रेस किए, केवल 5 परसैंट ऐसे हैं जो ट्रेस नहीं हो सके। यह कोई छोटी फिगर नहीं हैं पहले इतने ट्रेस नहीं होते थे। स्पीकर साहब, लेबर एंड स्टुडैंटस के बारे में किसी माननीय सदस्य ने कोई खास जिक्र नहीं किया। इस पर मैं सदन का टाईम वेस्ट नहीं करना चाहता। कुछ इंडोविजुअल केसिज कई माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रखे। मास्टर ि ाव प्रसाद ने बोलते हुए कहा कि महकमों में पोलिटीकल इन्टरफीयरेंस होता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पुलिस के महकमें में और दूसरे महकमे जो मेरे पास हैं किसी

किस्म का इंटरफीयरेंस नहीं है, कोई पोलिटीकल इन्टरफीयरेंस नहीं है। अगर माननीय सदस्य इन्स्टांस देंगे तो फौरी तौर पर एक ान लिया जाएगा। मास्टर ि ाव प्रस्ज्ञद जी बोलते हुए कह रहे थे कि अम्बाला भाहर में 10 हजार रुपया माहवार पुलिस का बंध हुआ है, सट्टे का बाजार गर्म है, अफीम की स्मगलिंग होती है। इस वक्त मास्टर ि ाव प्रसावद जी नहीं बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता था कि पिछले 18 महीने से वे मेरे दोस्त हैं। जब से होम डिपार्टमैंट मेरे पास आया, कभी उन्होंने मुझे इसके बारे में नहीं बताया कि अम्बाला में ऐसी पोजी ान है। अगर कोई इन्स्टांस मास्टर जी देंग तो जरूर गौर की जाएगी। इस बात का मैं उनको वि वास दिलाता हूं। राव राम नारायण जी ने कहा कि हरियाणा में तीन चार आई0जी0 हो गए। राव राम नारायण जी ने सारी उम्र सर्विस की है, हमारे यहां आई0जी0 सिर्फ एक है, दो आई0जी0 प्रमोट किए हैं और वे एक्स काडर फोस्टों पर काम कर रहे हैं। हमारे यहां एक ही आई0जी0 है और एक ही रहेगा। इस तरह की बातें करना इनको भाोभा नहीं देता। एस0एच0ओ0 रोहतक के बारे में राव साहब को बडा गम है। राव साहब ठीक कह रहे हैं। बाबूजी आये और लोगों ने वहां हुल्लडबाजी की। बाबू जी के साथ दूसरे सीनियर आफिसर भी थे और उन लडकों को रोकना एस0एच0ओ0 का काम था। वह एस0एच0ओ0 कल्प्रिट पाया गया और कल्प्रिट के खिलाफ सख्त एक ान लियां राव राम नारायण जी इसको पोलिटीकल इन्टरफीयरेंस कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए जो कल्प्रिट है उसको सजा देनी चाहिए, हमारी

उसके साथ कोई दु मनी नहीं है। सुशमा जी ने बोलते हुए कहा कि गोच्छी गांव में अत्याचार हुआ। ऐसा काम हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केस वाकई दर्दनाक है लेकिन मैं बहन सुशमा जी को बताना चाहता हूं कि उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया है, मुलजिमों को पकड लिया गया है और कानून के मुताबिक जो सजा होगी, वह दिलाई जाएगी। चौधरी गया लाल जी ने कुछ बातें फरमाई। उन्होंने कहा कि स्टाफ को इंक्रीज किया जाना चाहिएं जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों हमने 256 कांस्टेबल बढाये हैं और 28 ए0एस0आई0 बढाये हैं। इसी तरह इस साल ढाई तीन हजार कांस्टेबल बढाने जा रहे हैं पुलिस स्ट्रैंथ बढाने का कारण यह है कि दिन प्रति दिन आबादी बढती जा रही है। इस हिसाब से पुलिस फोर्स का बढाना आव यक हो गया है। श्री मांगे राम गुप्ता ने कहा कि 6 डाके पड चुके हैं, इन्होंने बडा बावेला मचाया और सदन में सन्नाटा छा गया। ये तो दफा 458 के मुकद्दमे को भी डाका समझते हैं। दफा 388 को भी डाका मानते हैं। हर चीज को रौबरी का नाम देना कोइ अच्छी बात नहीं हैं एक दो केसिज जो रजिस्टर हुए हैं, इनमें से एक एस0डी0ओ0 जींद के घर डाका पडा था, दफा 458 के तहत उसका पर्चा दर्ज है। इसको भी रौबरी की भाब्ल दे सकते हैं, डाका कह सकते हैं। इन्होंने यह भी कहा कि किसी मुलजिम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इस केस में मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं और हजार रुपये की रिकवरी भी हो चुकी है। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। खेड़ी दरौदी, अलीपुरा, बोतवाला और किठाना में डाके के केस रजिस्टर हुए हैं और इनमें से एक भी केस बरामद नहीं हुआ है।

Mr. Speaker: This is no point of order. If you do not agree with the Minister's statement you may either give it in writing or you can see him in his office.

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, इनसे मैं क्या इ ा ज्वायन करूं कि किस चीज के केस थे। मेरे पास तो एफ0आई0आर0 के नम्बर हैं, मैं सैक ान भी पढ सकता हूं। जिनके तहत वे दर्ज हुए हैं लेकिन मैं इस चीज में न पडकर केवल इतना कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोताही नहीं होगी। मैं यह वि वास भी हाउस को दिलाना चाहता हूं कि लॉ लैसनैस हम किसी कौस्ट पर बरदा त नहीं करेंगे लेकिन साथ ही साथ मैं सदस्यगण से यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि वे बोलते वक्त चाहे वे स्टेज पर बोलें या कहीं और बोलें इस तरह की बातें करें जिससे कि लॉ एंड आर्डर मेनटेन करने में कोई दिक्कत न हो। लॉ एंड आर्डर मैनटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी है चाहे अपोजी ान के भाई हों या ट्रैजरी बैंचिज के सदस्य हों हम सबको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे प्रदे ा में भाांति रहे। मैं यह नम्रता से निवेदन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला): अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं0 23 के बारे में मैं कुछ बातें हाउस को बताना चाहता हूं। हाउस के अंदर काफी चर्चा हुई कि किराए में तो वृद्धि हुई है लेकिन बसों की हालत काफी खराब है।

श्री अध्यक्षः मेरे ख्याल में पन्द्रह मिनट और बढाने पडेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः मैं तो केवल पांच मिनट लूंगा।

स्पीकर साहब, इससे पहले तीन साल पूर्व 20—4—1976 को किराया रिवाईज किया गया था। उस वक्त हमारा खर्चा पर किलो मीटर 164 पेसे के करीब पडता था। आजकल प्राइसिज इतनी बढ गई हैं कि यह 184 पैसे पर किलोमीटर हो गया है। इसके अंदर जो खर्च भाामिल हैं वे ये हैं कि हमने 6 कि तें एडहौक रिलीफ की अपने कर्मचारियों को दी हैं, एक्सग्रे ि िया ग्रांट 12 परसैंट से बढाकर 15 परसैंट की गई है। इन दोनों फैक्टर्ज को अगर ले तो 7.8 पैसे पर किलोमीटर वृद्धि हमारी हो गई हैं। स्पेयर पार्टस मोबिल आयल और दूसरे अखराजात महंगे होने के कारण 7.4 पेसे पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च बढा है। हमारी बस की कीमत 1 लाख 35 हजार से बढ कर 1 लाख 60 हजार हो गयी है। 25 हजार एक बस की कीमत बढने के कारण 3 पेसे पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च बढ गया है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, सैंट्रल बजट के कारण जिस पर आजकल पार्लियामैंट में बहस हो रही है, अगर वह यों का यों एक्सैप्ट कर लिया जाता है तो मेरा ख्याल है 6 पैसे पर किलो मीटर हमारे ऊपर और बोझ पडेगा। इस हिसाब से फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने किराये में जो बढौ़तरी की है उसके बावजूद भी सात पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से और वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, हमारा पर किलोमीटर खर्चा 184 पैसे से बढकर 192 पेसे हो जाता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट एक ऐसा डिपार्टमैंट है जिसके टोटल रिसोर्सिज हर साल बढते जा रहे हैं। सन 1974–75 में इसके टोटल रिसोर्सिज 12.63 करोड के थे। सन 1977–78 में यह बढकर 19.37 करोड के हो गए। इस हिसाब से इसमें 17 परसैंट की टोटल वृद्धि हुई है। इसमें से हम अभी 10 परसैंट वृद्धि को ही पूरा कर रहे हैं। बाकी 7 परसैंट की वृद्धि को अभी हमने पूरा करना हैं (विघ्न) स्पीकर साहब, हाउस को मैं एक बात और बताना चाहता हूं। हमारी बसों का किराया दस परसैंट और बढने के बाद भी दूसरी स्टेटस के किराये के मुकाबले में आएगा, उनसे ज्यादा नहीं होगा। सात परसैंट के घाटे को हम अपने डिपार्टमैंट को री आर्गेनाइज करके पूरा करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पास 2200 बसिज हैं और 11 डिपोज तथा 19 सब डिपोज हैं। हमारा विचार है कि सब डिपोज को खत्म करके उनकी जगह हम डिपोज ही बढाएं। आपको मालूम है कि सब डिपोज के अंदर इस वक्त हम वर्क भॉप और स्टाफ वगैरा को वे फैसिलिटीज मुहैया नहीं कर पा

रहे हैं जो कि हमें करनी चाहिए। इस वक्त इन सब डिपोज के बारे में विचार चल रहा है और मैं आ ाा करता हूं कि वे जल्दी ही डिपोज बन जाएंगे। हर चार पांच डिपोज के ऊपर सब जगह नहीं कुछ जगह, एक डिविजनल मैनेजर को लगाएंगे जो उनके ऊपर कंट्रोल रखेगा। इसवजह से ऐफि ाएंसी बढेगी। स्पीकर साहब, यह बताना भी उचित होगा कि 30 दिसम्बर 1978 तक हमारे डिपार्टमैंट को 5.78 लाख रुपये का घाटा था लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर तकरीबन 30 लाख रुपये का फायदा इस डिपार्टमैंट को होगा।

स्पीकर साहब, हमारा ज्यादा नुक्सान ओवर स्पीडिंग से हुआ करता था। इसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि अप्रैल 1979 तक हमारी सभी बसों के अंदर ओवर स्पीडिंग को चैक करने वाला एक डिवाइस लगा दिया जाएगा। इससे एक्सपैंडिचर भी कम होगा और ओवर स्पीडिंग की वजह से हमारी जो फ्यूल की कंजम्प ान ज्यादा होती है, वह भी कम हो जाएगी।

स्पीकर साहब, हम अपने डिपार्टमैंट में एक विजिलैंस सैली भी कायम करना चाहते हैं जिसको एक डी0एस0पी0 हैड करेगा। इससे यह फायदा होगा कि जिन केसिज को इस वक्त हमारे इंस्पैक्टर या दूसरे लोग पकडते हैं उनको डी0एस0पी0 पकड कर सीध क्रिमिनल केस बनाएगा जिसकी वजह से हमें यह यकीन होगा कि कोर्ट में उनको सजा मिलेगी। यह नहीं इस सै ान के फौरी बाद हमारे मुख्य मंत्री जी की आज्ञा के अनुसार सभी

मिनिस्टर साहब एक स्पै ाल कैम्पेन इस स्टेट में चलाएंगे। ये लोग बसिज और डिपोज को चैक करेंगे और जो इररैगुलैरेटीज इनको मिलेंगी उनको ये चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाएंगे। (विघ्न) स्पीकर साहब, इस वक्त भी हमारे बहुत से क्रिमिनल केसिज डिफाल्टर्ज के अगेन्सट कचहरियों के अंदर पैंडिंग पडे हैं।

स्पीकर साहब, आपको यह जानकर भी खु ाी होगी कि 512 बसिज एक साल के अंदर नई आई हैं। अगले साल हम 400 नई बसिज लेकर आएंगे जबकि पहले 200 या 250 बसिज एक साल में आया करती थी। आप देखेंगे कि पहले से यह नम्बर डबल है।

बहिन सुशमा जी ने अपने अम्बालर कैंट के बस अड्डे के बारे में कहा था कि उसे वहां से ि ाफ्ट किया जाना चाहिए। इस बारे में अर्ज यह है कि हम उसके लिए सूटेबल जगह तला ा कर रहे हैं।

स्पीकर साहब, चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेलवाला जी ने बोलते हुए यह कहा था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट बस अड्डों की कैंटींज से लाखों रुपया किराए के रूप में चार्ज करता है लेकिन वहां पैसैन्जर्ज को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती। हमने इसकी चैकिंग की है और यह बात ठीक है कि हम उस हद तक पैसैंजर्ज को सही रेट पर अच्छी चीजें नहीं दिला पाए हैं जिस हद तक हमें

दिलानी चाहिए थी। इसके बारे मैं हमारी सरकार ने इस दफा यह फैसला किया है कि नो लौस नो प्रौफिट के ऊपर हम अपनी दुकानें खोलेंगे जिनमें हम अपने पैसैंजर्ज को अच्छी चाय, कौफी और सौफ्ट ड्रिंक आदि मुहैया करेंगे। (विघ्न)

स्पीकर साहब, हमारे डिपार्टमैंट में एक और कमी थी। पहले हम दूसरे डिपोज की बसौं को चैक नहीं किया करते थे लेकिन अब हमने ऐसा करने की इंस्ट्रक ान्ज जारी कर दी हैं।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं हाउस से अनुरोध करूंगा कि यह जो डिमांड नं0 23 है इसको पास कर दिया जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस की इजाजत हो तो मैं हाउस को पन्द्रह मिनअ के लिए एक्सटैंड कर देता हूं।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय पन्द्रह मिनट और बढाया जाता है।

वर्श 1979–80 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला यहां इस समय हाउस में नहीं हैं लेकिन उनके दूसरे साथी हैं। मैं उनकी मेहरबानी के लिए भाुक्रिया अदा करता हूं कि डिमांड नंबर 2 जो जनरल एडमिनिस्ट्रे ान के बारे में है उसके बारे में उन्होंने कोई खास एतराज नहीं किया सिवाए इस बात के कि अफसरों के ट्रांस्फर जल्दी जल्दी कर दिये जाते हैं। बेहतर तो यह होता कि वे हाउस में मौजूद होते और मेरा जवाब सुनते। मैं उनको बताता कि अफसरों के ट्रांस्फर क्यों हुए ? अफसरों के ट्रांस्फर इसलिए हुए कि जिस वक्त मैंने चीफ मिनिस्टर के रूप में जिम्मेवारी संभाली थी उस वक्त उन्हौंने अपने हिसार के मुताबिक अफसरों की फिटिंग कर रखी थी। नये नये जब हम आये तो हमें यह दिक्कत आई कि जो भी ि ाकायत पहुंचे उसमें यही लिखा होता था कि पिछले रिजीम के अफसर अब भी वहीं बैठे हुए हैं। इसलिए भी मुझे ट्रांसफर करने पडे। कुछ कारण यह भी था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ट्रांस्फर करना जरूरी था। लेकिन मैं उन्हें इतना बता दूं कि आइंदा उन्हें इस बात का मौका नहीं मिलेगा कि फील्ड में अफसरों से नाजायज काम करवा सकें क्योंकि वे अब इन्डीपैंडन्टली काम करेंगे और उन्हें ट्रांस्फर नहीं किया जायेगा।

दूसरा एतराज टाप हैवी एडमिनिस्ट्रे ान का किया। मैं मानता हूं कि मिनिस्टरी बढी है, पहले नौ मिनिस्टर होते थे अब 16 हैं। इन मिनिस्टरों के बढने का भी कारण है सन 1967 में राव

बीरेन्द्र सिंह की मिनिस्टरी में श्री सुरजेवाला भी मिनिस्टर हुआ करते थे और सरदार लछमन सिंह जो आज भी मिनिस्टर हैं ये भी मिनिस्टर हुआ करते थे। उस वक्त हरियाणा का सालाना प्लान सिर्फ 34 करोड 41 लाख रुपये का था और उस वक्त विधान सभा के 75 या 80 मैम्बर थे जिनमें 42 रूलिंग पार्टी में हुआ करते थे। 42 रूलिंग पार्टी के मैम्बरों में से 28 मिनिस्टर हुआ करते थे। आज सिर्फ 16 मिनिस्टर हैं लेकिन उनके 28 मिनिस्टर होते थे और प्लान होता था 34 करोड और 41 लाख रुपए का। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जबकि हमारे से पहले साल का प्लान 136 करोड रुपये का था और अब 227 करोड का है यानी तीन साल में ही 91 करोड रुपये ज्यादा कर दिया गया है व सन 1967 से तो 8 गुना है। काम बढा तो मिनिस्टरों की तादाद भी बढ़ी।

स्पीकर साहब, हमारे ऊपर कुदरत की तरफ से भी मुसीबतें आई हैं। पहले साल भी फ्लड आया और पिछले साल भी फिर इन्हीं दिनों जानमार ओले पड़े जिनके लिए हमने लोगों की पूरी मदद की। हमने आज पढे लिखे लोगों की बेकारी को दूर करने के लिए रूरल इंन्डस्ट्रीयेलाइजे ान की स्कीम को चालू किया है। उसकी बाबत मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि डा0 मंगल सैन जी ने काफी कुछ बता दिया है। इस स्कीम के लिए हमने तीन चार कम्पेन चलाये हैं सारा एडमिनिस्ट्रे ान इस कम्पेन में हमारा साथ दे रहा है। हमारे मिनिस्टर, डी0सी0, एस0डी0ओ0 और दूसरे अफसरान बडी तेजी से इस कम्पेन को चला रहे हैं।

हमने डिवैल्पमैंट का काम तेजी से चलाने के लिए 16 मिनिस्टर बनाये हैं। आज हम अफसरों की भी कमी महसूस कर रहे हैं क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ गया है और इसीलिए कुछ अफसर बढाने पडे हैं ताकि डिवैल्पमैंट का काम तेजी से चल सके।

उन्होंने यहां पर फिजूलखर्ची की भी बात की। फिजूलखर्ची में वे हीटर और एयरकंडी ान से आगे नहीं जा सके। हमने तो पहले ही फैसला कर लिया है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा है उस पर हम अमल कर रहे हैं। जिन बडी बडी कोठियों का किराया ज्यादा है उनको छोड कर एम0एल0एज0 फ्लैट और छोटी कोठियों में जा रहे हैं। जिन एम0एल0ए0 फ्लैटों में एम0एल0एज0 बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं या कोई निजी प्रैक्टिस आदि का धन्धा कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा। जिन कोठियों का किराया 800 या 1200 रुपये है और जो पहले से ली हुई हैं, उनको छोडने का इरादा नहीं है। हम बचत की हर चीज को पहले अपने घर से भाुरू करव रहे हैं हम उस कहावत पर नहीं चल रहे हैं कि दीगरान को नसीयत और खुद मियां फसीयत। हम अपने घर से इस पर अमल भाुरू कर रहे हैं हम फिजूलखर्ची कम करके और बतत करके हरियाणा की डिवैल्पमैंट करना चाहते हैं।

उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि आपस में तालमेल नहीं है। उनको इस बात की क्या पडी है कि हमारा तालमेल है या नहीं। हमारा तो तालमेज है परन्तु उनकी निगाहें यहां आने पर

लगी हुई हैं कि ट्रैजरी बैंचिंज पर जल्दी से जल्दी कब आयें। उनको इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम आपस में मिल कर चल रहे हैं। हमारे सामने एक ही नि ाना है कि किस तरह से हरियाणा की डिवैल्पमैंट हो, किस तरह से खु ाहाली आये। इस नि ाने को पूरा करने के लिए तालमेल का होना स्वाभाविक है।

उन्होंने यह भी कह दिया कि बिना सिफारि ा और रि वत दिये कोई काम नहीं होता। उन्होंने रि वत के बारे में कोई मिसाल नहीं दी। हम दावे से यह कह सकते हैं कि कहीं भी रि वत का केस नोटिस में आया है तो हमने फौरन एक ान लिया है। ये कोई सबूत पे ा नहीं कर सके हैं कि वहां पर रि वत चली हैं। मैं यहां हाउस में बार बार दोहराता हूं कि रि वत को खत्म करने के लिए आप हमारा साथ दें। हम अपोजी ान पार्टी का सहयोग चाहते हैं ताकि रि वत जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। रि वत तब चलती है जब रूटीन में काम होना बंद हो जाता है। हमने रूटीन में अच्छा काम चलाने के लिए हैड आफ दि डिपार्टमैंट को और डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्ज पर हिदायतें दी हुई हैं कि एक घंटा रोजाना लोगों के ग्रिविन्सिज सुनें। अगर रूटीन के मुताबिक काम हो जाये तो सिफारि ा करने की और पैसा चढाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर हमारी ग्रिविन्सिज कमेटी बनी हुई है। हम वहां पर ि ाकायतें सुनते हैं। इसको यह असर हुआ है कि पहले जहां हजारों की तादाद में लोग यहां आते थे

अब सिर्फ चालीस पचास लोग ही यहां आते हैं अब वे यहां पर छोटे मोटे काम के लिए आते हैं। जब रूटीन व कायदे के मुताबिक काम भुरू हो जाये तो रि वत आटोमैटिकली बंद हो जाती है।

जहां तक एम0एल0एज0 होस्टल और हरियाणा भवन की कैंटीनों का ताल्लुक है, हम उनको सबसीडाइज करते हैं ताकि लोगों का आराम से और सस्ता खाना मिले और ठीक से इंतजाम हो सके। हम उन्हें सबसीडाइज न करें तो जो 12–13 या 22 रुपये हम अलाउंस देते हैं वह उन लोगों का और बढाना पडेगा। इसलिए हरियाणा भवन की कैंटीन में हम सबसीडाइज करते हैं।

अफसरों की कारों के संबंध में भी कहा गया कि गलत ढंग से इस्तेमाल हो रही हैं। हम योजना बना रहे हैं कि कारों का कम से कम इस्तेमाल हो। हरियाणा की कारें दिल्ली में हैं, वे अगर दिल्ली जाते हैं तो उनसे काम ले सकते हैं। इस बारे में मेरे साथ मेरा साथ देंगे।

यहां पर यह बात भी कही गयी कि एडवाइजर पर एडवाइजर लगाए जा रहे हैं। आखिर स्टेट का काम चलाने के लिए एडवाइजर जरूरी हैं। क्या मैं सुरेन्द्र सिंह और श्री सुरजेवाला को रखूं ? एडवाइजर तो वही रखे जाते हैं जिन पर भरोसा हो। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो पोलिटीकल एडवाइस करते हैं और कुछ साथी ऐसे होते हैं जो पोलिटीकल के साथ एडमिनिस्ट्रे ान

एडवाईस करते हैं। अगर पोलिटीकल एडवाइजर अच्छे तजुर्बे का न हो तो एडमिनिस्ट्रे ान पर असर अच्छा नहीं पडता है इसलिए कम्पीटैंट पोलिटीकल इफैक्ट अच्छा पडें। जो लोग उधर से इधर आना चाहते हैं वे यहां न आ सकेंगे और हम ही यहां पर रहेंगे। स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में और तो कोई ऐसी बात नहीं गई है। जो उन्होंने कही हो और मैंने जवाब नहीं दिया हो। स्पीकर साहब, जनरल एडमिनिस्ट्रे ान इस ढंग से चलना चाहिए कि कम से कम ि ाकायत अपोजी ान को मिले और उसमें कम से कम फिजूलखर्ची हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत मिल सकें। एडमिनिस्ट्रे ान के साथ ही साथ डिवैल्पमैंट का काम भी जारी रहे और जो बेकारी फैली हुई हैं।, उस बेकारी को दूर करने के लिए हमें लोगों की मदद मिल सके। स्पीकर साहब, इस ढंग से एडमिनिस्ट्रे ान चल सकता है।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान अब कट मो ांज और डिमांडज पर वोटिंग होगी। पहले मैं डिमांड नं0 2 पर सर्वश्री भाम ोर सिंह सुरजेवाला तथा सुरेन्द्र सिंह द्वारा दी गई कट मो ान वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है –

कि सामान्य प्र ाासन के बारे में 60714070 रुपए की मांग सं0 2 में 1 रुपए की कटौती की जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब मैं डिमांड नं0 2 पर सर्वश्री इन्द्र जीत सिंह तथा नाराण सिंह द्वारा दी गई कट मो ान वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है –

कि सामान्य प्र ाासन के बारे में 60714070 रुपए की मांग सं0 2 में 1 रुपए की कटौती की जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब मैं डिमांड नं0 2 वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है–

कि 60714070 रुपए से अनधिक धनरा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 2 सामान्य प्र ाासन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः पहले मैं डिमांड नं0 3 पर सर्वश्री भाम ोर सिंह सुरजेवाला तथा सुरेन्द्र सिंह द्वारा दी गई कट मो ान वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है –

कि पुलिस के बारे में 129442100 रुपए की मांग सं0 3 के अधीन मुख्य भाीर्श 255 में 1 रुपए की कटौती की जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब मैं डिमांड नं0 3 पर सर्वश्री इन्द्र जीत सिंह तथा नारायण सिंह द्वारा दी गई कट मो ान वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है –

कि गृह के बारे में 157609960 रुपए की मांग सं0 3 में 1 रुपए की कटौती की जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब मैं डिमांड नं0 3 वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है–

कि 157609960 रुपए से अनधिक धनरा ि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 3 गृह के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः पहले मैं डिमांड नं0 9 पर सर्वश्री भाम ेर सिंह सुरजेवाला तथा सुरेन्द्र सिंह द्वारा दी गई कट मो ान वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है –

कि ि ाक्षा के बारे में 544572990 रुपए की मांग सं0 9 में 1 रुपए की कटौती की जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब मैं डिमांड नं0 9 वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है–

कि 544572990 रुपए से अनधिक धनरा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 9 ि ाक्षा के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः पहले मैं डिमांड नं0 12 पर सर्वश्री भाम ेर सिंह सुरजेवाला तथा सुरेन्द्र सिंह द्वारा दी गई कट मो ान वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है –

कि श्रम तथा रोजगार के बारे में 28970470 रुपए की मांग सं0 12 में 1 रुपए की कटौती की जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब मैं डिमांड नं0 12 वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है–

कि 28970470 रुपए से अनधिक धनरा ि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 12 श्रम तथा रोजगार के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मैं डिमांड नं0 16 वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है–

कि 57313085 रुपए से अनधिक धनरा ि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 16 उद्योग के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मैं डिमांड नं0 23 वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्र न है–

कि 477983020 रुपए से अनधिक धनरा ि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 23 परिवहन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन कल दिनांक 23–3–1979, प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित किया जाता है।

19.38 hours.

(The Sabha then *adjorned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 27th March, 1979).

परिि ाश्ट

Regularisation of work charged employees in P.W.D. (B&R)

***1180. Shri Shamsher Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) the categorywise number of work charged employees in each circle of the P.W.D. (B&R) whose services were regularised in 1974 and prior to that year;

(b) whether it is fact that employees of P.W.D. (B&R) whose services were regularised before 1974 and during 1974 or afterwards are being given different pay scales for the same post;

(c) if so, the names of such categories of employees togetherwith the details of different two sets of pay scales; and

(d) the steps being taken to remove the anomaly in the pay scales for the same post ?

Public Works Minister(Kanwar Ram Pal Singh):

(a) The Requisite information is at Annexure 'A'

(b) No.

(c & d) Question does not arise.

ANNEXURE

Statement showing Circlewise/Categorywise number of Work Charged employees of P.W.D. (B&R Branch) whose services were regularised in 1974 and prior to that

Sr. No.	Name of Category	Ambala Circle	Karnal Circle	Hissar Circle	Bhiwani Circle	Rohtak Circle	N.H. Circle	Gurgaon Circle	Jind Circle	Res. Lab. Hissar	Elece. Circle	Mech Circle	Total
1	Work Mistry	8	6	18	6	6		9	2				55
2	Raod Mate	26	13	31	39	17		50	17				193
3	Mortar Mate	3	7	2									12
4	Beldar	229	104	160	159	88		195	99				1034
5	Chowkidar	5	5	8	8			11	4				41
6	Mate	1	4		1	2			2				10
7	Mason Class-I Do- II	3				4							7 1
8	Driver	23				7							30
9	Sweepers	1			1								2

10	Work Inspesctor			4	2	4		1	2				13
11	Road Inspector			1				2					3
12	Carpenter			1									1
13	Work Munshi			1									1
14	Road Roller Driver				4	3						52	59
15	Jeep/Truck Driver				1							28	29
16	Research Assistant					1				2			3
17	Lab. Boy					1				2			3
18	Receptionist cum-Telephone Operator							4					4